



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 109]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 20, 1995/ज्येष्ठ 30, 1917

No. 109]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 20, 1995/JYAISTHA 30, 1917

कल्याण मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 29 मई, 1995

सं. 4-1/93-कारा.—उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका एल.के. पाण्डेय बनाम भारत संघ (1982 का 1971) में दिनांक 6-2-1984, 27-9-1985 और 3-12-86 को अपने निर्णय में निर्धारित किए गए बच्चों के दत्तक-ग्रहण से संबंधित मानवण्डों, सिद्धान्तों तथा प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए भारत सरकार ने कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या 13-33/85-सी.एच.आई. (ए.सी.) दिनांक 4 जुलाई, 1989 के तहत कुछ मार्ग-निर्देश जारी किए थे।

2. तत्पश्चात उसी मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा 19 सितम्बर, 1989, 14 अगस्त, 1991, 22 अक्तूबर, 1991, 14 नवम्बर, 1991 तथा 20 नवम्बर, 1991 द्वारा कुछ अधिक स्पष्टीकरण संबंधी निर्णय जारी किए गए। इसके अतिरिक्त, 1989 में जारी किए गए मार्गनिर्देशों के कार्यान्वयन में प्राप्त हुए अनुभवों का देखते हुए पहले के जारी किए गए मार्गनिर्देशों को संशोधित करना आवश्यक समझा गया।

तदनुसार, न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) पी.एन. भगवती, भारत के भूतपूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 12 अगस्त, 1992 को एक कृत्यक बल का गठन किया गया जिसमें दत्तक-ग्रहण कार्य से जुड़ी गठन एजेंसियों के विभिन्न वर्गों के प्रति निधियों को शामिल किया गया। इस कृत्यक बल ने अपनी रिपोर्ट 28-8-1993 को प्रस्तुत की।

3. भारत सरकार ने विधि कार्य विभाग के परामर्श से इस कृत्यक बल की रिपोर्ट की जांच की।

4. इस रिपोर्ट की सिफारिशों में से एक सिफारिश कारा के दर्जे में परिवर्तन करके इस कल्याण मंत्रालय के विंग से सोमायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत स्वायत्त निकाय के रूप में पंजीकृत किये जाने के संबंध में है। यह सिफारिश विचाराधीन है तथा इस संबंध में आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

5. कृत्यक बल की कुछ सिफारिशों में भावी दत्तक-ग्राही मानापिता द्वारा स्थापन एजेंसी को देय व्ययों की ऊपरी सीमा में संशोधन परिकल्पित है जिसके लिए उच्चतम न्यायालय की स्वीकृति अपेक्षित होगी। इस पहलू पर भी अलग से विचार किया जा रहा है।

6. उपर्युक्त भदों से संबंधित भिन्नभिन्नों को छोड़कर सरकार ने इस कृत्यक बल की रिपोर्ट को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है।

7. तदनुसार, भारत सरकार ने इस संकल्प के अनुबंध 1 के अनुसार बच्चों के दत्तकग्रहण पर संशोधित दिशानिर्देशों को आम जनता, स्वैच्छिक एजेंसियों तथा विषय के संबंधित सभी के मार्गनिर्देश तथा सूचना के लिए एतद्वारा जारी किया जाता है।

ए.के. चौधरी, संयुक्त सचिव

अध्याय-1

भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण में संबंधित मामलों के विनियम के लिए संबंधित मार्ग-निर्देश

लक्ष्य तथा उद्देश्य

1.1 वर्तमान मार्गनिर्देशों का उद्देश्य एल.के.पाण्डे बनाम भारत संघ तथा अन्य के मामले में 1984 तथा 1991 में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों में निर्धारित मानदण्डों तथा सिद्धांतों के अन्तर्गत दत्तक ग्रहण को ठोस आधार प्रदान करना है।

1.2 दत्तक ग्रहण निःसंदेह एक परिवार में परित्यक्त, निराश्रित या उपेक्षित बच्चे की देखरेख तथा संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है तथा उसके/उसकी प्रतिभाओं और संभावनाओं को चरितार्थ करने के लिए खुशी, प्यार तथा हमदर्दी के वातावरण की सृष्टि करता है। इसमें वह सारी भावात्मक, शारीरिक और भौतिक सुरक्षा विद्यमान रहती है जो बच्चे के उचित विकास के लिए जरूरी है और साथ ही परित्यक्त, निराश्रित तथा उपेक्षित बच्चों के दुरुपयोग, शोषण तथा सामाजिक कुसमंजन से जुड़ी स्थितियों को रोकने का अत्यन्त विश्वमनीय साधन के रूप में कार्य करता है।

1.3 भारत सरकार ने अपने संवैधानिक आदेश के अनुसरण में बच्चों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की है। इस नीति के महत्व का सारांश इस प्रकार है :

“बच्चे राष्ट्र की अत्यधिक महत्वपूर्ण संपत्ति हैं। उनका पालन पोषण और उत्सुकता हमारा दायित्व है। मानव विकास की हमारी राष्ट्रीय योजनाओं में बच्चों के कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया जाना चाहिए ताकि हमारे बच्चे बड़े होकर हृष्टपुष्ट नागरिक, शारीरिक रूप से योग्य, मानसिक रूप से चरुत तथा नैतिक रूप से स्वस्थ हों और वे समाज के लिए आवश्यक कौशलों तथा प्रेरणाओं से युक्त हों। सभी बच्चों को उनके विकास की अवधि के दौरान विकास के लिए समान अवसर देना हमारा उद्देश्य होना चाहिए और

इससे सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने तथा असमानता को कम करने का हमारा बड़ा प्रयोजन पूरा होगा।”

1.4 20 नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बच्चों के दत्तकग्रहण के अधिकारों के घोषणा पत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के कल्याण के बारे में समान रूप से चिन्ता व्यक्त की गई है। तत्पश्चात विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा सेमिनारों में बच्चों के कल्याण के विषय पर लगातार विचारविमर्श चलता रहा है।

1.5 बच्चों के कल्याण की राष्ट्रीय नीति भी उम अत्यावश्यक भूमिका को महत्व देती है जो स्वयंसेवी संगठनों को बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा सामाजिक कल्याण सेवाओं के क्षेत्र में निभानी पड़ती है और इस नीति में घोषणा है कि राज्य का प्रयास ऐसे स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित और मजबूत करना होगा।

बच्चों के विकास के लिए परिवार के आधार की आवश्यकता

1.6 यह एक स्वीकृत तथ्य है कि परिवार में बच्चे का भावात्मक, शारीरिक तथा बौद्धिक संतुलित विकास परिवार के अन्तर्गत सबसे अच्छी तरह सुनिश्चित किया जा सकता है और जहां यह संभव नहीं है, वहां इसे पारिवारिक परिवेश में सुनिश्चित किया जा सकता है। उन बच्चों सहित जो अनाथ, परित्यक्त, उपेक्षित, दुरुपयोग के शिकार हैं, बच्चों को संरक्षण तथा देख-रेख प्रदान करने का दायित्व मुख्य रूप से परिवार, समुदाय तथा समाज का है। तथापि, पारिवारिक संरचना सहित अनेक परम्परागत संस्थाएं चूँकि गृहरीकरण तथा औद्योगिकीकरण तथा विकास की सामान्य प्रक्रिया के कारण नाना प्रकार के सामाजिक परिवर्तनों में गुजर रही हैं। इसलिए, बच्चे को परिवार का आधार हमेशा उपलब्ध नहीं हो पाता है। समुदाय, समाज तथा राज्य का उत्तरदायित्व बन जाता है। इसलिए निराश्रित बच्चों को संस्थागत तथा गैर-संस्थागत दोनों आधार प्रदान करना राज्य का उत्तरदायित्व है। भारत सरकार दत्तक ग्रहण को बच्चों के पुनर्वास के लिए एक सर्वोत्तम गैर-संस्थागत आधार समझती है।

परम्परागत रूप से हमारा समाज धर्मार्थ संस्थानों तथा गैर-संस्थागत कार्यकलापों जैसे दत्तक ग्रहण, अभिभावकत्व तथा फोस्टर देखभाल के माध्यम से आधार प्रदान कर रहा है। सामाजिक संरचना तथा अन्य संबंधित कारकों में तेजी से परिवर्तन होने के कारण उन बच्चों की संख्या में वृद्धि हो रही है जिन्हें देखरेख, संरक्षण तथा पुनर्वास की आवश्यकता है। इसलिए ऐसे बच्चों के पालन पोषण के लिए न केवल संस्थागत तथा गैर-संस्थागत दोनों सुविधाओं का विस्तार करना आवश्यक है बल्कि सभी कार्यक्रमों का विनियमन तथा मानीटर करना भी आवश्यक है ताकि सभी बाल कल्याण कार्यकलापों में न्यूनतम मानक सुनिश्चित हो सकें। गैर-संस्थागत रीतियों में बच्चे का हित परिवार में दत्तक

ग्रहण के माध्यम से सबसे अधिक हो सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि बच्चे का सर्वोत्तम विकास उसके/उसकी स्वयं के सांस्कृतिक तथा सामाजिक वातावरण में होता है। इस प्रकार, दत्तक ग्रहण के माध्यम से बच्चे का स्थापन देशी परिवेश में करना उसके/उसकी उन्नति तथा विकास के लिए आदर्श होगा। अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण अर्थात् विदेश में रहने वाले दत्तकग्राही माता पिता द्वारा भारतीय बच्चों का दत्तक ग्रहण का सहारा केवल तभी लिया जाना चाहिए जब बच्चे को भारत में रहने वाले दत्तक-ग्राही माता पिता के पाम रखने के सभी प्रयास असफल भिद्ध हो गए हों। सामान्य तौर पर दत्तक ग्रहण से संबंधित सभी मामलों में चाहे देश में हो या विदेश में हों, बच्चे का हित तथा कल्याण की सर्वोच्च होगा। इसलिए अप्राधिकृत व्यक्तियों, एजेंसियों या संस्थाओं द्वारा संचालित किए गए परित्यक्त, निराश्रित, त्यागे हुए/अभ्यापित बच्चों के निजी दत्तक ग्रहण को हतोत्साहित किया जाना चाहिए तथा इसे किसी व्यक्तिगत एजेंसी या संस्था चाहे वह सरकार के स्वामित्व में हो या सरकार द्वारा चलाई जा रही हो, के लिए खुला नहीं होना चाहिए अथवा किसी विदेशी से दत्तक ग्रहण के माध्यम से किसी बच्चे को लेने हेतु प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। सरकार का प्रयास भारतीय बच्चे के अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण को सरल बनाने और अन्तरदेशीय दत्तक ग्रहण का विनियमन करने का होना चाहिए।

दत्तक ग्रहण कार्यविधि की समीक्षा

1.7 उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, कल्याण मंत्रालय ने अपने दिनांक 4-7-1989 के संकल्प के तहत दत्तक ग्रहण से संबंधित कार्यक्रमों के विनियमन, मानीटर तथा पर्यवेक्षण के लिए मार्गनिर्देश बनाए हैं जिनमें वर्तमान प्रक्रिया और कार्यविधियां निर्धारित की गई हैं। उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सी आर एम) संख्या 1171/1982 में एल.के.पाण्डेय बनाम भारत संघ तथा दिनांक 19 सितम्बर 1989, 14 अगस्त 1991, 20 अक्टूबर 1991, 14 नवम्बर 1991 तथा 20 नवम्बर 1991 के निर्णयों में अन्तरदेशीय दत्तक ग्रहण के मामले में अनुसरण की गई मौजूदा प्रक्रियाओं तथा कार्यविधियों की पूर्ण रूप से समीक्षा की। कल्याण मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय के सभी निर्णयों तथा देश के कानूनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात तथा संबंधित सरकारी तथा स्वैच्छिक एजेंसियों और बदलती हुई सामाजिक यथार्थताओं के अनुभव को ध्यान रखने के पश्चात इन मार्गनिर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया। इस दशा में कल्याण मंत्रालय में एक कृत्यक बल का गठन श्री न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती (भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश) की अध्यक्षता में किया जिसमें विभिन्न स्वैच्छिक स्थापन एजेंसियों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व दिया गया।

1.8 ये संशोधित मार्गनिर्देश कृत्यक बल की सिफारिशों से उभरे हैं।

अध्याय - 2

भारत सरकार की भूमिका:—

2.1 भारत सरकार से दत्तक ग्रहण से सम्बन्धित सभी मामलों पर विचार कल्याण मंत्रालय में किया जाएगा। केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (कारग) की स्थापना दिनांक 28-6-1990 को कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में दिनांक 9-5-1990 के मन्त्रिमण्डल के निर्णय के अनुसरण में की गई थी तथा केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी की स्थापना इन मार्ग निर्देशों के अन्तर्गत किए जाने के बाद ऐसी केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी यथा विनिर्दिष्ट दत्तक ग्रहण से सम्बन्धित सभी मामलों का निपटान करेगी।

2.2 भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय ससश-समय पर नियम तथा मार्ग निर्देश तैयार करेगी तथा राज्य सरकारों, स्वैच्छिक एजेंसियों तथा स्वैच्छिक समन्वय एजेंसियों और जांच एजेंसियों को देश में दत्तक ग्रहण को आसान बनाने तथा बढ़ावा देने तथा भारतीय बच्चों के अन्तर देशीय दत्तक ग्रहण को विनियमित करने के लिए अनुदेश जारी करेगी।

दत्तक ग्रहण के लिए मान्यता प्राप्त विदेशी एजेंसियों की सूची

2.3 केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध दत्तक ग्रहण के लिए मान्यता प्राप्त विदेशी एजेंसियों की सूची रखेगी। इन एजेंसियों को सूचियों की प्रतियां केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियों द्वारा, भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों, सभी राज्य सरकारों, सभी मान्यता प्राप्त भारतीय एजेंसियों, सभी स्वैच्छिक समन्वय एजेंसियों, सभी जांच एजेंसियों तथा विदेशों में सभी भारतीय मिशनों तथा सभी पारस्परिक कार्यालयों को प्रत्येक वर्ष में एक बार उपलब्ध की जाएगी।

दत्तक ग्रहण के लिए मान्यता प्राप्त भारतीय एजेंसियों की सूची

2.4 केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी दत्तक ग्रहण के लिए मान्यता प्राप्त सभी भारतीय एजेंसियों की एक सूची भी तैयार करेगी। प्रत्येक राज्य कार्यरत इन एजेंसियों की सूची प्रत्येक वर्ष में एक बार राज्य में तीन व्यापक परिचालन वाले प्रमुख समाचार पत्रों में, एक अंग्रेजी भाषा में एक हिन्दी भाषा में तथा तीसरा उन राज्य की क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करेगी। सूची को देश के सभी उच्च न्यायालयों को प्रत्येक राज्य के जिला न्यायालयों में परिचालन के लिए सभी राज्य सरकारों, सभी मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसियों, सभी विदेशी सूचीबद्ध एजेंसियों, सभी भारतीय विदेशी मिशनों, सभी स्वैच्छिक समन्वय एजेंसियों तथा सभी जांच एजेंसियों को भेजा जाएगा।

भारतीय राजनयिक मिशनों से सम्पर्क

2.5 केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी विदेश में भारतीय राजनयिक मिशनों के साथ विदेशी माता-पिता द्वारा दत्तक ग्रहण किए गए भारतीय मूल के बच्चों की उपेक्षा, दुर्व्यवहार, शोषण या दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा करने के लिए सम्पर्क बनाए रखेगी और ऐसे बच्चों के कल्याण और प्रगति पर लगातार निगरानी बनाए रखेगी। इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय संसाधन एजेन्सी प्रत्येक संबंधित भारतीय राजनयिक मिशन को जब कभी भारतीय बच्चों दत्तक ग्रहण द्वारा या दत्तक ग्रहण के प्रयोजन से विदेशी माता-पिता द्वारा लिया जाए तो उसकी सूचना देगी। ऐसे बच्चों तथा उनके दत्तक ग्राही/भावी दत्तकग्राही माता-पिता के नाम, पते तथा अन्य विवरण भारतीय राजनयिक मिशनों को यथा संभव शीघ्र किसी भी मामले में प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से पहले देगी।

दत्तक ग्रहण में शामिल एजेंसियों की बैठक

2.6 केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी प्रत्येक वर्ष सभी मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसियों, स्वैच्छिक समन्वय एजेंसियों तथा जांच निकायों की बैठक आयोजित करेगी जो पारस्परिक हित तथा ऐसे अन्य मामलों पर विचार-विमर्श के लिए जो आवश्यक और उचित समझे जाएं।

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी की भूमिका

2.7 रिट याचिका (सी. आर. एन.) संख्या 1171/82 में भारत के उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार तथा दिनांक 9-5-1990 को मंत्रिमण्डल के निर्णय के आधार पर भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय ने भारत के राजपत्र में संख्या 166 दिनांक 2 जुलाई, 1990 को प्रकाशित दिनांक 28 जून, 1990 के संकल्प संख्या 1-10/88-सी. एच. (ए. सी.) के तहत केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी की स्थापना देश में तथा अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए उपलब्ध बच्चों की सूचना के निकासी गृह के रूप में कार्य करने तथा दत्तक ग्रहण के माध्यम से बच्चों के पुनर्वास के लिए कार्यक्रमों को विनियमित, मानीटर तथा विकसित करने के लिए की है।

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी का मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय

2.8 केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा तथापि, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी की शाखाएं/क्षेत्रीय कार्यालय ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएंगे जोंकि उपयुक्त समझे जाएं।

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी

2.8क. केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी संचालन समिति की सम्पूर्ण नीति निर्देशन के अधीन कार्य करेगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे—

- (1) अध्यक्ष (गैर सरकारी)।

- (2) सचिव (कारा)—सदस्य सचिव-सह-कार्यपालक अधिकारी

- (3) भारतीय बाल कल्याण परिषद् (मूल निकाय) से एक प्रतिनिधि।

- (4) भारतीय समाज कल्याण परिषद् (मूल निकाय) से एक प्रतिनिधि।

- (5) मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसियों के चार प्रतिनिधि, प्रत्येक क्षेत्र में एक जो देश में कम से कम 50% अधिक दत्तक ग्रहण कार्य करते हों।

- (6) स्वैच्छिक समन्वय एजेंसियों से एक प्रतिनिधि।

- (7) विदेश मंत्रालय से एक प्रतिनिधि।

- (8) महिला तथा बाल विकास विभाग से एक प्रतिनिधि।

- (9) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से एक प्रतिनिधि।

मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसियों तथा स्वैच्छिक समन्वय एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का कार्यकाल चक्रानुक्रम आधार पर दो वर्षों की अवधि के लिए होगा। कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात सदस्य आगामी दो वर्षों की उत्तरवर्ती अवधि के लिए पुनः नामांकन के पात्र नहीं होंगे।

अध्यक्ष की नियुक्ति अवैतनिक रूप से होगी। केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी के सदस्य सचिव-सह-कार्यपालक अधिकारी भारत सरकार में उप सचिव-निदेशक के रैंक के अधिकारी होंगे।

2.9 केन्द्र सरकार केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी इतनी धनराशि का भुगतान करेगी जो इस संकल्प के अधीन उसके कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझी जाए।

2.10 केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी के लेखे का रखरखाव तथा उसकी लेखा परीक्षा केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट भारत के नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से किया जाएगा।

2.11. केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी केन्द्र सरकार के अनुमोदन के अधधीन अपने लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के अनुरूप अपने कार्यों के निर्वहन के लिए अपने स्वयं विनियम तथा उपनियम बनाएगी।

2.12 केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी को एक समिति का गठन करने का अधिकार होगा जो देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने से सम्बन्धित मामलों को अनन्य रूप से देखेगी तथा कारा को इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त नीतियों तथा कार्यक्रमों की सलाह देगी।

कारा के कार्य

2.13 केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी (कारा) के कार्य निम्नलिखित होंगे।

1. अन्तरदेशी दत्तक ग्रहण तथा देश में दत्तक ग्रहण के लिए उपलब्ध बच्चों के बारे में सूचना के निकासी गृह के रूप में कार्य करना।

2. उस देश में सरकार द्वारा संचालित अथवा स्वयं संगठन के जरिए अथवा मान्यता प्राप्त सामाजिक अथवा बाल कल्याण एजेंसी के माध्यम से भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिए इच्छुक विदेशियों विदेश में किसी मान्यता प्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण एजेंसी के माध्यम से या उस देश की सरकार के स्वामित्व वाले या संचालित संगठन के माध्यम से दत्तक ग्रहण में भारतीय बच्चों को लेने के इच्छुक विदेशियों के आवेदनों की प्रतियाँ अपेक्षित दस्तावेजों के साथ प्राप्त करना, जैसा कि लक्ष्मीकान्त पाण्डेय बनाम भारत संघ तथा अन्य के मामले में 1171/1982 सी. आर. एल (डब्ल्यू. पी.) में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया है।

3. कारा द्वारा मान्यता प्राप्त समाज या बाल कल्याण एजेंसियों में में एक एजेंसी को अपेक्षित करने के लिए जब कभी केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी द्वारा सीधे आवेदन प्राप्त होते हैं जो विदेशी माता-पिता के आवेदन पर सक्षम न्यायालय में कार्रवाई की जानी होती है।

4. दत्तक ग्रहण के लिए उपलब्ध बच्चों के नाम तथा विवरण प्राप्त करना जो भारतीय सामाजिक या कारा द्वारा मान्यता प्राप्त बाल कल्याण एजेंसियों की देखरेख में है तथा ऐसे बच्चों के नाम और अन्य विवरणों वाला एक रजिस्टर का रख-रखाव करना।

5. सभी भारतीय सामाजिक अथवा कारा द्वारा मान्यता-प्राप्त बाल कल्याण एजेंसियों से कारा द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अन्तर-देशीय के साथ-साथ अंतः देशीय दत्तक ग्रहण के लिए दिए गए बच्चों तथा उनके बाल गृहों में दाखिल बच्चों के बारे में पाक्षिक आंकड़े प्राप्त करना।

6. उनके स्वतंत्र और स्वैच्छिक कार्यकरण के साथ भारतीय सामाजिक या "कारा" द्वारा मान्यताप्राप्त बाल कल्याण एजेंसियों के कार्य को सतत मानीटर तथा विनियमित करना।

7. भारतीय सामाजिक तथा कारा द्वारा मान्यता प्राप्त बाल कल्याण एजेंसियों का निरीक्षण करना तथा ऐसी एजेंसियों के कार्यकरण पर केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट करना।

8. भारतीय सामाजिक तथा कारा द्वारा मान्यता प्राप्त बाल कल्याण एजेंसियों के लेखों का वार्षिक अंकेक्षण विवरणों को मंगाना।

9. सक्षम न्यायालय से उन बच्चों जिनका अभिभावकत्व विदेशी दत्तक ग्रहण करने वाले माता-पिता तथा/या प्रवासी और अनिवासी दोनों भारतीय राष्ट्रियों द्वारा दत्तक ग्रहण किया गया है, के बारे में आंकड़े प्राप्त करना।

10. भारतीय बच्चों को विदेश ले जाने के संबंध में कारा द्वारा निर्धारित प्रपत्र में विदेश में भारतीय राजनयिक दूतावासों को पाक्षिक विवरण भेजना।

11. उस देश में जहाँ ऐसी एजेंसी अवस्थित है भारतीय राजनयिक क्षिपणों के माध्यम से विदेशी देशों में सभी मान्यता-प्राप्त सामाजिक अथवा बाल कल्याण एजेंसियों से कारा द्वारा दत्तक ग्रहण के उद्देश्य में निर्धारित प्रपत्र में विदेशी माता-पिता द्वारा ले जाए गए बच्चों के बारे में पाक्षिक रिपोर्टें प्राप्त करना।

12. विदेशी दत्तकग्राही माता-पिता के साथ-साथ विदेशी देशों के मान्यताप्राप्त सामाजिक या बाल कल्याण एजेंसियों से बच्चों की आवधिक प्रगति रिपोर्टें प्राप्त करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसी रिपोर्टों की जांच तथा इस प्रकार की अनुवर्ती कार्रवाई करना।

13. समान हितों के मामलों पर बच्चों के लिए दत्तक ग्रहण के क्षेत्र में कार्यरत वी.सी.ए. की आवधिक बैठकों का आयोजन और प्रबंध करना।

14. प्रचार और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा सामुदायिक समर्थन के माध्यम से बच्चों को प्रायोजित करने का प्रबंध करना।

15. देश में ही बच्चों के दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहन देने में सामुदायिक विचार तथा सामुदायिक संसाधनों को गतिशील बनाना और सामान्य तौर पर बच्चों के कल्याण के साथ-साथ बच्चों के अन्तः देशीय दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए ऐसे सभी आवश्यक उपाय करना।

16. दत्तक ग्रहण द्वारा विशेष तौर पर बच्चों के पुनर्वास में बाल कल्याण कार्यकलापों में लगे सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा अन्य के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रबंध करना और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा संचालित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का भी मानकीकरण करना।

17. स्थापन एजेंसियों तथा जांच एजेंसियों सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा उन्हें प्रस्तुत सूचना की फ़ास चेक अथवा पुनः मत्यापन करते या बच्चों के दत्तक ग्रहण से संबंधित मामले में निष्पक्ष सलाह देने के लिए न्यायालयों को सहायता करना।

18. देश के भीतर तथा विदेश में बच्चों के दत्तक ग्रहण से संबंधित किसी अन्य कार्यकलाप पर कार्रवाई आरम्भ करना।

अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

2.14 भावधानीपूर्वक विचार करने के बाद भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि जहाँ तक विदेशी द्वारा बच्चों को दत्तक ग्रहण की इच्छा रखने वाले का संबंध है निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जोर दिया जाना चाहिए। बच्चे के दत्तक ग्रहण की इच्छा

बाले विदेशी से प्रत्येक आवेदन उस देश की सरकार विदेशी जिसका निवासी है द्वारा सामाजिक या मान्यता प्राप्त बाल कल्याण एजेंसी या लाइसेंस द्वारा अध्वय ही प्रायोजित होना चाहिए तथा कारा कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध होना चाहिए अंतः देशीय दत्तकग्रहण के क्षेत्र भारत में कार्यरत कोई सामाजिक/बाल कल्याण एजेंसी या बाल अपराध न्यायालय द्वारा किसी संस्था या केन्द्र या गृहजिसके बच्चों की सुनवाई की जा रही हों बच्चे को गोद लेने के लिए किसी विदेशी के आवेदन को सीधे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय द्वारा यथा निर्धारित मूल दस्तावेज के साथ मूल आवेदन को विदेशी सूचीबद्ध एजेंसी द्वारा भारत में मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसी को भेजा जाएगा। विदेशी सूची-बद्ध एजेंसी केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी को नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत नोटोराज्ड, जिसके हस्ताक्षर या तो विदेशी के देश में विदेश मंत्रालय के अधिकारी अथवा न्यायाधीश या समाज कल्याण या उस देश में भारतीय दूतावास, उच्चायोग या कांमुलेट द्वारा विधिवत प्रमाणित गृह अध्ययन रिपोर्ट सहित सभी निर्धारित दस्तावेजों के साथ-साथ प्रत्येक आवेदन की एक-एक प्रति भी संलग्न करेगा। अपेक्षित दस्तावेजों की एक सूची अनुबंध "क" पर है। चूकि गृह अध्ययन रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है इसलिए मोटे तौर पर निम्नलिखित सूचना शामिल होनी चाहिए:

- (क) सामाजिक स्तर तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि,
- (ख) घर का विवरण,
- (ग) घर में जैसा कि प्रतीत होता है, रहन-सहन के स्तर,
- (घ) पति तथा पत्नी के बीच वर्तमान सम्बन्ध,
- (ङ) माता-पिता तथा बच्चों के बीच वर्तमान संबंध (यदि कोई बच्चा हो तो),
- (च) पहले गोद लिए गए बच्चे का विकास (यदि कोई हो तो)
- (छ) दम्पति तथा एक दूसरे के परिवार के सदस्यों के बीच वर्तमान सम्बन्ध,
- (ज) दम्पति का रोजगार स्तर,
- (झ) स्वास्थ्य के व्योरे अर्थात् चिकित्सीय जांच, हृदय स्थिति, पूर्व बीमारी आदि (चिकित्सा प्रमाण पत्र आदि),
- (ञ) दम्पति का आर्थिक स्तर,
- (ट) बच्चे के लिए आवास,
- (ठ) स्कूली सुविधाएं,
- (ड) घर में सुविधा
- (ढ) भारतीय बच्चे को गोद लेने की इच्छा का कारण

(ण) दत्तक ग्रहण के प्रति दादा-दादी तथा संबंधियों की धारणा,

(त) दत्तकग्राही बच्चे के लिए अनुमानित योजनाएं,

(थ) भावी दत्तकग्राही माता-पिता का कानूनी स्तर।

प्रायोजक एजेंसी को मोटे तौर पर उपर्युक्त सूचना के आधार पर व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा सावधानी-पूर्वक गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करवाना चाहिए।

मूल दस्तावेजों के साथ-साथ मूल आवेदन की प्राप्ति से स्थापन अधिकारी मामले को आगे बढ़ाने के लिए हकदार नहीं होगा। वह केवल केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (कारा) कल्याण मंत्रालय से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्राप्त करने के बाद ही आगे बढ़ सकता है।

इसलिए केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (कारा), कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी "अनापत्ति प्रमाणपत्र" के बغير अंतः देशीय दत्तक ग्रहण के लिए मक्षम न्यायालय में कोई मान्यताप्राप्त स्थापन अधिकारी आवेदन पर कार्रवाई नहीं कर सकता। तथापि, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि उनसे प्राप्त आवेदन की प्रमाणित प्रतियां तथा अन्य दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद जहां तक संभव हो उचित समयावधि के भीतर अर्थात् 5 हफ्तों के भीतर प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाना चाहिए। यदि केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (कारा), आवेदन को अस्वीकार करती है तो भारतीय मान्यताप्राप्त स्थापन एजेंसी ऐसी अस्वीकृति के लिए कारणों को विनिर्दिष्ट कर सकती है।

मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी द्वारा सूचीबद्ध विदेशी एजेंसी से मूल आवेदन तथा मूल दस्तावेज प्राप्त होने के बाद संबंधित स्थापना एजेंसी भावी विदेशी माता पिता का नाम उनके लिए निर्धारित रजिस्टर में दर्ज करेगा। मान्यताप्राप्त स्थापन एजेंसी भावी विदेशी माता-पिता के गृह अध्ययन रिपोर्ट की जांच करेगा और गृह अध्ययन रिपोर्ट को बाल अध्ययन रिपोर्ट के साथ मिलान करने का अभ्यास प्रारंभ करेगा। जब वे इस निष्कर्ष पर पहुंचें कि उस खास-परिवार को बच्चे को दिया जा सकता है तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित बच्चे की बी.सी.ए. द्वारा अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के लिए निकासी दे दी गई है। उसके बाद मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसी बाल अध्ययन रिपोर्ट, बच्चे का फोटोग्राफ तथा भावी विदेशी दत्तकग्राही माता-पिता के अनुमोदन के लिए चिकित्सा रिपोर्ट भेजेगी। भावी विदेशी माता-पिता द्वारा बच्चे का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद संबंधित स्थापन एजेंसी बच्चे की निकासी के लिए "कारा" के पास आवेदन करेगी। इस स्तर पर केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसी ने उक्त बच्चे के लिए भारतीय परिवार ढूंढने में पर्याप्त प्रयास किया है और कारा, बी.सी.ए. द्वारा इस आशय की निकासी भी संलग्न है।

मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसी तथा बी.सी.ए. द्वारा प्रस्तुत सूचना को अध्ययन के बाद एजेंसी को तत्काल निकासी प्रदान करेगा। उसके बाद मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसी भावी दत्तक ग्राही विदेशी माता-पिता को बच्चे को अभिभावकत्व प्रदान करने के लिए सक्षम न्यायालय में मामले पर कार्रवाई करेगा। इस स्तर पर जांचकर्ता एजेंसी को सभी दस्तावेजों की जांच करनी होती है और सक्षम न्यायालय को सलाह देनी होती है कि उक्त अंतर देशीय दत्तक ग्रहण बच्चे के सर्वोत्तम न्यायालय द्वारा यथा निर्धारित समय के भीतर विदेशी माता-पिता को बच्चे का अभिभावकत्व प्रदान करेगा। न्यायालय के अभिभावकत्व आदेश के आधार पर मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसी को बच्चे के पक्ष में भारतीय पारपत्र प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय में आवेदन करना होता है। तत्पश्चात् बच्चे के लिए संबंधित देश के संबंधित दूतावास/उच्चायोग द्वारा वीजा जारी किया जाता है। बच्चा देश को छोड़कर भावी दत्तकग्राही माता-पिता के साथ अथवा प्रारक्षी के साथ, जैसा भी मामला हो, भावी दत्तकग्राही माता-पिता अर्थात् बच्चे के भावी निवास के देश को चला जाता है।

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी से “अनापत्ति प्रमाणपत्र” प्राप्त करने की अपेक्षा विकलांग बच्चों, तत्काल चिकित्सा देख-भाल की आवश्यकता वाले बच्चों के मामले में भी लागू होगी जिसे बच्चे के सहोदर भाई-बहनों और 6 वर्ष के अधिक आयु के बच्चों के कल्याण की देख-रेख कर नहीं सामाजिक अथवा बाल कल्याण एजेंसी देश के अन्तर्गत प्रदान नहीं कर सकती। मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसी विदेशी भावी माता-पिता का पता लगाने की प्रतीक्षा किए बिना “अनापत्ति प्रमाणपत्र” जारी करने के लिए एक आवेदन-पत्र ऐसे बच्चे की सूचना के साथ कारा को देगी। कारा सामान्यतया मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी से ऐसे बच्चे की सूचना की प्राप्ति की तारीख से एक मप्ताह के अन्दर विकलांग/विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों आदि के मामले में अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करेगी। साथ ही साथ मान्यता-प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसियों को ऐसे बच्चों के संदर्भ में अपनी पसंद की विदेशी एजेंसियों को भेजने की अनुमति दी जाएगी तथा विदेशी माता-पिता द्वारा बच्चे के लिए स्वीकृति देने के बाद संबंधित स्थापन एजेंसी भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय में यथा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करेगी। इस स्तर पर जांच एजेंसी इस संबंध में विदेशी एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों की जांच, जांच एजेंसी द्वारा सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए और सक्षम न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सलाह देनी चाहिए कि क्या दत्तक ग्रहण में विदेशी को दिया जाना बच्चे के हित में होगा। तथापि, भारतीय मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसी विकलांग बच्चे और तत्काल चिकित्सा देख-भाल की आवश्यकता वाले बच्चे से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने से पूर्व सरकारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा

अधिकारी से एक प्रमाणपत्र इस संबंध में रिकार्ड के लिए प्राप्त करेगी। ऐसे बच्चों के व्योरे मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) की (प्रत्येक) प्रति के साथ, जहां अपेक्षित हो, संबंधित भारतीय स्थापन एजेंसी द्वारा कारा को प्रत्येक माह के अन्त में भेजे जाएंगे।

2.15 जहां किसी देश में कोई मान्यता प्राप्त विदेशी एजेंसी नहीं हो तो उस देश का सरकारी विभाग/मंत्रालय भावी दत्तकग्राही माता-पिता आवेदनों तथा संबंधित दस्तावेजों को कारा को अप्रेषित करेगी। कारा उन कागजपत्रों की जांच करेगी और उन्हें आवेदन में संकेत की गई मान्यता-प्राप्त एजेंसियों अथवा यदि उसमें कोई ऐसा संकेत नहीं हो तो तब मामले पर आगे कार्रवाई करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसियों को भेजेगी। उसके बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जैसा कि पूर्ववर्ती पैरा ग्राफ में बताया गया है।

अन्तर देशीय दत्तक ग्रहण से संबंधित प्रक्रिया संक्षेप में अनुबंध “ख” में देखी जा सकती है।

2.16 मान्यताप्राप्त स्थापन एजेंसियां केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी को उन सूचीबद्ध विदेशी एजेंसियों की एक सूची मुहैया करेगी जिनके साथ वे कार्य कर रही हैं या कार्य करने का प्रस्ताव कर रही हैं। जहाँ तक मान्यता-प्राप्त विदेशी एजेंसी/सरकारी विभाग या एक भारतीय एजेंसी या भारतीय माता-पिता से केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी उपलब्ध सूचना के आधार पर इसे प्रक्रिया के लिए किसी स्थापन एजेंसी को इसे ध्यान में रखते हुए कि विदेशी एजेंसी तथा किसी खास स्थापन एजेंसी के बीच संबंध यदि कोई हो तो, भेजेगा। यदि स्थापन एजेंसी ऐसे मामले को लेने में असफल होती है तो वह तुरंत अनुरोध को स्वीकार न करने के कारणों को बताते हुए केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी को सूचित करेगी। केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी उसके बाद ऐसे मामलों को या तो किसी अन्य मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसी को भेज सकती है या आवेदन को विदेशी स्त्रोत को वापस भी कर सकती है।

2.17 स्थापन एजेंसी प्रत्येक तिमाही के अंत में अंतः देशीय दत्तक ग्रहण के लिए दिए गए बच्चों की संख्या, अंतर देशीय दत्तक ग्रहण के प्रतिक्षित बच्चों की संख्या संबंधी सूचना केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी को अवश्य भेजेगी।

न्यायालय के समक्ष अपेक्षा

2.18 जहाँ बच्चे के दत्तक ग्रहण के उद्देश्य से बच्चे का दत्तक ग्रहण के लिए प्रस्तावित माता-पिता द्वारा या ऐसे माता-पिता की ओर से स्थापन एजेंसी द्वारा अभिभावक के लिए न्यायालय के समक्ष आवेदन करता है तो आवेदन के साथ केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी द्वारा जारी

अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता होगा और यदि बच्चे के दन्तक ग्रहण के लिए आवेदन पर केन्द्रीय दन्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी द्वारा कोई कारण नहीं दिया गया हो तो इन मार्गनिर्देशों में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर आवेदन के साथ स्थापन एजेंसी द्वारा यह बताने हुए एक हलफनामा प्रस्तुत किया जाएगा कि केन्द्रीय दन्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के संबंध में मार्ग-निर्देशों की अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है।

अध्याय-3

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की भूमिका

बाल गृहों की सूची

3.1 राज्य सरकारें (शब्द "राज्य सरकार" में जहां लागू हो, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन शामिल होगा।) स्वयंसेवी/निजी संगठन, जो विभिन्न कानूनों के अंतर्गत पंजीकृत, मान्यता-प्राप्त, या लाइसेंसधारी संगठनों द्वारा निराश्रित, परित्यक्त अनाथ, अपराधी या अपेक्षित बच्चों के अनुरक्षण के लिए चलाए जा रहे हैं, सभी बाल गृहों की एक सूची का रख-रखाव करेगी।

दन्तक ग्रहण एजेंसियों की सूची

3.2 राज्य सरकार बच्चों के अंतःदेशीय तथा अंतर देशीय दन्तक ग्रहण के निमित्त सभी एजेंसियों की एक सूची का अलग से रख-रखाव भी करेगी तथा उन संस्थाओं/एजेंसियों, जिनके पास दन्तक ग्रहण के लिए कानूनी तौर स्वतंत्र बच्चे हैं, की पहचान करेगी।

3.3 राज्य सरकारें इसमें निर्धारित अंतःदेशीय दन्तक ग्रहण के लिए प्रक्रिया के अनुसार भारतीय दन्तक ग्रहण एजेंसियों को मान्यता देगी और इन मार्ग निर्देशों में निहित मानदंडों के अनुसार उचित सत्यापन के बाद अन्तर-देशीय दन्तक ग्रहण के लिए मान्यता प्राप्त की इच्छावाली एजेंसियों के आवेदनों को केन्द्रीय दन्तक ग्रहण संसाधन को अप्रेषित करेगी।

प्रत्येक राज्य सरकार निम्नलिखित कार्य भी करेगी

(1) इसके क्षेत्राधिकार में दन्तक ग्रहण कार्यक्रमों को मानीटर करना तथा स्थापन एजेंसियों तथा बी.सी.ए. और जांच एजेंसियों के कार्यकलापों में समन्वय करना,

(2) देश के भीतर परिवारों में पात्र बच्चों के दन्तक ग्रहण या अभिभावकत्व स्थापन को प्रोत्साहन तथा बढ़ावा देना,

(3) अनाथ तथा अन्य धर्मार्थ गृह (पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1960 का प्रवर्तन और/या बच्चों की देखभाल तथा बाल कल्याण संस्थानों के लिए कुछ न्यूनतम स्तर बनाए रखने के उद्देश्य से उपयुक्त वैकल्पिक नियमावली तैयार करना।

(4) जिन निरीक्षण संगठनों ने केन्द्रीय दन्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी को अन्तर-देशीय दन्तक ग्रहण के लिए मान्यता हेतु आवेदन किया है, तथा यह विचार करने के पश्चात् कि क्या आवेदक एजेंसी यथा निर्धारित सभी अपेक्षाओं को पूरा करती है, आवेदन को केन्द्रीय दन्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी को अपनी टिप्पणियों के साथ भेज देगी और इस प्रक्रिया को 60 दिन की अवधि के अन्तर्गत पूरा कर दिया जाएगा। यदि राज्य सरकार से इस अवधि के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो केन्द्रीय दन्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी तत्काल राज्य में समुचित स्तर पर इस मायले को उठाएगी और यदि आगे की 30 दिन की अवधि के भीतर कोई उत्तर नहीं आता है तो यह मान लिया जाएगा कि राज्य सरकार को मान्यता प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है। यदि राज्य सरकार का यह विचार हो कि आवेदक एजेंसी को मान्यता प्रदान नहीं की जानी चाहिए तो इस विचार को रखने के लिए यह संगत कारणों को देगी और उसे अपनी टिप्पणियों के साथ केन्द्रीय दन्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी को अप्रेषित करेगी।

(5) एक सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

- (क) सचिव, महिला तथा बाल विकास/समाज कल्याण/पंचायत राज —अध्यक्ष
- (ख) निदेशक, कल्याण/समाज, कल्याण/महिला और बाल विकास —सदस्य
- (ग) राज्य के अन्तर्गत स्थापन एजेंसियों, बी.सी.ए. तथा जांच एजेंसियों के दो प्रतिनिधि —सदस्य
- (घ) समाज और बाल कल्याण के क्षेत्र में तीन विशेषज्ञ —सदस्य

समिति बाल कल्याण उपायों, विशेष तौर पर बच्चों के अंतःदेशीय दन्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के तौर तरीकों पर आधिकारिक रूप से विचार-विमर्श करने के लिए बैठकें आयोजित करेगी। राज्य सरकार भी दन्तक ग्रहण के कार्य को समन्वित विनियमित रूप से विकसित करने के लिए समाज कल्याण निदेशालय में एक दन्तक ग्रहण सैल की स्थापना करेगी और दन्तक ग्रहण के बारे में सलाह देने के रूप में हर सहायता प्रदान करेगी। ऐसी समिति का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।

दन्तक ग्रहण एजेंसियों का निरीक्षण

3.4 राज्य सरकार आवधिक रूप से और कम से कम 2 वर्ष में एक बार सभी एजेंसियों तथा संस्थाओं के अंतःदेशीय तथा अन्तर देशीय दन्तक ग्रहण के साथ ही बच्चों की सेवा में संबंधित उनके कारगजातों, कारगजपत्रों तथा कार्यकलापों

का सामान्यतः निम्नलिखित प्रमाणिक ठहराने के लिए निरीक्षण करेगी या करवाएगी :

(1) कि दत्तक ग्रहण को एक वाणिज्यिक कार्यकलाप के रूप में नहीं बल्कि बच्चों के हित में एक कल्याण उपाय के रूप में एक कार्यकलाप के तौर पर किया जा रहा है,

(2) इन ग्रुहों में प्रवेश दिए गए बच्चों के अनुरक्षण के लिए उचित रिकार्डों का रख-रखाव किया जा रहा है,

(3) दाखिल किए गए बच्चों को उनकी देख-भाल के लिए कम से कम आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है,

(4) एक बच्चे को गोद लेने या एक बच्चे को अभि-भावकत्व के अंतर्गत लेने में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की सूचियों का रख-रखाव संगठन द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है,

(5) कि संगठन के लेखे का रख-रखाव किया जा रहा है, तथा उनकी लेखा-परीक्षा वार्षिक रूप से बिना विलंब के की जा रही है और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट यह पुष्टि करती हैं कि लेखा ठीक और सही है और कि कोई संगठन, जो विदेशी निधि प्राप्त करता है, गृह मंत्रालय के साथ पंजीकृत है और उसने विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों का अनुपालन अव्यथा कर लिया है।

(6) कि संगठन दत्तक ग्रहण में दिए गए बच्चों के कल्याण के बारे में नियमित प्रगति रिपोर्टें प्राप्त कर रहा है,

(7) कि एजेंसी/संगठनों द्वारा कार्य में अनुभव रखने वाले स्टाफ को बच्चों की देखभाल करने के लिए काम पर लगाया जाता है तथा ऐसे स्टाफ/कर्मचारियों तक बच्चों की पहुंच आसान है।

कार्य निष्पादन की मानीटरिंग

3.5 राज्य सरकार दत्तक ग्रहण कार्य में लगी सभी एजेंसियों से सभी सूचनाएं और आंकड़े इन एजेंसियों के कार्यकरण की मानीटर करने के लिए प्रत्येक तिमाही में प्राप्त करेगी। इन आंकड़ों को केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी द्वारा निर्धारित किए जाने वाले एक प्रपत्र में मंगाया जाएगा।

3.6 राज्य सरकार ऐसे सभी उपाय करेगी जो बच्चों के अन्तः देशीय दत्तक ग्रहण को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक समझे जाए। बच्चों के पुनर्वास के लिए अनाथालयों में दत्तक ग्रहण द्वारा स्थापन के माध्यम से विशेष देखभाल/प्रयास किए जाएंगे।

1464 GI/95-2

अध्याय--4

दत्तक ग्रहण के लिए मान्यता प्राप्त भारतीय एजेंसियों की भूमिका

प्राधिकरणों के साथ सूचीकरण

4.1 प्रत्येक संस्था और बाल कल्याण एजेंसी को, जो बच्चों की देखभाल तथा अभिरक्षा या दत्तक ग्रहण कार्य या अनाथ, निराश्रित अपेक्षित या परित्यक्त बच्चों से संबंधित कार्य कलाप से जुड़ी हुई है, संबंधित राज्य सरकार द्वारा तत्काल सूचीबद्ध किया जाएगा और ऐसी सूची को काग को अग्रेषित किया जाएगा।

केवल मान्यताप्राप्त एजेंसियां दत्तक-ग्रहण संबंधी कार्य आरंभ कर सकेंगी

4.2(1) कोई एजेंसी अंतः देशीय दत्तक ग्रहण के स्थापन और प्रोत्साहन कार्य में, जब तक उसे राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हो जाती है, अपने को संलग्न नहीं करेगी और स्थापन कार्य में जुड़ी एजेंसी के मामले में इसे एक बाल कल्याण एजेंसी होना चाहिए। कोई भारतीय एजेंसी जो अन्तर-देशीय दत्तक ग्रहण कार्य को आरंभ करने की इच्छुक हो, वह केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी, संबंधित राज्य सरकार तथा केवल उन एजेंसियों से जो केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त हो, मान्यता के लिए आवेदन करेगी और तब अन्तःदेशीय दत्तक ग्रहण कार्य को आरंभ करने की पात्र होगी। ऐसी एजेंसियों को दत्तक ग्रहण के लिए मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसियां कहा जाएगा। उन एजेंसियों को भी, जो स्थापन कार्य नहीं कर रही हैं परन्तु भारतीय दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के कार्य में लगी हुई हैं, को भी कारा द्वारा मान्यता दी जाएगी।

(2) संबंधित राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसियों को छोड़कर कोई एजेंसियां अंतःदेशीय दत्तक ग्रहण कार्य में संलग्न नहीं होंगी। इस प्रयोग के लिए नियम तथा मार्ग-निर्देश राज्य सरकार द्वारा तैयार किए जाएंगे।

बाल कल्याण पर जोर

4.3 केवल वे ही स्वैच्छिक संगठन, जो मुख्य रूप से बाल कल्याण कार्यक्रमों की उन्नति और विकास संबंधी कार्यों से जुड़ी हुई हैं और जो दत्तक-ग्रहण कार्य को अपने समग्र कार्यकलापों के एक अंग के रूप में हाथ में लेती हैं, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी को अन्तर-देशीय दत्तक ग्रहण हेतु मान्यता के लिए आवेदन कर सकती हैं।

भावी दत्तक ग्राही माता-पिता की सूची

4.4 दत्तक ग्रहण में स्थापन कार्य के लिए प्रत्येक समाज बाल कल्याण संगठन सभी भावी दत्तकग्राही माता-पिताओं की एक सूची नियमित रूप से रखेगा जिसमें उनके नाम, पते और आंकड़े तथा अन्य व्योरे होंगे जिसके आधार पर दत्तक ग्रहण में एक बच्चे को लेने के लिए संगठन से अनुरोध किया है।

अन्तः देशीय दत्तक ग्रहण की प्राथमिकता

4.5 जब कोई मान्यता प्राप्त भारतीय एजेंसी किसी बच्चे को प्राप्त करती है जो इसका प्रधान वायित्व जैविक माता-पिता का पता लगाना और बच्चे को उन्हें वापस देना होता है और ऐसा न होने पर जहां तक संभव हो भारतीय परिवारों के साथ दत्तक ग्रहण में देना होता है। यह वांछनीय होगा कि एक भारतीय मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसी दत्तक ग्रहण में भारतीय परिवारों को दिए गए बच्चों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक प्रति वर्ष स्थापित करता चाहिए। तथापि, विकलांग बच्चे, 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे और सहोदर भाई-बहन को इस गणना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। स्थापन एजेंसियों को भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण पर विचार करते हुए निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम का पालन करना अपेक्षित है :

1. भारत में भारतीय परिवार।
2. विदेश में भारतीय परिवार।
3. विदेश में भारतीय मूल के माता-पिता में से कोई एक।
4. पूर्णतया विदेशी।

प्रत्येक मान्यताप्राप्त स्थापन एजेंसी भावी दत्तकग्राही माता-पिता के बच्चे के पूरे व्योरे, जैविक माता-पिता के नाम-पते को छोड़कर जहां एजेंसी को जानकारी हो, देगी। केवल ऐसी स्थिति में यदि जहां बच्चे को देश के अंदर रखने के प्रयास असफल हो जाएं तो बच्चे को अन्तर्-देशीय दत्तक ग्रहण के लिए स्वीकृति दी जाएगी। इस संबंध में बी.सी.ए. से एक निकासी प्रमाणपत्र लिया जाना चाहिए। ऐसा निकासी प्रमाणपत्र बी.सी.ए. द्वारा दिया जाएगा। यदि बी.सी.ए. को आवेदन देने की तारीख से 60 दिनों के अन्दर, बी.सी.ए. ऐसे उपयुक्त भारतीय माता-पिता का पता लगाने में असमर्थ हो जो बच्चे को दत्तक ग्रहण में लेने के इच्छुक हों तो तत्काल केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी बी.सी.ए. को आवेदन देने संबंधी सूचना दी जाएगी। केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी सभी स्वयं सेवी समन्वय एजेंसियों द्वारा जारी किए जाने वाले निकासी प्रमाणपत्र के लिए एक समान प्रपत्र (प्रोफार्मा) तैयार करेगी।

4.6 विदेश स्थित भारतीयों के साथ भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण को अन्तर्देशीय स्थापन माना जाएगा। तथापि, ऐसे किसी भारतीय को उस देश में स्थित किसी सूचीबद्ध विदेशी एजेंसी के माध्यम से अपने आवेदन, कागजात इत्यादि

भजने में वही प्रक्रिया अपनाती होगी जो अन्तः देशीय दत्तक ग्रहण के लिए है।

बढ़ावा देने संबंधी प्रयासों का रिकार्ड

4.7 प्रत्येक मान्यता प्राप्त एजेंसी किसी बच्चे के दत्तक ग्रहण के लिए किसी भारतीय माता पिता को पहचान करने संबंधी स्वयं द्वारा किए गए प्रयासों का काल क्रमानुसार पूर्ण रिकार्ड रखेगी जिसमें किसी भारतीय माता पिता के साथ किसी बच्चे का अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण न हो पाने की स्थिति के कारणों का विशेष उल्लेख होगा।

मामले का पूर्ववृत्त

4.8 प्रत्येक मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग फाइल का रखरखाव करेगी जिसमें उस बच्चे का पूरा जीवन वृत्त होगा।

प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए जाने वाले तिमाही आंकड़े

4.9 प्रत्येक मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी उस राज्य सरकार को तिमाही आंकड़े प्रस्तुत करेगी जिसमें वह एजेंसी कार्यरत हो। साथ ही वह केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी को एक तिमाही विवरण उस प्रोफार्मा में भरकर भेजेगी जो केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी, भारतीयों तथा अन्यो को बच्चों के दत्तक ग्रहण पर दिए जाने के लिए समय समय पर निर्धारित करती है।

बच्चों का अन्तर्ग्रहण

4.10 किसी मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा स्वीकृत सभी बच्चों की प्रविष्टि केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सभी उपलब्ध सूचनाओं के साथ प्रवेश रजिस्टर में की जानी चाहिए।

4.11 किशोर समाज बोर्ड/किशोर न्यायालय के माध्यम से न प्राप्त किए गए किसी परित्यक्त बच्चे के मामले में अथवा जैविक माता पिताओं द्वारा सीधे त्याग की स्थिति में संबंधित एजेंसी को चाहिए कि वह बच्चे के मान्यता प्राप्त एजेंसी के बाल गृह पहुंचने के 24 घंटे के भीतर स्थानीय पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए। एजेंसी के बाल गृह में बच्चे के आगमन की सूचना निकटतम किशोर कल्याण बोर्ड अथवा जहां यह बोर्ड नहीं है वहां किशोर न्यायालय अथवा जिला कलेक्टर को भी 24 घंटे के भीतर दे दी जानी चाहिए।

4.12 मान्यता प्राप्त एजेंसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे की चिकित्सा जांच उसके आगमन के 24 घंटे के भीतर की जाए और जहां कहीं आवश्यक हो, उपयुक्त उपचार किया जाए।

किसी बच्चे का अभ्यर्ण

4.13 किसी बच्चे के अभ्यर्ण के मामले में उसके जैविक माता पिता से राय ली जानी चाहिए और एजेंसी द्वारा

दत्तक ग्रहण के लिए उनकी सहमति एवं बच्चे की देख-भाल और अनुरक्षण के लिए उपलब्ध विकल्पों के बारे में संबंधित लोगों को विधिवत सूचना भेजी जानी चाहिए।

4.14 अभ्यर्पण संबंधी दस्तावेज का कार्यान्वयन जैविक माता पिताओं/माता पिता की स्वतंत्र इच्छा के अनुसार किया जाना चाहिए, एजेंसी की ओर से किसी दबाव, भुगतान अथवा मुआवजे के बदौलत नहीं। यदि जैविक माता पिता बच्चे के धार्मिक रूप से पालन-पोषण को तर्जिह देते हैं तो जहां तक संभव हो सके उनकी इच्छाओं का सम्मान किया जाना चाहिए लेकिन दत्तक ग्रहण किए जाने से पूर्व अमृत बच्चे के हित को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मांगदर्शी सिद्धांत के रूप में माना जाना चाहिए।

4.15 एजेंसी द्वारा-माता/पिताओं/माता-पिता को अभ्यर्पण करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर बच्चे पर पुनः दावा करने संबंधी उसके/उसकी/उनके अधिकार के बारे में सूचना दी जानी चाहिए। उसे/उन्हें यह जानकारी दी जानी चाहिए कि 90 दिनों की अवधि क पश्चात परित्राण बन्धपत्र अपरिवर्तनीय हो जाएगा और तब एजेंसी बच्चे का दत्तक ग्रहण करने अथवा देश के भीतर या विदेश में उसे किसी के अभिभावकत्व के अधीन रखने के लिए स्वतंत्र होगी।

4.16 जहां कहीं संभव हो, अभ्यर्पण संबंधी दस्तावेज स्टाम्प पेपर पर तैयार किया जाना चाहिए। यह कार्य दो जिम्मेदार गवाहों की उपस्थिति में किया जाना चाहिए जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर मान्यता प्राप्त एजेंसी उपस्थित कर पाने में सक्षम हो। समर्पण दस्तावेज की विश्वसनीयता का वायित्व एजेंसी पर होगा।

अभ्यर्पण प्रक्रिया के दौरान मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेंसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि:—

- (1) यदि किसी वैध बच्चे का अभ्यर्पण किया जाता है तो परित्याग संबंधी दस्तावेज पर माता-पिता दोनों के हस्ताक्षर होते हैं और यदि माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है।
- (2) यदि किसी बच्चे का जन्म वैवाहिक स्थिति में हुआ हो तो बच्चे के अभ्यर्पण का अधिकार एक-मात्र रूप से मां को होगा।
- (3) यदि अभ्यर्पण जविक माता-पिताओं/माता-पिता के अतिरिक्त किसी और व्यक्ति से प्रभावित होता हो तो वही प्रक्रिया अपनाई जानी है जो किसी परित्यक्त बच्चे के लिए अपनाई जाती है।

निराश्रित अथवा परित्यक्त बच्चा

4.17 यदि कोई परित्यक्त अथवा निराश्रित बच्चा पाया जाता है तो किशोर कल्याण बोर्ड/किशोर न्यायालय

अथवा समाज कल्याण विभाग अथवा कलेक्टर के माध्यम वाली प्रक्रिया अपनायी होगी। ज्यों ही किसी सामाजिक अथवा बाल कल्याण एजेंसी अथवा किसी नर्सिंग होम अथवा हस्पताल अथवा पुलिस अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई परित्यक्त अथवा निराश्रित बच्चा पाया जाए, स्थानीय पुलिस स्टेशन में बच्चे की एक तस्वीर सहित एक रिपोर्ट तत्काल दर्ज की जानी चाहिए। जलाकनेक्टर को आवश्यक रूप से सूचना दी जानी चाहिए जो निकटतम मान्यता प्राप्त एजेंसी और बी. सी. ए. को शीघ्र सूचित करेगा। पुलिस महानिरीक्षक अथवा पुलिस आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, को चाहिए कि वह इस बात अपने क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले सभी पुलिस थानों को अनुरोध दे कि वे रिपोर्ट किए गए बच्चे के माता-पिता का पता लगाने हेतु शीघ्र पूछताछ शुरू करें और इस प्रकार की पूछताछ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के एक महीने के भीतर अवश्य पूरी कर ली जानी चाहिए। इसी बीच, वह सामाजिक अथवा बाल कल्याण एजेंसी जिसने परित्यक्त अथवा निराश्रित बच्चा प्राप्त किया हो, किशोर कल्याण परिषद को आवेदन कर सकती है और जहां यह कार्यरत न हो वहां किशोर न्यायालय अथवा समाज कल्याण विभाग अथवा कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, को एक निर्मुक्ति आवेदन जिसके तहत यह घोषणा की गई हो कि बच्चा दत्तक ग्रहण के लिए कानूनन स्वतंत्र है आवेदन कर सकती है। चूंकि, पुलिस द्वारा पूछताछ की रिपोर्ट एक महीने की अवधि में पूरी की जानी होती है इसलिए किशोर न्यायालय अथवा कलेक्टर के लिए दो वर्ष और तीन महीने संतोष को आयु के बच्चों, उस आयु से ऊपर के बच्चों के मामले में आवेदन किए जाने की तारीख से लेकर छः सप्ताह की अवधि के भीतर दत्तक ग्रहण को दृष्टि से बच्चे का कानूनन मुक्त घोषित किए जाने संबंधी निर्मुक्ति आवेदन जारी करना संभव हो पाएगा।

जन्म प्रमाण-पत्र

4.18 प्रत्येक बच्चे का आवश्यक रूप से एक जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। किसी ऐसे परित्यक्त अथवा निराश्रित बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिसके जन्म का पंजीकरण उपलब्ध न हो, संबंधित एजेंसी स्थानीय मजिस्ट्रेट को आवश्यक रूप से एक आवेदन करेगा जिसके साथ वैसी अन्य सामग्री भी होगी जो एजेंसी द्वारा, एजेंसी के किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा शपथ लिए जाने में प्रासंगिक समझा जाए। तब स्थानीय मजिस्ट्रेट जन्म प्रमाण-पत्र में शामिल किए जाने वाले व्यौरों का अनुमोदन करते हुए एक आवेदन पारित करेगा और मजिस्ट्रेट के आवेदन के आधार पर उस नगर/शहर/क्षेत्र के स्थानीय जन्म प्रमाण-पत्र निगमन प्राधिकारी द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी किया

जाएगा जिसमें बच्चा पाया गया हो। मैजिस्ट्रेट सामान्यतः मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा मंजूर किए गए प्रमाण-पत्र आधार पर कार्यवाई करेगा। यह प्रक्रिया केवल दत्तक ग्रहण को अंतिम रूप दिए जाने के बाद शुरू की जाएगी ताकि गोद लेने वाले माता-पिता के व्योरे प्रमाण-पत्र में भरे जाने के लिए उपलब्ध हो सकें। उस स्थिति में जबकि बच्चा तीन वर्ष आय पूरी कर चुका हो और दत्तक ग्रहण को अब तक अंतिम रूप नहीं दिया गया हो तो आवश्यकता महसूस होने पर एजेंसी न्यायालय को शपथ-पत्र द्वारा सूचित करने ए जन्म प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकती है :—

- (क) यह कि जहां तक इसकी जानकारी हो बच्चे ने तीन वर्षों की आय प्राप्त कर ली है ;
- (ख) यह कि उसकी/उसके दत्तक ग्रहण को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और इसमें कुछ समय लगने की संभावना है अथवा किसी भी तरह इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता ;
- (भ) यह कि शैक्षणिक/चिकित्सा/कानूनी उद्देश्यों के लिए अथवा किसी अन्य तर्कसंगत उद्देश्य के लिए, जो विनिर्दिष्ट की जाए, एक प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है ; और
- (घ) उस समय तक जबकि बच्चा व्यस्क हो जाए अथवा उसे गोद लिया जाए, जो भी पहले हो, कौन व्यक्ति उसके स्थानीय माता-पिता के रूप में सामने आएंगे (उस व्यक्ति को स्थापन एजेंसी से संबंधित एक जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए)।

ऐसे मामलों में दत्तक ग्रहण के बाद एक अन्य जन्म प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा ताकि बच्चे और गोद लेने वाले माता-पिता के नामों में परिवर्तन की व्यवस्था की जा सके। यह कार्य उस न्यायालय से इस बाबत एक आदेश प्राप्त होने पर किया जाएगा जिसने मूल जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने के आदेश दिए थे।

सूचना

4.19 अभिभावकत्व/दत्तक ग्रहण के लिए उपलब्ध बच्चे के बारे में एक तिमाही विवरण राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी के उपयुक्त प्राधिकारी और संबंधित वी. सी. ए. को प्रत्येक महीने केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया

4.20 किसी भी बच्चे को दत्तक ग्रहण के लिए समर्पित नहीं किया जाना चाहिए :

- (क) परित्यक्त बच्चे के मामले में किशोर कल्याण बोर्ड/किशोर न्यायालय, कलेक्टर अथवा जला मैजिस्ट्रेट अथवा समाज कल्याण विभाग जब तक यह घोषणा

नहीं करता हो कि अमुक बच्चा स्थापन किए जाने हेतु कानूनन मुक्त है।

- (ख) वापस लौटाए गए बच्चे के मामले में तब तक, जब तक कि माता-पिता द्वारा पुनर्विचार किए जाने हेतु तीन महीने की अवधि समाप्त न हो जाए।

- (ग) उस बच्चे के मामले में जो बिना उसके/उसकी सहमति के समझ सकता हो और अभिव्यक्त कर सकता हो।

स्थापन एजेंसियों की भूमिका

4.21 वापस लौटाए गए बच्चे के मामले में, पुनर्विचार की तीन महीने की अवधि के पश्चात स्थापन एजेंसियों को चाहिए कि वे देश में किसी भारतीय माता-पिता के साथ बच्चे को स्थापित करने के लिए 45 दिनों के भीतर मारे प्रयत्न करें। लेकिन किसी निराश्रित अथवा परित्यक्त बच्चे के मामले में स्थापन एजेंसी द्वारा सक्षम प्राधिकारी ने दत्तक ग्रहण के लिए बच्चे को कानूनन मुक्त घोषित किए जाने संबंधी निर्मुक्ति आदेश प्राप्त कर लेने पर उसे चाहिए कि वह निर्मुक्ति आदेश की तारीख से लेकर अधिकतम सात सप्ताह की अवधि के भीतर बच्चे का स्थापन देश के भीतर करने के सारे प्रयास करे। उक्त अवधि के अंतर्गत जैविक माता-पिता के अभिज्ञात होने की स्थिति में पुनर्विचार के लिए एक सप्ताह का समय शामिल है।

4.22 यदि अभिज्ञात स्थापन एजेंसी देश के भीतर उपयुक्त भारतीय परिवार का पता लगाने में समर्थ न हो तो यह स्वैच्छिक समन्वयकर्ता एजेंसी को जहां कहीं यह विद्यमान हो बच्चे के सारे व्योरे प्रस्तुत करेगा। उक्त सूचना के अंतर्गत प्रवेश, चिकित्सा पूर्ववृत्त, कानूनी स्थिति, फोटोग्राफ और देश में परिवारों का पता लगाने हेतु किए गए प्रयासों का व्योरा आवश्यक रूप से शामिल होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर वी सी ए के अधिकारियों को बच्चे तक पहुंचने और उसे देखने की अनुमति दी जाएगी।

4.23 वहां जहां वी सी ए दत्तक ग्रहण के लिए उपलब्ध बच्चों का एक रजिस्टर और भारतीय गोद लेने वाले माता-पिताओं जो किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हों, के लिए एक रजिस्टर का रखरखाव कर रहा हो, वी सी ए उस भारतीय परिवार के साथ शीघ्र ही सम्पर्क स्थापित करेगा जो उसके रजिस्टर में संभावित गोद लेने वाले माता-पिता के रूप में दर्ज हो, साथ ही उन्हें इस बाबत सूचित करेगा कि दत्तक ग्रहण के लिए बच्चा उपलब्ध है। यदि दो महीने की अवधि के भीतर बच्चे को किसी भारतीय परिवार द्वारा गोद नहीं लिया जाता है तो उसे अन्तः देशीय दत्तक ग्रहण के लिए उपलब्ध माना जाना चाहिए। भारत में अन्तर-राज्यीय दत्तक ग्रहण और अन्तर वी सी ए समन्वय की

सम्भावना को भी बच्चे को अन्तःदेशीय दत्तक ग्रहण के लिए समर्पित किए जाने से पूर्व देख लिया जाना चाहिए।

अन्तःदेशीय दत्तक ग्रहण में प्रथम प्राथमिकता विदेश स्थित भारतीयों को दी जानी चाहिए, यदि ऐसा कोई भारतीय परिवार उपलब्ध न हो तो उन गोद लेने वाले जोड़ों को बरीयता दी जाएगी जिनमें कम से कम एक भारतीय मूल का हो। तथापि, भारतीय मूल के माता-पिताओं अथवा जिनमें कम से कम एक भारतीय मूल का हो, के साथ बच्चे को स्थापित किए जाने को अन्तःदेशीय दत्तक ग्रहण के रूप में माना जाएगा।

4.24 जहां बी सी ए विद्यमान न हो अथवा कोई भी भारतीय परिवार अधिकतम दो महीने की अवधि के भीतर बच्चे को गोद लेने के लिए आगे नहीं आता हो तो बच्चे को अन्तःदेशीय दत्तक ग्रहण के लिए उपलब्ध माना जाना चाहिए। तथापि, यदि बच्चा विकलांग हो अथवा सगा भाई या बहन हो अथवा 6 वर्ष से अधिक आयु का हो तो बी सी ए क्लियरेंस प्राप्त करने की विधि अपनाएं जाने की आवश्यकता नहीं है और बच्चे को दो महीने की प्रतीक्षा अवधि के बगैर अन्तःदेशीय दत्तक ग्रहण के लिए उपलब्ध माना जाना चाहिए। अन्य मामलों में भी यदि बच्चा खराब स्वास्थ्य की स्थिति में हो और उसे तत्काल चिकित्सा देखरेख की जरूरत हो और सामाजिक अथवा बाल कल्याण एजेंसी के लिए बच्चे की देख-भाल देश के भीतर करवाना सम्भव न हो तो ऐसी स्थिति में एजेंसी को दो महीने की अवधि की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए बल्कि उसे इस बाबत किसी सरकारी अस्पताल के चिकित्सा विशेषज्ञ से यह प्रमाण-पत्र ले लेना चाहिए कि बच्चे के शीघ्र उपचार की जरूरत है और वह यात्रा कर सकता है। साथ ही उसे बी सी ए स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए और मामले को अन्तःदेशीय दत्तक ग्रहण के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। तथापि वापस किए गए बच्चे के मामले में पुनर्विचार के लिए तीन माह की अवधि का आवश्यक रूप से पालन किया जाना चाहिए।

4.25 किसी बच्चे का अन्तःदेशीय दत्तक ग्रहण के लिए समर्पण किसी मान्यताप्राप्त भारतीय एजेंसी द्वारा बी सी ए से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाव ही किया जाना चाहिए। यह कार्य पैराग्राफ 4.5 और 4.24 में उल्लिखित मामलों को छोड़कर किया जाएगा। जैसा कि पैराग्राफ 4.23 में विनिर्दिष्ट है, यदि बच्चे को गोद लेने के लिए किसी उपयुक्त भारतीय माता-पिता को तलाश कर पाना दो माह की अवधि के भीतर संभव नहीं हो पाया हो तो बी. सी. ए. अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

4.26 दत्तक ग्रहण/अभिभावकत्व की औपचारिकताएं पूरी करने में केन्द्र सरकार/केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी द्वारा निर्धारित सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए।

प्रत्याशित माता-पिताओं की आयु, उनके विवाह, आय, स्वास्थ्य, सम्पत्ति और बच्चों का दस्तावेजी साक्ष्य, प्रति-हस्ताक्षरित बाल अध्ययन रिपोर्ट सहित किसी बच्चे विशेष को स्वीकार करने सम्बन्धी स्वीकृति पत्र, प्रत्याशित माता-पिताओं/एजेंसी की सम्मति सम्बन्धी फोटोग्राफ और मेडिकल रिपोर्ट तथा भारतीय एजेंसी के कार्यकर्ता के नाम से पावर ऑफ एटोर्नी प्राप्त कर लिया जाना चाहिए। एक व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा अथवा उसके पर्यवेक्षण में तैयार किए गए एक होम स्टडी रिपोर्ट को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रत्याशित माता-पिता के तस्वीरों को भी रिकार्ड में रखा जाना चाहिए।

4.27 सामान्य दत्तकग्रहण/अभिभावकत्व का पूरा किया जाना लम्बित रखने हुए भारत में रहने वाले भारतीय माता-पिता के मामले में प्रत्याशित गोद लेने वाले माता-पिता की देख-रेख में रखा जा सकता है।

विकलांग बच्चों का स्थापन

4.28 विकलांग बच्चों के स्थापन को दत्तकग्रहण के कार्य के मूल्यांकन की दृष्टि से एक घनात्मक मुद्दे के रूप में माना जाना चाहिए।

बच्चों का हस्तांतरण

राज्य के भीतर अथवा बाहर किसी गैर-मान्यताप्राप्त एजेंसी द्वारा मान्यताप्राप्त स्थापन एजेंसी (भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त) को हस्तांतरित किए गए सभी बच्चे, इससे पहले कि बच्चे के विदेश में स्थापन के लिए कोई कार्रवाई की जाए, मान्यताप्राप्त एजेंसी के संरक्षण में कम से कम एक महीने तक रखे जाने चाहिए।

4.3 बच्चे का हस्तांतरण, इसके प्रवेश, प्रारंभिक मामले के पूर्ववृत्त संबंधी दस्तावेज तथा यह प्रमाणित करने संबंधी प्रमाण-पत्र के साथ किया जाना चाहिए कि बच्चा दत्तक ग्रहण के लिए कानूनन मुक्त है। साथ ही एक हस्तांतरण पत्र भी होना चाहिए। मान्यताप्राप्त स्थापन एजेंसी को बच्चा स्वीकार करने से पहले सभी तथ्यों की पुष्टि कर लेनी चाहिए। क्योंकि स्थापन के लिए वे कानूनी दृष्टि से उत्तरदायी हैं।

4.31 उन बच्चों जो स्थापन के लिए कानूनी दृष्टि से मुक्त हैं, को गोद लेने वाले माता-पिताओं की तलाश करने संबंधी प्रयास उस बाल कल्याण एजेंसी द्वारा किए जा सकते हैं जिसने बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी गैर मान्यता-प्राप्त एजेंसी अथवा बी.सी.ए. के माध्यम से प्राप्त किया हो।

4.32 बच्चों के अन्तर्राज्यीय हस्तांतरण के मामले में मान्यताप्राप्त भारतीय एजेंसी द्वारा बच्चों का हस्तांतरण अपनी किसी नामित शाखाओं को किया जा सकता है बशर्ते

यह कार्य समाज कल्याण विभाग/मैजिस्ट्रेट/कलेक्टर जैसा भी मामला हो, की लिखित सहमति और अनुमति से किया जाए। निकटतम वी सी ए को भी सूचित किया जाना चाहिए।

अनुवर्ती देखभाल

4.33 देश के भीतर स्थापित बच्चों की देखरेख निम्न प्रकार से की जाएगी—

1. यदि कोई स्थापन पूर्व फोस्टर देखभाल प्रभावित होता है तो फोस्टर देखभाल की नियमित मॉनिटरिंग और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। एक व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता को उस परिवार का नियमित रूप से दौरा करना चाहिए।

2. अनुवर्ती प्रपत्र मान्यता प्राप्त स्थापन एजेन्सी द्वारा पूरा किया जाना चाहिए और प्रत्येक छः महीने पर वी सी ए राज्य सरकार और केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी को भेजा जाना चाहिए।

3. एजेन्सी को यह देखना चाहिए कि कानूनी दत्तक ग्रहण शीघ्र प्रभाव में आ जाए ताकि बच्चे के हितों की सुरक्षा हो सके।

4. कानूनी दत्तक ग्रहण के बाद भी एजेन्सी को चाहिए कि वह तीन वर्षों की अवधि तक उस परिवार के साथ संपर्क बनाए रखे।

5. एजेन्सी द्वारा गोद लेने वाले माता-पिता को दत्तक ग्रहण पश्चात परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए।

रिकार्ड

4.34 प्रत्येक मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेन्सी द्वारा निम्नलिखित रिकार्डों एवं रजिस्ट्रों का रखरखाव किया जाना चाहिए।

1. प्रवेश रजिस्टर

2. निर्धारित फार्म में प्रत्येक बच्चे के बारे में एक पृथक फाईल, जिसमें पूर्ण व्यौरा/पहले की घटनाओं के बारे में जिक्र हो। प्रत्येक दत्तक ग्रहण से सम्बन्धित कानूनी दस्तावेजों/बच्चे की पृष्ठभूमि/उसके विगत समय के भावी संदर्भ के लिए कम से कम 18 वर्षों तक रखरखाव किया जाना चाहिए।

3. प्रत्याशित गोद लेने वाले माता-पिताओं के व्यौरे सहित रजिस्टर

4. बच्चे का आगमन प्रस्थान, अस्पताल में भर्ती उनके माता-पिता को वापसी और उनकी मृत्यु, यदि कोई हो, तो उसे दर्शाने वाला रजिस्टर।

5. कानूनी स्थापन से पूर्व और कानूनी स्थापन के बाद गोद लेने वाले परिवारों के साथ स्थापित बच्चों का अनुवर्ती रजिस्टर।

6. निर्धारित पत्र में तिमाही रिपोर्ट, जैसा कि राज्य सरकार केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी और वी सी ए को भेजा जाता है।

7. निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक व्यौरे और आंकड़ों सहित संगठन की वार्षिक रिपोर्ट, जैसी राज्य सरकार केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी और वी सी ए को भेजी जाती हो।

8. गृह मंत्रालय को प्रस्तुत एफ सी आर ए लेखा खाते की एक प्रति सहित लेखा खातों का लेखा परीक्षित विवरण जैसा कि राज्य सरकार और केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी को भेजा जाता है।

9. सोसायटीज पंजीयन अधिनियम, 1860 अथवा सार्वजनिक न्यायों के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार के कानून के अन्तर्गत निर्धारित अन्य रिकार्ड।

लागतों की वसूली

4.35 संगठन केवल गैर लाभजनक उद्देश्यों को ही अपनाएगा। किसी ही हालत में इसे अन्तः देशीय अथवा अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण से सम्बन्धित किसी कार्यकलाप से कोई अनुचित वित्तीय लाभ नहीं प्राप्त करना चाहिए। तथापि यह प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष लागतों एवं वास्तविक कार्यों के लिए प्रतिपूर्ति अथवा अन्य भुगतान प्राप्त कर सकता है।

4.36 अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए एजेन्सी द्वारा आवश्यक समझे जाने पर वह गोद लेने वाले माता-पिताओं से निम्नलिखित शुल्कों को वसूल कर सकता है—

1. भारतीय माता-पिता/माता-पिताओं द्वारा बच्चा स्वीकार किए जाने की तारीख से लेकर उसके संस्थान से प्रस्थान करने की तारीख तक के लिए समय-समय पर न्यायालयों द्वारा यथानिर्धारित अनुरक्षण लागत।

2. पाकेट लागत, प्रशासनिक लागत तथा बावश्रम्यन तैयार करने संबंधी सेवा शुल्क चिकित्सा और वृद्धिलब्धि (आई.क्यू.) रिपोर्ट कानूनी व्यय तथा वाहन इत्यादि संबंधी लागत जो न्यायालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए।

4.37 भारतीय माता-पिताओं से अनुरक्षण व्ययों को प्रतिपूर्ति स्वरूप किसी एजेन्सी द्वारा भारित अधिकतम धनराशि न्यायालय द्वारा निश्चित की जाएगी।

4.38 अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए विदेशी गोद लेने वाले माता-पिताओं से एजेन्सी द्वारा निम्नलिखित लागतें वसूल की जाएगी।

1. बच्चे की शल्यचिकित्सा अथवा चिकित्सा उपचार संबंधी लागत, विधिवत रूप से अधिप्रमाणित विनों अथवा वाउचरों के प्रस्तुत किए जाने पर।

2. किसी बच्चे को अन्ततः गोद लेने के उद्देश्य से उसके अभिभावक के रूप में नियुक्ति हेतु किसी विदेशी के आवेदन पत्र पर कार्यवाही करने हेतु भारतीय स्थापन एजेन्सी को विदेशी व्यक्ति से आवेदन-पत्र भरने और न्यायालय में प्रस्तुत करने, कानूनी व्ययों प्रशासनिक व्ययों, बाल अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने चिकित्सा और वृद्धि लब्धि रिपोर्ट बनाने पासपोर्ट और बीजा व्ययों तथा बहन व्ययों और न्यायालयों द्वारा अधिकतम 6000/-रु. तक निर्धारित व्ययों की वसूली के लिए पात्र ठहराया जाना चाहिए। इस संबंध में मामलों की अधिकतम वसूली में किसी प्रकार की वृद्धि केवल भारतीय उच्चतम न्यायालय के अनुमोदन से की जा सकती है। जहाँ तक बच्चों के लिए गृह चलने वाली मान्यताप्राप्त स्थापन एजेन्सियों द्वारा बहन किये गये चिकित्सा व्ययों अथवा अनुरक्षण व्ययों का संबंध है वे गोद लेने वाले विदेशी व्यक्ति से ऐसे अनुरक्षण व्ययों द्वारा चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति राशि लेने के हकदार हैं। यह राशि प्रतिदिन प्रति बच्चे 78 रुपये से अधिक न होगी और गोद लेने वाले माता-पिता द्वारा बच्चे के चयन की तारीख से लेकर गोद लेने वाले माता-पिता के अभिभावक नियुक्त किए जाने की तारीख तक के लिए होगी। वसूली योग्य व्ययों की इस बाहरी सीमा की कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तीन वर्षों में एक बार समीक्षा की जाएगी जो जीवन लागत सहित व्ययों में वृद्धि पर निर्भर है।

3. भारत से प्राप्तकर्ता देश तक बच्चे की यात्रा लागत और एक रक्षार्थ साथ जाने वाले व्यक्ति की लागत यदि विदेशी मान्यताप्राप्त एजेन्सी रक्षक प्रदान करने में असमर्थ हो।

4. दत्तक ग्रहण टूटने अथवा असफल होने की स्थिति में बच्चे को भारत वापस भेजने की लागत, यदि भारतीय एजेन्सी की सहमति से विदेशी मान्यता प्राप्त एजेन्सी द्वारा विदेशी व्यक्ति के देश में बच्चे के स्थापन की कोई वैकल्पिक व्यवस्था न हो।

5. यदि केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी को सूचना प्राप्त होती है कि कोई मान्यता प्राप्त भारतीय एजेन्सी निर्धारित शुल्कों से अधिक शुल्क वसूल करती है अथवा विदेशी सूचीबद्ध एजेन्सी का वित्तीय शोषण करने की कोशिश करती है तो केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी उस एजेन्सी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर देते हुए उसकी मान्यता निलम्बित अथवा रद्द कर सकती है। इसी प्रकार यदि कोई विदेशी सूचीबद्ध एजेन्सी किसी भारतीय बच्चे के अन्तः देशीय दत्तकग्रहण के मामले पर कार्यवाही करने के लिए प्रलोभन देती है अथवा अधिक धन देती है तो केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी उक्त एजेन्सी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका देते हुए विदेशी एजेन्सी की सूची से निष्कासित कर सकती है।

अध्याय — 5

दत्तकग्रहण के लिए भारतीय एजेन्सियों को मान्यता

आवेदन के लिए प्रपत्र

5.1 कोई भी भारतीय समाज/बाल कल्याण एजेन्सी जो अन्तर्देशीय दत्तकग्रहण का काम शुरू करने के लिए भारत सरकार से मान्यता प्राप्त करने की इच्छुक हों, वह उम्र राज्य के समाज कल्याण/महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से जहाँ वह एजेन्सी स्थित है, कारा को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करेगी।

मान्यता रहित एजेन्सियों पर रोक

5.2 कोई भी एजेन्सी जिसके पास कारा का प्रमाण-पत्र नहीं होगा, विदेशी माता-पिताओं को दत्तकग्रहण के लिए कोई बच्चा नहीं देगी और न ही संरक्षण और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अंतर्गत किसी विदेशी को एक भारतीय बच्चे के माता-पिता के रूप में घोषित करने के लिए किसी भारतीय न्यायालय में आवेदन कर सकती है।

विशिष्ट अवधि के लिए मान्यता

5.3 इस दिशानिर्देश में दी गई शर्तों के अनुसार, किसी भारतीय एजेन्सी को आरम्भ में तीन वर्ष की अवधि के लिए ही मान्यता प्रदान की जाएगी।

मान्यता की शर्तें

5.4 कोई भी भारतीय एजेन्सी जो मान्यता प्राप्त करना चाहती है, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगी:

- (क) इसे सोमायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक सोमायटी के रूप में रजिस्टर्ड या धर्मार्थ न्याय अधिनियम के अंतर्गत सृजित एक न्याय अथवा किसी उचित कानून के अंतर्गत एक रजिस्टर्ड संगठन या एक ऐसा संगठन होना होगा जिसने पिछले पांच वर्षों के दौरान बच्चों के कल्याण के लिए कार्य किया हो।
- (ख) संगठन को राज्य सरकार द्वारा महिला एवं बाल संस्थान (लाइसेंस) अधिनियम, 1956 या अनाथालय अथवा धर्मार्थ संस्थान (पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत लाइसेंसित होना होगा।
- (ग) इसकी एक बाकायदा निर्भिन कार्यकारिणी समिति होनी चाहिए, संगठन के मुख्य कार्यपालक के साथ-साथ बोर्ड/कार्यकारिणी के अधिकांश सदस्यों को भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- (घ) उसके पास शिशुओं सहित बच्चों की सुरक्षा तथा पालन पोषण के लिए समुचित बाल गृह होना चाहिए।

- (क) वान अथवा सरकारी अनुदानों से धनराशि एकत्र करने में समर्थ होना चाहिए ।
- (ख) उसे गैर-वाणिज्यिक लाभ न कमाने वाला होना चाहिए ।
- (ग) दत्तकग्रहण का काम करने के लिए उसके स्टाफ में कम से कम एक योग्य सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए ।
- (घ) संगठन के मुख्य कार्यपालक को भारत के उच्चतम न्यायालय तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों और कारा द्वारा बनाए गए विनियमों, यदि कोई हों, का पालन करने के लिए एक लिखित शपथ पर हस्ताक्षर करने को तैयार होना होगा ।
- (ङ) एजेन्सी को मान्यता देने के लिए संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश होनी चाहिए अथवा, यदि इस प्रकार की सिफारिश नहीं की जाती है, तो इन्कार करने का कारण दिया होना चाहिए । कारा इन्कार के कारणों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है । कारा का निर्णय अंतिम होगा ।

मान्यता का नवीकरण

5.5 मूल आवेदन राज्य सरकार के उचित प्राधिकारी को और साथ ही साथ उसकी एक प्रति सीधे कारा को भेजी जानी चाहिए । राज्य सरकार मूल आवेदन को अपने विचारों सहित आवेदन प्राप्ति के दो मास के भीतर कारा को भेजेगी । यदि राज्य सरकार आवेदन प्राप्ति के दो मास के भीतर अपने विचारों सहित आवेदन को कारा को नहीं भेजती तो कारा द्वारा यह माना जाएगा कि राज्य सरकार सहमत है और उस आवेदन पर मान्यता प्रदान करने के लिए अधिकतम आगामी दो मास की अवधि में ही कार्रवाई कर दी जाएगी । यदि ऐसे और दो मास की अवधि के भीतर कारा से आवेदन पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता, या एजेन्सी की मान्यता समाप्त होने से पहले, जो भी बाद में हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण प्रदान किया हुआ माना जाएगा । यह मान्यता प्रायः एक समय पर निम्नलिखित शर्तों के अध्वयधीन तीन वर्षों की अवधि के लिए नवीकरण की जाएगी :—

- (1) देश के भीतर दत्तकग्रहण में संतोषजनक कार्य निष्पादन हो । लाईसेंस प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन एजेन्सियों को भारतीय दत्तकग्रहण के क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी प्रदर्शित करनी चाहिए । इसलिए, प्रत्येक मान्यताप्राप्त स्थापन एजेन्सी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे मान्यता के पहले वर्ष में इसके द्वारा दत्तकग्रहण/अभिभावकत्व हेतु कुल नियोजन में से कम-से-कम 25 प्रतिशत बच्चों का स्थापन भारतीय परिवारों

में हो । देश के भीतर दत्तकग्रहण/अभिभावकत्व का यह स्तर मान्यता के तीसरे वर्ष में बढ़कर 50 प्रतिशत तक हो जाएगा । यह मान्यता वहां निलम्बित/समाप्त की जा सकती है जहां कोई मान्यता प्राप्त एजेन्सी उक्त आंकड़ों के अनुसार देश के भीतर दत्तकग्रहण का प्रबन्ध करने में असफल रहती है । तथापि, स्थापन एजेन्सी को ऐसे निलम्बन समाप्ति के लिए कारण बताने का अवसर दिया जाएगा और ऐसे निलम्बन/समाप्ति के लिए कारण देते हुए एक लिखित आदेश दिया जाएगा ।

- (2) रिपोर्टों और रिटर्न की नियमित प्रस्तुति ।
- (3) स्थापन एजेन्सी के विरुद्ध प्रमाणित दुरुपयोग का कोई मामला न हो ।
- (4) सम्बद्ध राज्य सरकार की सिफारिश बगैर कि सिफारिश की इन्कारी किसी अपमानित, अमम्बद्ध या मानने योग्य कारणों पर आधारित न हो ।

एजेन्सियों द्वारा लेखों का रखरखाव

4.7 (1) प्रत्येक एजेन्सी लेखों का उचित रूप से रखरखाव करेगी और जो प्रति वर्ष किसी सनदी लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा किए जाएंगे ।

- (2) प्रत्येक एजेन्सी, सनदी लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा की तारीख से लेखा परीक्षित लेखों की एक फांटी प्रति और आडिट रिपोर्ट सहित संबंधित राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग और कारा को भेजेगी ।
- (3) एजेन्सी द्वारा गृह मंत्रालय को प्रस्तुत की गई एफ.सी.आर.ए. की एक फांटी प्रति, लेखा परीक्षित लेखों सहित कारा को प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

आवेदन पर कार्रवाई केवल मान्यता प्राप्त एजेन्सियों द्वारा ही की जानी है ।

5.8 किसी विदेशी को या किसी भारतीय को अन्य देश में दत्तकग्रहण के लिए किसी भारतीय बच्चे को अभिभावक घोषित करने के लिए आवेदन पर कार्रवाई इन दिशानिर्देशों में दी गई प्रक्रिया के अनुपालन के बाद केवल किसी मान्यता प्राप्त भारतीय एजेन्सी द्वारा ही कार्रवाई की जाएगी ।

सूचीबद्ध विदेशी एजेन्सियों द्वारा आवेदन प्रायोजित करना

5.9 कोई भी मान्यता प्राप्त भारतीय एजेन्सी किसी भावी विदेशी माता-पिता का आवेदन किसी भारतीय बच्चे का अभिभावकत्व प्रदान करने के लिए आवेदन कर सकती है बशर्ते ऐसे विदेशी का आवेदन भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध किसी विदेशी स्वैच्छिक एजेन्सी द्वारा अग्रप्रेषित किया गया हो और ये आवेदन इन दिशानिर्देशों के अनुरूप हों । तथापि, यदि कोई एजेन्सी किसी देश में स्वयं चलाई जाती है तो विदेशी

भावी माता-पिता विदेशी सरकार की ऐसी एजेंसी के माध्यम से भारत में किसी मान्यता प्राप्त भारतीय एजेंसी से सम्पर्क कर सकते हैं।

विदेश में सूचीबद्ध एजेंसियों के साथ काम करने के लिए मान्यता प्राप्त भारतीय एजेंसियां

5.10 कोई भी मान्यता प्राप्त भारतीय एजेंसी किसी भारतीय बच्चे के दत्तकग्रहण के लिए किसी विदेशी या सौचीबद्ध विदेशी एजेंसी से सीधे ही आवेदन प्राप्त नहीं करेगी। जब तक आवेदन सहित निर्धारित दस्तावेज को कारा की मंजूरी नहीं मिल जाती।

एजेंसियों का निरीक्षण

5.11 भारतीय मान्यता प्राप्त एजेंसियों के बाल गृहों सहित उनके परिमर और उनके रिकार्ड कारा के अधिकारियों के निरीक्षण के लिए किसी भी समय उपलब्ध होंगे।

अध्याय 6

दत्तक ग्रहण के लिए सूचीबद्ध विदेशी एजेंसियों की भूमिका
विदेशी एजेंसियों को भारतीय राजनयिक दूतावासों को आवेदन करना है।

1.1 कोई विदेशी समाज/बाल कल्याण एजेंसी, जो किसी भारतीय बच्चे के दत्तकग्रहण हेतु भावी विदेशी माता-पिता के आवेदन प्रायोजित करने के इच्छुक हों, कारा के साथ सूचीबद्ध होने के लिए उस देश में भारतीय राजनयिक मिशन में आवेदन करेगा और कारा द्वारा इस प्रयोजन हेतु सूचीबद्ध केवल वही विदेशी एजेंसियां ही ऐसे कार्यक्रमों शुरू करेंगी।

विदेशी एजेंसियों को सूचीबद्ध करने के लिए मानदण्ड

6.2 अन्तर्देशीय दत्तकग्रहण के प्रयोजन से कारा द्वारा विदेशी एजेंसियों को सूचीबद्ध करने के लिए मानदण्ड इस प्रकार है:—

(1) यह उस देश की सरकार का भाग होगा या सम्बद्ध देश के उपयुक्त कानून के अंतर्गत बाकायदा एक रजिस्टर्ड स्वैच्छिक एजेंसी हो तथा उस देश के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

(2) यह एक बाल कल्याण एजेंसी हो जो इस क्षेत्र में सुप्रतिष्ठित हो और उसके पास दत्तकग्रहण के क्षेत्र में काम करने के अनुबन्ध वाला योग्य स्टाफ होना चाहिए।

(3) यह एजेंसी वास्तव में गैर-वाणिज्यिक और लाभ न कमाने के आधार पर चलाई जाएगी। विदेशी एजेंसी को उनके भारत में काम करने के लिए लेखों का लेखा परीक्षित विवरण और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता चाहिए।

(4) सूचीबद्ध विदेशी एजेंसी द्वारा यह लिखित वचन दिया जाएगा कि दत्तकग्रहण करने से पहले विदेशी परिवार के विखण्डन के मामले में या दत्तकग्राही परिवार में यदि बच्चे की उचित देखभाल नहीं की जाती है या दुर्व्यवहार अथवा दुरुपयोग किया जाता है, तो यह भारतीय राजनयिक मिशन, केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी, कल्याण मंत्रालय तथा सम्बद्ध भारतीय मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसी को सूचित करते हुए बच्चे की देखभाल करेगी तथा उस मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसी की सहमति से जिसने मामले पर कार्रवाई की है, की सहमति से समुचित वैकल्पिक स्थापन प्रयत्न करेगी और ऐसे स्थापन की रिपोर्ट उस भारतीय न्यायालय को देगी जिसने अभिभावकत्व के लिए आदेश दिया था और कारा को भी इसकी सूचना देगी।

(5) संगठन का प्रमुख/मुख्य कार्यपालक को कारा द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के पालन करने और सूचीबद्ध विदेशी एजेंसियों द्वारा अनुपालन करने के लिए एक लिखित वचन पर हस्ताक्षर करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। सूचीबद्ध विदेशी एजेंसियों को उन भारतीय एजेंसियों की एक सूची कारा को भेजनी चाहिए जिनसे उनके सम्पर्क और कार्य संबंध है और जिनके साथ वे कार्य संबंध रखने को तैयार हैं।

सूचीबद्धता के लिए प्रक्रिया

6.3 (1) कोई विदेशी समाज/बाल कल्याण एजेंसी जो भारतीय बच्चे के दत्तकग्रहण हेतु विदेशी दत्तकग्राही माता-पिता के आवेदनों को प्रायोजित करने की इच्छुक हों, भारतीय दूतावास मिशन के कार्यालय और उस देश की सरकार जहां ये स्थित है, के माध्यम से सूचीबद्धता के लिए आवेदन करेगी।

(2) सम्बद्ध देश में भारत के राजनयिक मिशन की सिफारिश पर, कारा उस आवेदन की जांच करेगी, मान्यता के लिए सम्बद्ध एजेंसी पर विचार करेगी बशर्ते कि यह उपर्युक्त पैराग्राफ 6.2 में दिए गए मानदण्डों को पूरा करती है।

सूचीबद्धता का नवीकरण

6.4 (1) अन्तर-देशीय दत्तकग्रहण में कार्यरत किसी विदेशी एजेंसी को कारा द्वारा आरम्भ में पांच वर्षों की अवधि के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। यह सूचीबद्धता एक समय में संतोषजनक कार्य निष्पादन और इन दिशा-निर्देशों में दी गई शर्तों की शर्त पर पांच वर्षों के लिए नवीकरण होगा।

(2) कारा, सूचीबद्धता का नवीकरण प्रदान करते समय निम्नलिखित घटकों पर विचार करेगी बशर्ते नवीकरण के लिए आवेदन उचित माध्यम से तथा पिछली मान्यता समाप्त होने से छह मास पहले दिया जाए।

- (क) क्या एजेंसी उस देश के उचित प्राधिकारी द्वारा अभी भी मान्यता प्राप्त है जहां वह अवस्थित है,
- (ख) क्या ये एजेंसी बच्चों के दत्तकग्रहण के संबंध में प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करने में नियमित रही है ?
- (ग) क्या एजेंसी का सामान्य कार्य निष्पादन संतोषजनक रहा है और क्या उनके द्वारा स्थापन के लिए दिए गए बच्चे संतोषजनक प्रगति कर रहे हैं ?
- (घ) क्या भारत सरकार के उस देश में राजनयिक मिशन ने नवीकरण के मामले की सिफारिश की है ?

तथापि, कारा के विवेकाधिकार पर वैध या कानूनी कारणों से सूचीबद्धता के नवीकरण से इनकार किया जा सकता है परन्तु कारा ऐसे कारण बताने के लिए बाध्य नहीं होगा।

असूचीबद्ध करना

6.5 केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार किसी भी विदेशी एजेंसी को वैध अथवा विधिक कारणों से असूचीबद्ध कर सकती है और कारा उसे बताने के लिए बाध्य नहीं होगी। तथापि, यदि असूचीबद्धता के समय कोई मामला हाथ में होगा तो उसे पूरा करने दिया जाएगा।

6.6 जब न्यायालय दत्तकग्राही माता-पिता को बच्चे के अभिभावकत्व नियुक्त करने का आदेश देता है तो इस आदेश में दत्तकग्राही माता-पिता की एक बचनबद्धता होगी कि वे बच्चे की सुरक्षा और हितों की सुरक्षा करेंगे और बच्चे की कानूनी रूप से प्राप्त करने की अवस्था में आदेश की तारीख से दो वर्षों से पहले ही दत्तकग्रहण कर लिया जाएगा और ऐसे बच्चे के दत्तकग्रहण पर, देश के कानूनों के अनुसार यह बच्चा एक प्राकृतिक रूप से जन्म बच्चे के सभी अधिकार प्राप्त करेगा।

विदेश ले गए बच्चे के अधिकार

6.7 अपने देश के कानूनों के अनुसार विदेशी माता-पिता द्वारा बच्चे के दत्तकग्रहण पर, यह समझा जाता है कि उस देश के कानूनों की शर्त पर, वह बच्चा प्राकृतिक रूप से विवाह के बाद जन्मे बच्चे के रूप में वही स्थिति, अनुवंशिकी और उत्तराधिकार के वही अधिकार तथा वही राष्ट्रीयता प्राप्त करेगा जो उसके विदेशी माता-पिता की है।

6.8 जहां भारत में न्यायालय के आदेश की तारीख के दो वर्ष के भीतर परिवार के विघटन या बच्चे के व्यवहार के कारण दत्तकग्राही माता-पिता के समायोजित नहीं होने के कारण या अन्यथा, दत्तकग्राही माता-पिता द्वारा बच्चे का कानूनी रूप से दत्तकग्रहण नहीं किया जाता। यह विदेशी

एजेंसी जिसने बच्चे के दत्तकग्रहण के मामले पर कार्रवाई की थी, को तत्काल दत्तकग्राही माता-पिता से बच्चे को वापस लेना चाहिए और अपनी देखभाल व कब्जे में रख कर यथासम्भव बच्चे के दत्तकग्रहण में स्थापन हेतु नए दत्तकग्राही माता-पिता को ढूंढना चाहिए। वह विदेशी एजेंसी इस संबंध में भारत में न्यायालय को लिखित सूचना देगी।

6.9 सभी सूचीबद्ध विदेशी एजेंसियां कारा को प्रतिवर्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति भेजेंगी।

6.10 ये विदेशी एजेंसियां, इनके द्वारा नियोजित प्रत्येक बच्चे के सम्बन्ध में; विदेशों में भारत के राजनयिक दूतावासों के माध्यम से बच्चे की फोटोग्राफ सहित पहले दो वर्षों में तिमाही आधार पर और अगले तीन वर्षों में अर्द्ध-वार्षिक आधार पर कारा को तथा भारत के उस न्यायालय को जिसने अभिभावकत्व प्रदान किया था तथा सम्बद्ध भारतीय स्थापन एजेंसी को रिपोर्ट भेजेंगी। ये विदेशी सूचीबद्ध एजेंसियां कारा को प्रति वर्ष उसके दत्तकग्राही माता-पिता सहित बच्चे का एक फोटो संग्रह (एलबम) भेजेंगी।

6.11 ये विदेशी सूचीबद्ध एजेंसी जैसे ही उस देश के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा कानूनी दत्तकग्रहण आदेश जारी होता है, उसकी एक प्रति केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी तथा उस न्यायालय को जिसने अभिभावकत्व प्रदान किया था और सम्बद्ध भारतीय एजेंसी को भेजेंगी।

6.12 दत्तकग्रहण को कानूनी रूप देने के बाद भी सूचीबद्ध विदेशी एजेंसी को दत्तकग्राही परिवार के साथ दत्तकग्राही परिवार की गोपनीयता की आवश्यकता बनाए रखने में ससर्क रखेगी और यदि आवश्यक हो, समर्थन व परामर्श सेवाएं प्रदान करेगी तथा ऐसे समय तक जब वह बच्चा नहीं हो जाता/जाती हैं बच्चों के हित की सुरक्षा करेगी।

6.13 सूचीबद्ध विदेशी एजेंसी को अपने देश में भारतीय मूल के दत्तकग्रहण किए गए बच्चों और उनके दत्तकग्राही परिवारों का भारत की संस्कृति दिखाने के लिए इकट्ठा करने के प्रबंध में सहायता करनी चाहिए। ये एकत्रीकरण 15 अगस्त, 14 नवम्बर, 26 जनवरी यादि जैसे राष्ट्रीय अवसरों के समय पर आयोजित किए जाएंगे। कारा भी कुछ अवसरों पर इन समूहों में दत्तकग्रहण किए गए बच्चे की प्रगति पर फीड-बैक जानने के लिए भाग ले सकती है।

6.14 सूचीबद्ध विदेशी एजेंसियां अन्तर-देशीय दत्तकग्रहण के संबंध में किसी प्रकार के कार्यक्रमों के लिए भारत में अपने प्रतिनिधियों को नहीं लगा सकती है।

अध्याय 7

स्वैच्छिक समन्वय एजेंसियां

7.1 किसी राज्य में या किसी बड़े नगर में जहां अनेक मान्यताप्राप्त स्थापना और बाल कल्याण एजेंसियां हैं, वहां एक केन्द्रीयकृत एजेंसी अर्थात् स्वैच्छिक समन्वय एजेंसी होगी। इस एजेंसी के मुख्य कार्य इस प्रकार होंगे :—

- (क) यह भारतीय दत्तकग्रहण को बढ़ावा देने और इस संबंध में कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों को विकसित तथा कार्यान्वित करने एवं चेतना सृजन करने में सक्रिय रहेगी।
- (ख) यह सुनिश्चित करेगी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा देश में या विदेश में भारतीय द्वारा दत्तकग्रहण/स्थापना पर दी गई प्राथमिकता का पालन हो। देश में सभी मान्यताप्राप्त समाज/बाल कल्याण एजेंसियां किशोर कल्याण बोर्ड और सरकारी गृह, जो बच्चों के दत्तकग्रहण/स्थापना के कार्य में इच्छुक हों, वे कानूनी रूप से मुक्त बच्चों के दत्तकग्रहण की एक सूची सम्बद्ध वी. सी. ए. के साथ-साथ कारा को देंगे।
- (ग) यह सभी भावी दत्तकग्राही माता-पिताओं का एक रजिस्टर रखेगी।
- (घ) यह उन सभी बच्चों का जो दत्तकग्रहण के लिए कानूनी रूप से मुक्त हैं, का एक रजिस्टर रखेगी।
- (ङ) यह भारतीय दत्तकग्रहण के क्षेत्र में अपनी सभी सदस्य एजेंसियों तथा अन्य बाल कल्याण संस्थाओं के काम को समन्वित करेगी। जहां भारतीय दत्तकग्रहण इसके कार्यक्षेत्र में कठिन है, ये राज्य और देश में अन्य वी सी ए के साथ समन्वय करेगी।
- (च) जहां पर भारतीय स्थापन प्रभावी नहीं होता, तो यह आवेदन प्राप्ति के दो मास के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र वी सी ए मान्यताप्राप्त स्थापना एजेंसी को देगा ताकि बच्चे को अन्तर्देशीय दत्तकग्रहण के लिए दिया जा सके।
- (छ) किसी ऐसे मामले में जहां बच्चे को तत्काल चिकित्सा या सर्जरी महायता की आवश्यकता है, वी सी ए सम्पर्क पैराग्राफ 4.24 में चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निर्धारित प्रतीक्षा अवधि में छुट ले सकती हैं और शीघ्रानिश्चय अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगी।
- (ज) ये कम से कम एक-एक तिमाही में सदस्य एजेंसियों की एक बैठक बुलाएंगे।
- (झ) यदि जहां ऐसे दिशानिर्देशों का पालन मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसियों द्वारा नहीं किया जा रहा है, संबंधित वी सी ए समुचित कार्रवाई करने के

लिए पर्याप्त प्रमाण सहित कारा के ध्यान में लाएंगी।

7.2 वी सी ए सोमायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत की जाएगी और इस अधिनियम के अंतर्गत सभी नियमों और इन दिशानिर्देशों का भी पालन करेगी।

7.3 प्रत्येक वी सी ए के पास अपने स्टाफ में कम से कम दो प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता होंगे।

7.4 प्रत्येक वी सी ए का कारा से मान्यताप्राप्त करने के लिए एक आवेदन करना होगा जोकि राज्य सरकार के माध्यम से अप्रेषित होगा और राज्य सरकार यह आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अपनी टिप्पणियां देगी और यदि 30 दिन की अवधि में कोई टिप्पणियां प्राप्त नहीं होती हैं, तो यह माना जायेगा कि राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

7.5 सभी मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसियां (चार अंतर्देशीय या अंतरदेशीय दत्तकग्रहण का काम कर रही हैं) वी सी ए का सदस्य बनने की पात्र होंगी और वे बाल कल्याण एजेंसियां जो दत्तकग्रहण के लिए बच्चे नहीं देती हैं बल्कि बच्चों के लिए केवल गृह चला रही हैं, भी वी सी ए का सदस्य बनने की पात्र होंगी। यदि कोई एजेंसी कारा द्वारा कुप्यवस्था या किसी अन्य वैध कारण से मान्यताहीन कर दी जाती है या बाल कल्याण एजेंसी का राज्य सरकार द्वारा लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है तो इसी वी सी ए की सदस्यता समाप्त हो जाएगी और ये वी सी ए की सदस्यता की तब तक पात्र नहीं होगी जब तक इसे पुनः मान्यता या लाइसेंस प्रदान नहीं हो जाता है।

7.6 मान्यताप्राप्त स्थापन एजेंसियों को वी सी ए की कार्यकारी समिति के चुनाव में वोट देने का अधिकार होगा। बाल कल्याण एजेंसियां वोट का अधिकार नहीं होगी। वी सी ए प्रजातांत्रिक ढंग से एक स्वतंत्र पंजीकृत निकाय होना चाहिए। अध्यक्ष देश में या अन्तरदेशीय स्थापन में से किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए।

वी सी ए का ढांचा

7.7 वी सी ए के दैनिक कार्यों का प्रबन्ध करने के लिए एक कार्यकारी समिति होगी। इस कार्यकारिणी समिति में तीन से कम सदस्य नहीं होंगे और वी सी ए के सदस्यों के एक-तिहाई से अधिक नहीं होंगे।

वी सी ए की कार्यकारिणी समिति

7.8 वी सी ए की कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित होंगे:—

(क) वी सी ए के अध्यक्ष

(ख) राज्य सरकार का उप निदेशक (कल्याण)/बाल कल्याण या अधिक स्तर का प्रतिनिधि।

(ग) संबंधित वी सी ए के क्षेत्राधिकार में कार्यरत प्रत्येक जांच एजेंसी का एक वरिष्ठ प्रतिनिधि

(घ) अनन्य भारतीय दत्तकग्रहण करने वाली एजेंसियों का एक प्रतिनिधि ।

(ङ) मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसियों के तीन प्रतिनिधि, इसमें से कम से कम दो स्थापन एजेंसियों से होंगे जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान कम से कम 50 प्रतिशत बच्चे देश में ही दत्तकग्रहण कराए हों जिनका चुनाव बी. सी. ए. की सदस्य मान्यता-प्राप्त स्थापन एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। कार्य-कारिणी समिति के मद (ग) और (घ) के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा और वे अगले दो वर्ष के लिए पुनर्नियुक्त हेतु पात्र नहीं होंगे ।

बी. सी. ए. की कार्यकारिणी समिति बी. सी. ए. के दैनिक काम को निपटाने के लिए स्टाफ नियुक्त कर सकती है। ऐसा बेतन-भोगी स्टाफ कार्यकारिणी समिति के प्रति जवाबदेह होगा ।

7.9 बी. सी. ए. द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण-पत्र दो व्यक्तियों के हस्ताक्षरित होगा—अध्यक्ष और सदस्य-सचिव और ये दोनों देश में और अन्तर-देशीय दत्तक ग्रहण दोनों की गतिविधियों से सम्बद्ध नहीं होंगे । कोई भी मान्यताप्राप्त स्थापन एजेंसी, इन उक्त दिशानिर्देशों में संदर्भित छूट प्रदान किए गए वर्गों के मामले को छोड़कर अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बिना अन्तरदेशीय दत्तकग्रहण के लिए आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई नहीं करेगी ।

बी. सी. ए. द्वारा निम्नलिखित मुख्य प्रक्रिया अपनायी जानी है :—

7.10 (क) सभी सदस्य एजेंसियों को बच्चों और भावी दत्तकग्राही माता-पिता की एक सूची मासिक आधार पर बी. सी. ए. को अवश्य प्रस्तुत करनी होगी ।

(ख) जब कोई एजेंसी किसी बच्चे को विदेशी दत्तक-ग्रहण में देना चाहती है तो इसे पहले बी. सी. ए. से यह पता लगा लेना होगा कि क्या कोई भारतीय माता-पिता बच्चे को दत्तकग्रहण में लेने के इच्छुक हैं ।

(ग) उच्चतम न्यायालय के निर्णय में किसी बच्चों को भारतीय माता-पिता को दत्तकग्रहण में देने के लिए प्रयास करने की दी गई 30 दिन की अवधि अपर्याप्त मानी गई है और इसे उस दिन से जब कोई भारतीय परिवार तलाश करने के लिए बी. सी. ए. की सहायता मांगी जाती है, 60 दिन तक विस्तारित किया जाना चाहिए । यह प्रक्रिया 5 सप्ताह के दौरान ही

अपनाई जानी चाहिए जिसके भीतर ही कारा को एक अंतिम निर्णय देना होगा ।

(घ) बी. सी. ए. के लिए भारत में स्थापन तलाश करने के लिए समय-सीमा 60 दिन होगी जैसा कि उक्त धारा (ग) में दिया गया है और उसके बाद ही केवल अन्तर-देशीय स्थापन पर कार्रवाई की जाएगी ।

(ङ) यदि स्थापन एजेंसी और बी. सी. ए. के बीच अन्तर-देशीय दत्तकग्रहण के लिए बच्चे की निकासी के संबंध में मतभेद है, स्थापन एजेंसी ऐसे मामले कारा को भेज सकती है । ऐसे मामलों में कारा यह निर्णय करेगी कि बच्चे का निर्णय देना है या नहीं, कारा का निर्णय अंतिम होगा ।

मान्यता के लिए मानदण्ड

7.11 बी. सी. ए. के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी एजेंसी को निम्नलिखित मानदण्ड पूरे करने होंगे:—

(1) यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत होनी चाहिए ।

(2) कारा द्वारा मान्यता दिए जाने हेतु इसको संबंधित राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए ।

(3) यह एजेंसी गैर-वाणिज्यिक और लाभ न कमाने के आधार पर चलनी चाहिए ।

(4) इसके पदाधिकारी पैरा 7.8 में मद (घ) और (ङ) के अनुसार मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसियों से होंगे जिन्होंने एक वर्ष से कुल स्थापन हेतु दिए गए बच्चों में से 50 प्रतिशत या अधिक की सीमा तक विकलांग बच्चों और 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को छोड़कर देश के भीतर ही दिए हैं ।

(5) सभी पदाधिकारी भारतीय राष्ट्रीय होंगे । बी. सी. ए. की आरम्भिक मान्यता 3 वर्ष की अवधि के लिए होगी ।

मान्यता का नवीकरण

7.12 कोई भी बी. सी. ए. जो मान्यता का नवीकरण चाहती है, को अपना आवेदन पिछली मान्यता के समाप्त होने से छह मास पहले, राज्य सरकार के माध्यम से कारा को प्रस्तुत करना चाहिए । मान्यता के नवीकरण हेतु मुख्य मानदण्ड निम्नलिखित होंगे :—

(1) देश के भीतर दत्तकग्रहण को बढ़ावा देने में संतोष-जनक कार्य निष्पादन ।

(2) कारा द्वारा विनिर्दिष्ट रिपोर्टों और विवरणियों की समय पर प्रस्तुति ।

मान्यता वापस लेना

7.13 राज्य सरकार से असंतोषजनक कार्य के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होने पर और बी. सी. ए. को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक अवसर देने के बाव, कारा किसी बी. सी. ए. की मान्यता वापस ले सकती है। बी. सी. ए. को अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रही सभी स्थापन एजेंसियों के बीच अधिक समन्वय लाने के लिए, सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। कोई भी गड़बड़ी, यदि प्रमाणित हो जाए, तो उससे मान्यता समाप्त होने के रूप में तत्काल कार्रवाई होगी। राज्य सरकार या कारा द्वारा मांगी गई रिपोर्टें/प्रतिक्रियाएं न देना या देरी करना भी मान्यता वापस लेने का एक आधार हो सकता है।

7.14 बी. सी. ए. की तिमाही बैठकें आयोजित करके सभी पात्र सदस्य भाग लें और दत्तकग्रहण से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करें। संबंधित बी. सी. ए. द्वारा बैठकों के कार्यवृत्त कारा को भेजे जाने चाहिए।

बी. सी. ए. का वित्तपोषण

7.15 कल्याण मंत्रालय में भारत सरकार निर्धारित मानदण्डों के अनुसार बी. सी. ए. को लागत के 90 प्रतिशत तक सहायता अनुदान देगी।

वर्तमान बी. सी. ए.

7.16 वर्तमान बी. सी. ए. के कार्य क्षेत्र के लिए इन दिशानिर्देशों के अनुसार जैसे ही बी. सी. ए. गठित की जाती है, वर्तमान बी. सी. ए. अधिक्रमित मानी जाएगी।

7.17 यदि किसी क्षेत्र में केवल एक मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसी है, तो यह अधिक साथ वाले क्षेत्र में काम कर रही बी. सी. ए. की मदद बनने की पात्र होगी।

अध्याय - 8

जांच एजेंसी

8.1 यह न्यायालय के लिए खुला है कि वह बच्चे को दत्तक ग्रहण के लिए भावी दत्तकग्राही माता-पिता से आवेदनपत्र की जांच के लिए जांच एजेंसी के रूप में किसी स्वतंत्र, ख्यातिप्राप्त सामाजिक अथवा बाल कल्याण एजेंसी की नियुक्ति को धारा 11 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अंतर्गत संरक्षक के नियुक्ति मामले की जांच करे। यह एजेंसी बाल-देखभाल तथा कल्याण के क्षेत्र में विशेषज्ञों की एक समिति होनी चाहिए जो दत्तक ग्रहण में बच्चों के स्थापन संबंधी कार्यों में किसी ढंग से शामिल नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में दो जांच एजेंसियों अर्थात् भारतीय समाज कल्याण परिषद् तथा भारतीय बाल कल्याण परिषद् हैं, जो न्यायालय

द्वारा नियुक्त की गई हैं। न्यायालय से जांच एजेंसी के रूप में किसी अन्य पात्र बाल अथवा समाज कल्याण एजेंसी, जो कारा द्वारा निर्धारित पात्रता और मानदंडों को अधिमानतः पूरा करती है, को नियुक्त करने का अनुरोध किया जा सकता है।

मान्यता के लिए प्रक्रिया

8.2 कारा एजेंसियों का एक पैनेल बनाएगा जो इसके अनुसार एक जांच एजेंसी का कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा कर सकती है। भारतीय बाल कल्याण परिषद् तथा भारतीय समाज कल्याण परिषद् से अन्यथा किसी एजेंसी को एक जांच एजेंसी के रूप में मान्यता हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित होगी:—

- (1) एजेंसी को जांच एजेंसी के रूप में मान्यता के लिए कारा को आवेदन करना होगा।
- (2) एजेंसी को जांच एजेंसी के रूप में मान्यता के लिए कारा द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करना होगा।
- (3) कारा मान्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए जांच एजेंसी से ऐसी सूचना मांग सकती है जो इसकी वास्तविकता और कार्य-निष्पादन के संबंध में आवश्यक हो सकती है और ऐसी रिपोर्ट के आधार पर मान्यता प्रमाणपत्र जारी कर सकती है।
- (4) जांच एजेंसी को प्रारंभ में तीन वर्षों के लिए मान्यता दी जाएगी तथा नवीकरण इन दिशानिर्देशों में दी गई पद्धति के अनुसार होगा।

मान्यता हेतु मानदंड

- 8.3 (1) एजेंसी को एक आत्म-निर्भर, विख्यात सामाजिक/बाल कल्याण एजेंसी होना चाहिए।
- (2) एजेंसी बाल-देखभाल तथा कल्याण के क्षेत्र में विशेषज्ञों की एक समिति होनी चाहिए।
- (3) एजेंसी दत्तकग्रहण में बच्चों के स्थापन संबंधी कार्य में शामिल नहीं होनी चाहिए।
- (4) यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत एक सोसायटी होनी चाहिए।
- (5) सभी पदाधिकारी भारतीय नागरिक होने चाहिए।
- (6) एजेंसी को एक गैर-वाणिज्यिक तथा लाभ प्राप्त न करने वाली एजेंसी के आधार पर कार्य करना चाहिए।

मान्यता का नवीकरण

- 8.3 (क) प्रत्येक मान्यता प्राप्त एजेंसी को मान्यता के नवीकरण के लिए, पिछली मान्यता के समाप्त होने की तारीख से 6 माह पूर्व आवेदन करना चाहिए। यदि जांच एजेंसी का कार्य निष्पादन संतोषजनक पाया गया है तथा किसी कार्यालय

अथवा संबंधित राज्य सरकार से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है और कारा द्वारा मांगी गई कोई रिपोर्ट अथवा रिटर्न यदि नियमित रूप से बिना देर किए इसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने हैं तो मान्यता का समय-समय पर नवीकरण किया जाएगा परन्तु प्रत्येक बार यह 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा।

बचाव धारा

8.4 किसी भी जांच एजेंसी को, किसी राज्य सरकार अथवा किसी न्यायालय के कदाचार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, कारा के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करते हुए एजेंसी को एक अवसर प्रदान करने के बाद, किसी भी समय कारा द्वारा मान्यता वापस ली जा सकती है।

जांच एजेंसी का कार्यकरण

8.5 प्रत्येक जांच एजेंसी को निम्नलिखित कार्य करना आवश्यक होगा :—

(1) निम्नलिखित दस्तावेजों की जांच करना :

- (1) अभिभावकत्व हेतु आवेदन पत्र/भावी दत्तक ग्राही विदेशी माता-पिता की ओर से किया गया दत्तक ग्रहण।
- (2) गृह अध्ययन रिपोर्ट।
- (3) बाल अध्ययन रिपोर्ट।
- (4) आवेदन पत्र के साथ संलग्न कोई अन्य दस्तावेज/प्रमाणपत्र।

(2) यह सुनिश्चित करना कि आवेदन पत्र अथवा आवेदन पत्र की प्रति, जैसा भी मामला हो, कारा को विदेशी एजेंसी द्वारा विधिवत अग्रप्रेषित की गई है।

(3) यह सुनिश्चित करना कि बच्चे को विदेशी दत्तक-ग्राही माता-पिता को संरक्षता में रखे जाने से पूर्व संबंधित वी सी ए से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(4) स्वयं को इस बात से संतुष्ट करना कि प्रपन्नगत बच्चा दत्तक-ग्रहण के लिए कानूनी रूप से मुक्त है।

(5) बच्चे को व्यक्तिगत रूप से देखना तथा यह जांच करना कि बच्चे के संबंध में भावी दत्तक-ग्राही माता-पिता को दी गई सूचना उचित है। यदि बच्चे की चिकित्सा/शारीरिक स्थिति में कोई परिवर्तन हो तो जांच एजेंसी यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि भावी दत्तक-ग्राही माता-पिता को उस परिवर्तन की सूचना दी गई है तथा संबंधित न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित होने से पूर्व उनकी सहमति प्राप्त कर ली है।

(6) स्वयं को इस बात से संतुष्ट करना कि भावी दत्तक-ग्राही माता-पिता अभिभावक विचाराधीन बच्चे को गोद लेने के लिए उचित व्यक्ति हैं।

(7) यह सुनिश्चित करना कि यह दत्तक-ग्रहण बच्चे के सर्वोत्तम हित में होगा।

(8) न्यायालय को यह पता लगाने के लिए महायत्ना करना कि क्या बच्चा जैविक माता-पिता द्वारा स्वेच्छा से अग्रप्रेषित किया गया है।

(9) जांच करना तथा स्वयं को संतुष्ट करना कि भारतीय तथा संबंधित विदेशी एजेंसियों सहित किसी भी विचाराधीन दत्तक-ग्रहण से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर रहा हो।

(10) बड़े बच्चों के मामले में दत्तक-ग्रहण संबंधी बच्चे के अपने विचारों को प्रमाणित करना। कारा को तत्काल इसके बारे में सूचित करना होगा।

(11) जहां तक संभव हो यह पता लगाना कि भावी दत्तक-ग्राही माता-पिता के देश में विदेशी बच्चों के दत्तक-ग्रहण संबंधी क्या कानून हैं तथा उनमें समुचित आश्वामन हो कि बच्चा कम से कम संभावित अवधि के अन्दर गोद ले लिया जाएगा लेकिन किसी भी मामले में यह अवधि दो वर्षों से अधिक नहीं होगी।

(12) यह सुनिश्चित करना कि विकलांग, सहोदर, अधिक आयु तथा अन्य आवश्यकताओं वाले बच्चों को एक ऐसे परिवार को दे दिए जाने से पूर्व एह-तियाती उपाय कर लिए गए हैं जो ऐसे बच्चों में वास्तव में रुचि रखते हैं।

8.6 जांच एजेंसी जांच किए गए सभी मामलों की प्रत्येक छः माह में एक बार कारा को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

8.7 भावी दत्तक-ग्राही माता-पिता के साथ बच्चे को रखने या भावी दत्तक-ग्राही माता-पिता के अनुकूल बनाने या कोई अन्य संबंधित मृद्दे के संबंध में स्थापन एजेंसी तथा जांच एजेंसी के मध्य कोई मतभेद होने पर जांच एजेंसी इसे कारा के विचारार्थ भेज सकती है।

जांच प्रभार

8.8 जब कभी भारतीय माता-पिता में से कोई एक स्वयं को किसी बच्चे के संरक्षक के रूप में नियुक्त करता/करती है या हिंदू माता-पिता में से कोई एक किसी बच्चे को गोद लेने के लिए अनुमति हेतु आवेदन करता/करती है और यदि न्यायालय द्वारा जांच एजेंसी को मामला भेजा जाता है तो जांच एजेंसी जब तक कि न्यायालय द्वारा दुबतर राशि का निर्णय नहीं किया गया हो न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार 150 रु. तक के खर्च की ऐसी राशि का प्रभार लगा सकती है।

जब विदेशी एजेंसी संरक्षकता के लिए आवेदन करती तो जांच एजेंसी बहन किए गए वास्तविक व्यय के लिए 450 रुपए से 500 रुपए के बीच न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट राशि भारतीय एजेंसी से प्रभार के रूप में ले सकती है तथा संबंधित भारतीय एजेंसी को विदेशी माता-पिता से जिनके आवेदन पर संरक्षकता के लिए इसने कार्रवाई की है, ऐसी राशि को वसूल करने का अधिकार होगा। यथा संबंधित न्यायालय किए गए विशिष्ट कार्य के लिए भुगतान की जाने वाली वास्तविक बढ़ी हुई राशि का आदेश विशेष रूप से देता है तो यह राशि 500 रुपए तक बढ़ सकती है।

अध्याय 9

विषय

दिशा निर्देशों का उल्लंघन

9.1 यदि यह किसी राज्य सरकार, अथवा भारत के किसी राजनयिक मिशन या कारा के ध्यान में आती है कि एक पंजीकृत भारतीय एजेंसी अथवा सूचीबद्ध विदेशी एजेंसी इन दिशा-निर्देशों के सभी अथवा सूचीबद्ध विदेशी नहीं कर रही है या उस ढंग से किसी उपबंध का पालन सामान्यतः बच्चों के हित से अन्यथा कार्य कर रही है जो को व्योक्तित्व में नहीं है तो वह तत्काल कारा को व्योक्तित्व प्रदान करेगी तथा कारा अपने विवेकानुसार ऐसी सूचीबद्ध एजेंसी की मान्यता समाप्त या वापस कर सकती है और अथवा अन्य ऐसी कार्रवाई कर सकती है जो आवश्यक समझी जाए।

9.2 यदि यह किसी राज्य सरकार के लिए यह वांछनीय होगा कि वह उन एजेंसी को प्रोत्साहित करे जो दत्तक ग्रहण के लिए भारत से बच्चे प्राप्त कर रहे हैं तथा ऐसे एजेंसी को प्रोत्साहित करने के लिए भारत उचित प्राधिकारियों और प्राप्तकर्ता के मध्य पूरा समन्वय दान करने तथा प्राप्तकर्ता राज्य में दत्तकग्रहण के लिए, लिए गए बच्चों के कल्याण की सुरक्षा और सुरक्षोपाय के लिए भी उपबंध होना चाहिए।

9.3 यह आशंका व्यक्त की गई है कि अनैतिक तत्व देश में कुछ अस्पतालों, नर्सिंग होमों, प्रसूति गृहों में बच्चों का उनके जन्म के समय दत्तकग्राही माता-पिता को गैर कानूनी स्थानांतरण करते हैं। बच्चों के ऐसे स्थानांतरण उचित मानदंडों तथा प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना हो रहे हैं जो गैर कानूनी है और इस प्रकार यह बच्चे के हित में बिल्कुल नहीं है। यदि कोई ऐसी शिकायतें कारा के ध्यान में आती हैं तो यह जोच किए जाने का आदेश देगी तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् सहित केन्द्र अथवा राज्य सरकार के उचित प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाएगी।

दिशानिर्देशों में संशोधन

कल्याण मंत्रालय भारत सरकार स्वयं स्वविवेक से इन मार्ग-निर्देशनों में ऐसे संशोधनों को करने, जोड़ने, हटाने अथवा

परिवर्तन करने, जैसा समय-समय पर आवश्यक समझे जाएं, की शक्ति निहित है।

अनुबन्ध—क

भारतीय बच्चे के अन्तःदेशीय आवेदन के विचारार्थ भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध किए गए समाज अथवा बाल कल्याण एजेंसी और दत्तकग्राही माता-पिता से अशिक्षित दस्तावेजों की सूची।

(क) अनुबन्ध “क” के अनुसार व्यावसायिक कार्यकर्ता द्वारा तैयार की गई दत्तकग्राही विदेशी माता-पिताओं की गृह अध्ययन रिपोर्ट।

(ख) दत्तकग्राही परिवार के हाल ही के फोटोग्राफ।

(ग) दत्तकग्राही विदेशी माता-पिताओं को वैवाहिक प्रमाणपत्र।

(घ) दत्तकग्राही माता पिता की स्वास्थ्य संबंधी घोषणा।

(ङ) मेडिकल डाक्टर द्वारा प्रमाणित दत्तकग्राही माता-पिता के आरोग्यता प्रमाणपत्र।

(च) विदेशी दत्तकग्राही माता पिता की वित्तीय स्थिति से संबंधित घोषणा के साथ, जहां आवश्यक हो नियोजित प्रमाणपत्र सहित सहायक प्रमाणपत्र।

(छ) दत्तकग्राही विदेशी माता पिता का रोजगार प्रमाण पत्र, यदि लागू हो।

(ज) दत्तकग्राही विदेशी माता पिता का आयकर मूल्यांकन आदेश।

(झ) बैंक संदर्भ।

(ञ) दत्तकग्राही विदेशी माता-पिता के स्वामित्व की संपत्तियों का व्यौरा।

(ट) दत्तकग्राही विदेशी माता-पिता से बच्चे के संरक्षक नियुक्त किए जाने के लिए इच्छा व्यक्त करने संबंधी घोषणा।

(ठ) विदेशी को प्रायोजित करने वाली समाज अथवा बाल कल्याण सूचीबद्ध एजेंसी से इस आशय का वचन पत्र कि बच्चे के पहुंचने के समय से ज्यादा से ज्यादा दो वर्षों के अन्दर तथा ज्यों ही दत्तकग्राही प्रभावी होता है देश के कानून के अनुसार दत्तकग्राही विदेशी माता पिता द्वारा बच्चा कानूनी तौर पर गोद लिया जाएगा। समाज अथवा बाल कल्याण सूचीबद्ध एजेंसी भारत में समाज अथवा बाल कल्याण एजेंसी को दत्तकग्रहण आदेश की तीन प्रमाणित प्रतियां भेजेगी जिसके जरिए संरक्षकता हेतु आवेदन, न्यायालय में दायर करने के लिए कार्रवाई की जाती है तथा एक प्रति केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी, कल्याण मंत्रालय को भेजेगी।

(ड) दत्तकग्राही विदेशी माता पिता से यह वचन पत्र कि गोद लिए जाने वाले बच्चे को आवश्यक शिक्षा प्रदान की जाएगी तथा दत्तकग्राही माता पिता के स्तर के अनुसार पालन पोषण किया जाएगा।

(ढ) समाज तथा बाल कल्याण सूचीबद्ध एजेंसी से आशय का एक वचन पत्र कि बच्चे के हाल ही के फोटो के साथ उसकी प्रगति से संबंधित रिपोर्ट विदेश स्थित भारतीय राजनयिक मिशन के माध्यम से निर्धारित प्रोफार्मा में पहले दो वर्षों के दौरान तिसाही तथा अगले तीन वर्षों में छमाही भेजी जाएगी।

(ण) भारत में समाज अथवा बाल कल्याण एजेंसी के अधिकारियों के पक्ष में दत्तकग्राही विदेशी माता-पिता से मुस्तारनामा जो कि मामले पर कार्रवाई करने के लिए आवश्यक होगा तथा ऐसे मुख्यतारनामे को विदेशी के पक्ष में मामले को चलाने के लिए प्राधिकृत करेगा, यदि विदेशी भारत में आने की स्थिति में नहीं है।

(त) विदेशी के आवेदन को प्रायोजित करने वाली सूचीबद्ध समाज अथवा बाल कल्याण एजेंसी से इस आशय का प्रमाणपत्र कि दत्तकग्राही माता-पिता को अपने देश के कानून के अनुसार बच्चे को गोद लेने की अनुमति है।

(ध) समाज अथवा बाल कल्याण सूचीबद्ध एजेंसी से इस आशय का वचन पत्र कि कानूनी तौर से दत्तकग्रहण प्रभावी होने से पूर्व विदेशी के परिवार के विघटन के मामले में, यह बच्चे की देखभाल करेगी तथा केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी के अनुमोदन से बच्चे के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थापन प्राप्त करेगी। कारा से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद यह विदेश में संरक्षकता संबंधी मामलों पर कार्रवाई कर रहे संबंधित न्यायालय को वैकल्पिक स्थापन की सूचना देगी और ऐसी सूचना न्यायालय द्वारा केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी को भेजी जाएगी।

द) समाज या बाल कल्याण सूचीबद्ध एजेंसी से इस का वचन पत्र कि वह बच्चे के अनुरक्षण तथा प्रक्रिया र फीस के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा निश्चित किए गए सभी खर्चों को संबंधित भारतीय समाज अथवा बाल कल्याण एजेंसी को वापस करेगी।

महत्वपूर्ण अनुदेश

(1) गृह अध्ययन रिपोर्ट में अनुबंध "क" में दिए गए विभिन्न मुद्दों के संबंध में सूचना व्यापक सूची में शामिल होनी चाहिए। यद्यपि इस अनुबंध में दी गई अपेक्षाओं पर पूर्णतया ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है तथा इसमें समाज अथवा बाल कल्याण एजेंसी द्वारा इस तरह का मूल्यांकन होना चाहिए कि क्या बच्चे को गोद लेने की इच्छा करने वाले विदेशी या अगले बच्चे को मातृत्व-पितृत्व प्रदान करने की परिवेश से और तथा क्या बच्चा दत्तकग्राही परिवार में क्षमता रखता है जिसमें वह रहता है, ठानने योग्य वातावरण तथा समुदाय में जिसमें वह रहता है, ठानने योग्य है।

(2) उक्त सभी प्रमाणपत्र, आवेदन के आवेदन के साथ ग्रहण के लिए बच्चे को लेने हेतु विदेशी से विधिवत प्रमाणित होने चाहिए और वे नोटरी पब्लिक के प्रमाणित होने चाहिए जिनके हस्ताक्षर विदेश मंत्रालय अथवा न्यायाधीश या विदेशी के देश के समाज में कांसुनेट से भारतीय दूतावास या उच्चायोगों या उस देश में प्रमाणित होने चाहिए।

अन्तर-देशीय दत्तकग्रहण को विनियमित करने की कार्यविधि

अप्रवासी भारतीय

भावी दत्तकग्राही विदेशी माता पिता

सम्पर्क करने के लिए

विदेशी सूचीबद्ध एजेंसी

—गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना

—सभी दस्तावेजों को पूरा करना

—को दस्तावेज प्रस्तुत करना

—प्रमाणित प्रति

—यह देखना कि क्या विदेशी एजेंसी सूचीबद्ध है।

मूल आवेदन पत्र तथा दस्तावेज

भारतीय मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसी

—एजेंसी में माता पिता को पंजीकृत करना

—बेबाकी प्रमाण पत्र के लिए संबंधित पी सी ए से संपर्क करना ↓

कारा

1

2

वी सी ए

—देश के अन्दर बच्चे के लिए संभावनाओं का पता लगाना

—सभी दस्तावेजों की जांच करना तथा सुनिश्चित करना तथा कि सभी नियमानुसार हैं।

—स्थापन एजेंसी को बेबाकी प्रमाणपत्र जारी करना

भारतीय मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसी

—गोद लेने वाले भावी विदेशी माता-पिता के साथ बच्चे का प्रत्यक्ष होना

—प्रस्तावित बच्चों के लिए गोद लेने वाली विदेशी माता-पिता की मंजूरी प्राप्त करना

सूचीबद्ध विदेशी एजेंसी

—दत्तकग्राही विदेशी माता पिता के अनुमोदन की स्थापन एजेंसी को भेजना

—स्थापन एजेंसी को बेबाकी प्रमाणपत्र जारी करना

—भारतीय परिवार के साथ बच्चे के स्थापन में मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसी द्वारा किए गए प्रयासों को सुनिश्चित करना तथा इसके लिए वी सी ए की स्वीकृति है।

भारतीय मान्यताप्राप्त स्थापन एजेंसी

—सक्षम न्यायालय में मामले पर कार्रवाई करना

भारतीय न्यायालय

—जांच एजेंसी द्वारा जांच किए गए दस्तावेजों को प्राप्त करना

—भावी दत्तकग्राही विदेशी माता पिता के पक्ष में बच्चे की संरक्षता प्रदान करना

भारतीय मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसी

—कारा को न्यायालय के आदेश की एक प्रति भेजना

—बच्चे के पासपोर्ट की व्यवस्था करना

—बच्चे को भावी विदेशी माता पिता या अनुरक्षक या विदेशी पंजीकृत एजेंसी के प्रतिनिधि को सौंपना।

विदेशी सूचीबद्ध एजेंसी

—आपने देश में बच्चे को ले जाना।

—संबंधित दत्तकग्राही माता पिता को बच्चे को देना।

—कानूनी दत्तक ग्रहण के लिए बच्चे के मामले को उठाना।

—बच्चे की प्रगति देखना।

—कानूनी दत्तक ग्रहण के आदेश और प्रगति रिपोर्ट की एक प्रतिकाग, संबंधित भारतीय मान्यताप्राप्त एजेंसी और संबंधित भारतीय न्यायालय को प्रस्तुत करना।

अनन्तः बच्चा दत्तकग्राही परिवार के साथ जुलमिल जाता है।

MINISTRY OF WELFARE

CHAPTER I

RESOLUTION

New Delhi, the 29th May, 1995

No. 4-1/93-CARA.—In order to facilitate the implementation of the norms, principles and procedures relating to adoption of children laid down by the Supreme Court in their judgements dated 6-2-1984, 27-9-1985 and 3-12-1986 in Writ Petition L. K. Pandey Vs. Union of India (No. 1171) of 1982, the Government of India had issued certain guidelines vide Ministry of Welfare Resolution No. 13-33/85-CHI(AC) dated 4th July, 1989.

2. Subsequently, some more clarificatory judgements in the same case were issued by the Supreme Court on 19th September, 1989, 14 August 1991, 29 October 1991, 14 November 1991 and 20 November 1991. Moreover, in the light of experience gained in the implementation of the guidelines issued in 1989, it was felt necessary to revise the guidelines previously issued. Accordingly, a Task Force consisting of a cross-section of representatives of agencies involved in adoption under the Chairmanship of Justice (Retd.) P. N. Bhagwati, former Chief Justice of India was constituted on 12 August, 1992. The Chairman of the Task Force submitted its Report on 28-8-1993.

3. The Government of India have examined the Report of the Task Force in consultation with the Department of Legal Affairs.

4. One of the recommendations contained in the report relates to change in the status of CARA from a wing of the Ministry of Welfare to an autonomous body to be registered under the Registration of Societies Act. This recommendation is under consideration and orders in this regard will be issued separately.

5. Some of the recommendations of the Task Force envisage; an upward revision of the ceiling of expenses payable to a placement agency by the prospective adoptive parents for which the approval of the Supreme Court would be required. This aspect is also separately under consideration.

6. Barring recommendations relating to the issues mentioned above, Government have accepted the Report of the Task Force in toto.

7. Accordingly, the Government of India hereby issue Revised Guidelines on Adoption of Children as per Annexure-I to this Resolution for the information and guidance of general public, voluntary agencies as well as all concerned with the subject matter.

A. K. CHAUDHARY, Jt. Secy.

REVISED GUIDELINES TO REGULATE MATTER RELATING TO ADOPTION OF INDIAN CHILDREN (1994)

Aims and Objects

1.1 The objective of the present guidelines is to provide a sound basis for adoption with in the framework of the norms and principles laid down by the Supreme Court of India in the series of judgements delivered in L. K. Pandey Vs. Union of India and Others between 1984 and 1991.

1.2 Adoption undoubtedly offers an important avenue for the care and protection of an abandoned, destitute or neglected child in a family setting and provides an atmosphere of happiness, love and understanding for the realisation of his/her talents and potentials. It carries with it all the emotional physical and material security necessary for the proper development of the child and also serves as the most reliable means of preventing situations associated with the abuse, exploitation and social maladjustment of abandoned, destitute and neglected children.

1.3 The Government of India, in pursuance of its constitutional mandate, has evolved a National Policy for the welfare of children. The thrust of this policy is summed up in the following words :

"The nation's children are a supremely important asset. Their nurture and solicitude are our responsibility. Children's programme should find a prominent part in our national plans for the development of human resources, so that our children grow up to become robust citizens, physically fit, mentally alert and morally healthy, endowed with the skills and motivations needed by society. Equal opportunities for development to all children during the period of growth should be our aim, for this would serve our larger purpose of reducing inequality and ensuring social justice."

1.4 There has been equally great concern for the welfare of children at the international level culminating in the Declaration of the Rights of the Child, adopted by the General Assembly of the United Nations on 20th November, 1959. Thereafter, in various international fora conferences and seminars, this subject of child welfare has continued to be constantly debated.

1.5 The National Policy for the Welfare of Children also stresses the vital role which the voluntary organisations have to play in the field of education, health, recreation and social welfare services for children and declares that it shall be the endeavour of the state to encourage and strengthen such voluntary organisations. Need for Family support for the Development of the children

1.6 It is an accepted fact that the balanced development of a child—emotional, physical and intellectual can be best ensured within the family, or where this

is not possible, then in familial surroundings. The responsibility for providing care and protection to children including those who are orphaned, abandoned, neglected and abused rests primarily with the family, the community and the society at large. However, since many traditional institutions including the family structure are undergoing vertical as well as horizontal social changes on account of urbanisation, industrialisation and the general process of development, family support to a child is not always available. It, therefore, becomes the responsibility of the community, of the society and of the State to provide both institutional and non-institutional support to destitute children. Government of India considers adoption as the best non-institutional support for rehabilitation of Children.

Traditionally, our society has been providing support through charitable institutions and non-institutional activities like adoption, guardianship and foster care. Due to rapid changes in the social structure and other related factors, the number of children who need care, protection and rehabilitation is on the increase. It is, therefore, necessary not only to expand both institutional and non-institutional facilities for the nurture of such children, but also to regulate and monitor all programmes so as to ensure minimum standards in all child welfare activities. Among non-institutional modes, the interest of the child can best be served through adoption in a family. Further, it is also an accepted fact that the child develops best in his or her own cultural and social milieu. Thus, placement of a child through adoption in an indigenous setting would be ideal for his or her growth and development. Inter-country adoption, i.e. adoption of Indian children by adoptive parents residing abroad, should be resorted to only if all efforts to place the child with adoptive parents residing in India prove unsuccessful. Generally, in all matters concerning adoption whether within the country or abroad, the welfare and interest of the child shall be paramount. Therefore, private adoptions of abandoned, destitute and surrendered/relinquished children conducted by unauthorised individuals, agencies or institutions should be discouraged and it should not be open to any individual agency or institution whether owned or run by the Government or not to process an application from a foreigner for taking a child in adoption. It should be the endeavour of Government to facilitate in-country adoption and to regulate inter-country adoption of Indian children.

Review of adoption procedure

1.7. In pursuance of the Supreme Court directives, the Ministry of Welfare vide its resolution dated 4-7-1989 formulated a set of guidelines to regulate, monitor and supervise programmes pertaining to adoption. That laid down the existing procedure and practices. The existing procedure and practices followed in the case of inter-country adoption were thoroughly reviewed by the Supreme Court in their subsequent judgements dated 19th September, 1989, 14th August, 1991, 29th October, 1991, 14th November, 1991 and 20th November, 1991 respectively in Writ Petition (CRL) No. 1171/1982 by Shri L. K. Pandey Vs. Union of India and others. The Ministry of Welfare after a careful study of all the judgements of the

Supreme Court of India and existing laws of the land and after taking into account the experience of the concerned Governmental as well as voluntary agencies and the changing social realities, decided to modify these guidelines. In this direction, the Ministry of Welfare constituted a Task Force consisting of members representing various voluntary placement agencies under the chairmanship of Mr. Justice P. N. Bhagwati (The former Chief Justice of India).

1.8 The revised guidelines as contained hereinafter have emerged from the Task Force recommendations.

CHAPTER II

Role of Government of India

2.1 In the Government of India all matters relating to adoption shall be dealt within the Ministry of Welfare. The Central Adoption Resource Agency (CARA) set up on 28-6-1990 under the aegis of the Ministry of Welfare in pursuance of Cabinet decision dated 9-5-1990 and when the Central Adoption Resource Agency is set up under these guidelines, then such Central Adoption Resource Agency shall deal with all matters concerning adoption as specified hereinafter.

2.2 The Government of India, Ministry of Welfare shall, from time to time, frame rules and guidelines and issue instructions to State Governments, voluntary agencies and voluntary coordinating agencies as well as to scrutinising agencies to facilitate and promote in-country adoption and to regulate inter-country adoption of Indian children.

List of Recognised Foreign Agencies for Adoption

2.3 The Central Adoption Resource Agency, shall maintain a list of all recognised foreign agencies for adoption enlisted by the Government of India. Copies of the lists of these agencies shall be supplied by the Central Adoption Resource Agency to the various High Courts in India, all the State Governments, all recognised Indian agencies, all voluntary coordinating agencies, all scrutinising agencies and all Indian missions abroad as well as all passport offices once every year.

List of Recognised Indian Agencies for Adoption

2.4 The Central Adoption Resource Agency shall also prepare a list of all recognised Indian agencies for adoption. It shall publish once a year the list of these agencies operating in each State in three leading newspapers having wide circulation in the State, one in the English language, one in the Hindi language and the third in the regional language of that State. The list shall also be sent to all the High Courts in the country for circulation to the District Courts in each State, all the State Governments, all recognised Indian placement agencies all foreign enlisted agencies, all Indian Missions abroad, all voluntary coordinating agencies, and all scrutinising agencies.

Liaison with Indian Diplomatic Missions

2.5 The Central Adoption Resource Agency shall maintain liaison with Indian diplomatic missions abroad in order to safeguard the interests of children of Indian origin adopted by foreign parents against neglect, maltreatment, exploitation or abuse and to maintain an unobtrusive watch over the welfare and progress of such children. For this purpose, the Central Adoption Resource Agency shall inform every Indian diplomatic missions concerned whenever an Indian child is taken in adoption or for the purpose of adoption, by foreign parents. The names, addresses and other particulars of such children and their adoptive/prospective adoptive parents shall be supplied to the Indian diplomatic missions as early as possible and in any case before the end of every quarter.

Meeting of Agencies Involved in Adoption

2.6 The Central Adoption Resource Agency shall arrange every year a meeting of all recognised placement agencies, voluntary coordinating agencies and scrutinising bodies for discussing matters of mutual interest and such other matters as are considered necessary and expedient.

Role of the Central Adoption Resource Agency (CARA)

2.7 As per the directions of the Supreme Court of India in Writ Petition (CRL) No. 1171/82 and on the basis of a Cabinet decision dated 9-5-1990, the Government of India in the Ministry of Welfare vide Resolution No. 1-10/88-CH(AC) dated 28th June, 1990 published in the Gazette of India No. 166 dated 3rd July, 1990 has set up a Central Adoption Resource Agency (CARA) to act as a clearing house of information in regard to children available for in-country and inter-country adoption and to regulate, monitor and develop programmes for the rehabilitation of children through adoption.

Headquarters and Regional Office of CARA

2.8 Central Adoption Resource Agency (CARA) shall have its headquarters in New Delhi. Branches/Regional Offices of Central Adoption Resource Agency (CARA) may, however, be set up at such places as may be considered appropriate.

Central Adoption Resource Agency

2.8A The Central Adoption Resource Agency (CARA) shall function under the overall policy guidance of a Steering Committee consisting of the following :—

- (i) Chairman (Non-Official).
- (ii) Secretary (CARA)—Member Secretary cum Executive Officer.
- (iii) One representative from Indian Council for Child Welfare (parent body).

(iv) One representative from Indian Council for Social Welfare (parent body).

(v) Four representatives of recognised placement agencies, one from each region, doing atleast more than 50 per cent in-country adoption.

(vi) One representative from among voluntary coordinating agencies.

(vii) One representative from the Ministry of External Affairs.

(viii) One representative from the Deptt. of Women and Child Development.

(ix) One representative from the Ministry of Information and Broadcasting.

The tenure of the members representing recognised placement agencies and voluntary coordinating agencies shall be for a period of two years on rotational basis. On the expiry of the tenure, the members shall not be eligible for renomination for the next succeeding period of two years.

The appointment of the Chairman would be in an honorary capacity. The Member Secretary cum Executive Officer of Central Adoption Resource Agency (CARA) would be an official of the rank of Deputy Secretary/Director in the Government of India who would enjoy a reasonable tenure, preferably five years.

2.9 The Central Government may pay to the Central Adoption Agency (CARA) such sums of money as may be considered necessary for the performance of its functions under this Resolution.

2.10 The accounts of the Central Adoption Resource Agency (CARA) shall be maintained and audited in such manner as may, in consultation with Comptroller and Auditor General of India, be specified by the Central Government.

2.11 The Central Adoption Resource Agency (CARA) shall, subject to the approval of the Central Government, frame its own regulations and bye-laws for discharging its functions in consonance with its aims and objectives.

2.12 The Central Adoption Resource Agency (CARA) shall have the power to constitute a Committee which will exclusively look into matters pertaining to promotion of in-country adoption and advice CARA on suitable policies and programmes for this purpose.

Functions of CARA

2.13 The functions of the Central Adoption Resource Agency (CARA) shall be as follows :—

- (1) To act as a clearing house of information in regard to children available for inter-country adoption as well as for in-country adoption ;

- (2) To receive applications or copies of applications alongwith requisite documents (as prescribed by the Supreme Court of India in CRL (WP) 1171/1982 in the matter of Shri Laxmi Kant Pandey Vs. Union of India and Others) of foreigners desirous of taking Indian children in adoption through a recognised social or child welfare agency in the foreign country or through an organisation owned or operated by the Government in that country.
- (3) Whenever such applications are received directly by Central Adoption Resource Agency (CARA) to forward such applications to one of the Indian social or child welfare agencies recognised by CARA for processing applications of foreign parents for adoption in the competent court;
- (4) To receive names and particulars of children available for adoption who are under the care of Indian social or child welfare agencies recognised by CARA and to maintain a register containing the names and other particulars of such children;
- (5) To receive periodical data from all Indian social or child welfare agencies recognised by CARA about the children admitted to their Children's Home and the Children given in adoption in-country as well as inter-country in a proforma prescribed by CARA;
- (6) To monitor and regulate the working of Indian social or child welfare agencies recognised by CARA consistently with their independent and voluntary functioning;
- (7) To inspect Indian social or child welfare agencies recognised by CARA and to report to the Central Government on the working of such agencies;
- (8) To call for annual audited statements of account from Indian social or child welfare agencies recognised by CARA;
- (9) To receive data from competent courts about children whose guardianship has been awarded in favour of foreign adoptive parents and/or who have been adopted by Indian nationals, both residents and non-residents;
- (10) To stand periodical data to Indian's Diplomatic Missions abroad in a proforma prescribed by CARA in respect of Indian children taken abroad;
- (11) To receive periodical reports about the children taken by foreign parents for the purpose of adoption in a proforma prescribed by CARA from all recognised social or child welfare agencies in foreign countries through India's Diplomatic Mission in the country where such agency is located;
- (12) To obtain periodical progress reports of children from foreign adoptive parents as well as from recognised social or child welfare agencies in foreign countries, to examine such reports and to take such follow-up action as deemed necessary;
- (13) To organise and arrange periodical meetings of VCAs working in the field of adoption for discussing matters of common interest.
- (14) To arrange sponsorship of children through community support by means of publicity and awareness programmes;
- (15) To mobilise community opinion and community resources in furtherance of adoption of children in the country itself and take all other measures necessary for the promotion of in-country adoption of children as well as welfare of children generally;
- (16) To arrange training programmes for social workers and others engaged in child welfare activity specially in the rehabilitation of children by means of adoption, and also to bring about standardisation of training courses conducted by the voluntary agencies;
- (17) To assist the courts to cross-check or re-verify the information furnished to them by various sources including the placement agencies and scrutinising agencies or to provide an independent advice in matters relating to adoption of children;
- (18) To initiate action on any other activity relating to adoption of children within the country and abroad.

PROCEDURE TO BE FOLLOWED

2.14 After careful consideration the Supreme Court of India has laid down that the following requirements should be insisted upon so far as a foreigner wishing to take a child in adoption is concerned. Every application from a foreigner desiring to adopt a child must be sponsored by social or child welfare agency recognised or licensed by the Government of the country in which the foreigner is resident and enlisted by CARA, Ministry of Welfare, Government of India. No application by foreigner for taking a child in adoption should be entertained directly by an social child welfare agency in India working in the areas of inter-country adoption or by any institution or centre or home to which children are committed by the Juvenile Court.

The original application alongwith original documents as prescribed by the Supreme Court of India would be forwarded by the foreign enlisted agency to a recognised placement agency in India. The foreign enlisted agency shall also send a copy each of the application as well as all the prescribed documents including Home Study Report enclosed with it to the Central Adoption Resource Agency (CARA) duly Notorised by Notary Public whose signature would be duly attested either by an officer of the Ministry of External Affairs or Justice or Social Welfare of the

country of a foreigner or by an Officer of the Indian Embassy or High Commission or Consulate in that country. A list of required documents is given at Annexure 'A'. The Home Study report being a crucial document should broadly include the following information :

- (a) Social Status and family background;
- (b) Description of Home;
- (c) Standard of living as it appears in the Home.
- (d) Current relationship between husband and wife.
- (e) Current relationship between the parents and children (if any children)
- (f) Development of already adopted children (if any).
- (g) Current relationship between the couple and the members of each other's family;
- (h) Employment status of the couple.
- (i) Health details such as clinical test, hear condition, past illness e'tc. (medical certificate etc.)
- (j) Economic status of the couple;
- (k) Accommodation for the child;
- (l) Schooling facilities ;
- (m) Amenities in the Home;
- (n) Reasons for wanting to adopt an Indian child;
- (o) Attitude of grant-parent and relatives towards Adoption;
- (p) Anticipated plans for the adoptive child;
- (q) Legal status of the prospective adoptive parents.

The sponsoring agency should carefully get the Home Study report prepared by the professional social worker broadly on the basis of the above information.

The receipt of the original application as well as original documents would not entitle the placement agency to proceed with the case. It can proceed only after getting 'NO OBJECTION CERTIFICATE' from the Central Adoption Resource Agency (CARA), Ministry of Welfare.

Therefore, no recognised placement agency can process the application in the competent court for inter-country adoption without having "NO OBJECTION CERTIFICATE" issued by the Central Adoption Resource Agency (CARA), Ministry of Welfare, Central Adoption Resource Agency shall however ensure that such certificate should as far as possible be issued within a reasonable period of time say 5 weeks from the date of receipt of the certified copies of the application and other documents from them. In case Central Adoption Resource Agency (CARA), rejects the application, it may specify the reasons for such refusal to the Indian recognised placement agency.

After the receipt of the original application and original documents from the enlisted foreign agency

by the recognised Indian placement agency, the concerned placement agency will register the name of the prospective foreign parents in the register meant for them. The recognised placement agency shall carefully examine the home study report of the prospective foreign adoptive parents and start the exercise in matching the home study report with the child study report. When they arrive at the conclusion that child can be placed with that particular family then they will have to ensure that the concerned child is cleared by the VCA for inter-country adoption. Thereafter the recognised placement agency will send the child study report, the photograph of the child and the medical report to the sponsoring foreign agency for the approval of the prospective adoptive parents. After obtaining the approval of the child by the prospective adoptive parents the concerned recognised placement agency will apply to CARA for getting a clearance of the child. At this stage, Central Adoption Resource Agency (CARA) shall have to ensure that the recognised placement agency has put in adequate efforts for finding an Indian family for the said child, and the clearance by the VCA to that effect is also enclosed. CARA after going through the information furnished by the recognised placement agency and VCA will immediately give the clearance to the agency. The recognised placement agency thereafter will process the case with the competent court for awarding the guardianship of the child to the foreign prospective adoptive parents. At this stage the scrutinising agency has to scrutinise all the documents and advise the competent court that the said inter-country adoption is in the best interest of the child. The competent court within the stipulated time as laid down by the Supreme Court of India awards the guardianship of the child to the foreign parents. On the basis of the Guardianship order of the court the recognised placement agency is to apply in the Regional Passport Office for obtaining an Indian Passport in favour of the child. Thereafter the visa issued by the concerned Embassy/High Commission of the concerned country for the child. The child leaves the country alongwith the prospective adoptive parents or with the escort, whatever the case may be to the country of prospective adoptive parents i.e. child's future country of residence.

The requirement of obtaining "NO OBJECTION CERTIFICATE" from Central Adoption Resource Agency will also apply in case of handicapped children, children needing urgent medical attention which the social or child welfare agency looking after the child cannot provide within the country, siblings and also children above the age of 6 years. The recognised placement agency, soon after the admission of such child without waiting for locating foreign prospective adoptive parents, shall make an application alongwith information of such child to CARA for issue of "NO OBJECTION CERTIFICATE". CARA shall ordinarily issue "NO OBJECTION CERTIFICATE" in case of handicapped/special needs children etc. within a period of one week from the date of receipt of information of such child from the Indian recognised placement agency. Simul-

taneously, the recognised Indian placement agencies would be allowed to send the referral of such children to foreign agencies of its choice and after the approval of the child by any foreign parents the concerned placement agency could follow the procedure as laid down in the judgement of the Supreme Court of India. At this stage the scrutinising agency should carefully examine all the documents furnished by the foreign agencies in this regard and advise the competent court in coming to the conclusion whether it would be in the interest of the child to be given in adoption to the foreigner. However, the recognised Indian placement agency shall obtain a certificate in this regard from the concerned Chief Medical Officer of the Government hospital prior to processing the case concerning to handicapped children and the children needing urgent medical attention for record. Details of such children together with a copy (each) of the certificate(s) issued by the CMO, where required, shall be sent at the end of each month to CARA by the concerned Indian placement agency.

2.15 Where there is no recognised foreign agency in any country, the concerned Government Department/Ministry of that country may forward the applications and related documents of the prospective adoptive parents to CARA. CARA will examine and send those papers to the recognised Indian placement agencies indicated in the application or, if there is no such indication, then to any of the recognised Indian placement agencies for further processing the case. The procedure to be adopted thereafter shall be the same as indicated in the foregoing paragraph.

The procedure for inter-country adoption at a glance may be seen at Annexure 'B'.

2.16 The recognised placement agencies should provide to the Central Adoption Resource Agency a list of the enlisted foreign agencies with which they are working or proposing to work. Where any application is originally received by the Central Adoption Resource Agency from a recognised foreign agency/Govt. Department or an Indian agency or Indian parents, the Central Adoption Resource Agency would on the basis of information available to it, send the application to any placement agency for processing it bearing in mind the operational relationship, if any, between the foreign agency and any particular placement agency. If the placement agency is unable to entertain such case, it shall promptly inform the Central Adoption Resource Agency giving reasons for not accepting the request. The Central Adoption Resource Agency may thereafter either send such case to any other recognised placement agency or even return the application to the foreign source.

2.17 The placement agencies must at the end of every quarter provide information on the number of children given in in-country adoption, the number given in inter-country adoption and the number awaiting adoption, to the Central Adoption Resource Agency.

Requirement Before the Court

2.18 Where an application is made to the Court by the parents proposing to take a child in adoption or by a placement agency on behalf of such parents for appointment of such parents as guardians of the child with a view to taking the child in adoption, the certificate of no objection by the Central Adoption Resource Agency shall be produced along with the application and if no response has been made by the Central Adoption Resource Agency to the application for taking the child in adoption, within the time limit specified in these guidelines, the application shall be accompanied by an affidavit to be made by the placement agency stating that the requirements of the guidelines have been fulfilled in regard to obtaining certificate of no objection from the Central Adoption Resource Agency.

CHAPTER III

ROLE OF THE STATE GOVERNMENTS/UNION TERRITORY ADMINISTRATION

List of Children's Home

3.1 The State Governments (the term "State Government" shall include Union Territory Administration wherever applicable) shall maintain a list of all children's homes being run for the maintenance of destitute, abandoned, orphaned, delinquent or neglected children by voluntary/private organisations which are registered, recognised or licensed under various laws.

List of Adoption Agencies

3.2 The State Government shall also separately maintain a list of all agencies handling in-country and inter-country adoption of children and shall identify those institutions/agencies which have children who are legally free for adoption.

3.3 The State Governments shall recognise Indian adoption agencies for in-country adoption as per the procedure laid down herein and shall forward applications of Indian agencies seeking recognition for inter-country adoption to the Central Adoption Resource after proper verification according to the criteria laid down in these guidelines.

Each State Government shall also :—

- (i) monitor the adoption programme within its jurisdiction and coordinate the activities of placement agencies and VCAs and scrutinising agencies ;
- (ii) encourage and promote placement of eligible children on adoption or guardianship with families within the country ;
- (iii) enforce the Orphanages and other charitable homes (Supervision and Control) Act, 1960 and/or formulate suitable alternate rules in order to maintain certain minimum standards for child care and child welfare institutions ;

(iv) inspect organisations which have applied for recognition for inter-country adoption to the Central Adoption Resource Agency and after considering whether the applicant agency fulfils all the requirements as laid down, forward the application to the Central Adoption Resource Agency with its comments, and this process shall be completed within a period of 60 days. If no response is received from the State Government within this period, the Central Adoption Resource Agency shall immediately take up the matter at an appropriate level in the State and if no response is received within a further period of 30 days, it shall presume that the State Government has no objection to the grant of recognition, if the State Government is of the view that the applicant agency should not be recognised, it shall give relevant reasons for taking this view and forward the same to the Central Adoption Resource Agency with its comments;

(v) form an Advisory Committee on adoption which shall have the following as members.—

- | | |
|---|----------|
| (a) Secretary, Women & Child Development Social Welfare Panchayat Raj | Chairman |
| (b) Director, Welfare Social Welfare Women & Child Development | Member |
| (c) Two representatives of placement Agencies, VCAs and scrutinising agencies operating under the State | Member |
| (d) Three experts in the field of social and child welfare. | Member |

The Committee shall meet periodically to discuss child welfare measures, specifically ways and means to promote in-country adoption of children. The State Government may also set up an Adoption Cell in the Directorate of Social Welfare to coordinate, regulate and develop the work of adoption and render all assistance to the advisory form on adoption. The tenure of such committee shall be three years.

Inspection of Adoption Agencies

3.4 The State Government shall periodically and atleast once a year, inspect or cause to be inspected, all agencies and institutions handling in-country and inter-country adoption as also their papers, documents and activities connected with the service of children, generally, in order to verify :—

- (i) that adoption as activity is being pursued by the organisation as a welfare measure in the interest of children and not as a commercial activity;

(ii) that proper records are being maintained for children admitted to the homes;

(iii) that the children admitted are provided with basic minimum facilities for their care, at least education and development;

(iv) that lists of persons interested in adopting a child or taking a child under guardianship are being maintained by the organisation regularly;

(v) that the accounts of the organisation are being maintained and audited annually without delay and that the auditor's reports confirm that the accounts are fair and accurate; that any organisation which is in receipt of foreign funding is duly registered with the Ministry of Home Affairs and has otherwise complied with the provisions of the Foreign Contributions (Regulations) Act, 1974;

(vi) that the organisation is receiving regular progress reports about the well-being of children given in adoption;

(vii) that qualified staff having social work experience are employed by the agency|organisation to take care of the children or they have access to such staff.

Monitoring of Performance

3.5 The State Government shall all for information and data every quarter from all agencies engaged in adoption in order to monitor the functioning of these agencies. The data shall be called for in a proforma to be prescribed by the Central Adoption Resource Agency.

3.6 The State Government shall take all such measure as are deemed necessary to actively encourage in-country adoption of children in preference to inter-country adoption. Special care|efforts shall be made for rehabilitation of children in orphanages through placement by adoption.

CHAPTER IV

ROLE OF RECOGNISED INDIAN AGENCIES FOR ADOPTION

Listing with authorities

4.1 Every institution and child welfare agency engaged in care and custody of children or in adoption work or any other activity related to orphan, abandoned, destitute, neglected or relinquished children shall immediately be listed by the concerned State Government and such list shall be forwarded to CARA.

Only Recognised Agencies could undertake Adoption

- 4.2(i) No agency shall engage in placement of or promotion of in-country adoption unless it is recognised by the State Government and in case of agency engaged in placement work, it should be a child welfare agency. Any Indian agency desirous of undertaking inter-country adoption work shall apply for recognition to the Central Adoption Resource Agency, the State Government concerned and only such agencies as are recognised by the Central Adoption Resource Agency, shall be entitled to undertake inter-country adoption work. Such agencies shall be termed

"recognised placement agencies", of adoption. The agencies which are not doing placement work but are involved in promotional work of Indian adoption shall also be recognised by CARA.

- (ii) No agencies except those recognised by the State Government concerned shall engage in in-country adoption. Rules and guidelines for this purpose may be formulated by the State Government.

EMPHASIS ON CHILD WELFARE

4.3 Only such voluntary agencies as are primarily engaged in child welfare programmes for the growth and development of children and which undertake adoption as a part of their total activities may apply for recognition for inter-country adoption to the Central Adoption Resource Agency.

LIST OF PROSPECTIVE ADOPTIVE PARENTS

4.4 Every social child welfare organisation recognised for placement work in adoption shall regularly maintain a list of all prospective adoptive parents containing their names, addresses and data on the basis of which they have approached the organisation for taking a child in adoption and other relevant details.

PRIORITY TO IN-COUNTRY ADOPTION

4.5 When a recognised Indian agency receives a child its first responsibility is to trace the biological parents and restore the child to them failing which as far as possible to place the child in adoption with Indian families. It would be desirable that an Indian recognised placement agency should place annually more than 50 per cent of the total number of children given in adoption with Indian families. However, the handicapped children, children above 6 years of age and siblings will be excluded from this calculation. The placement agencies are required to adhere the following order of priority while considering the adoption of Indian children :

1. Indian families in India.
2. Indian families abroad
3. One parent of Indian origin abroad.
4. Totally foreign.

Every recognised placement agency shall also give full details of the child to the prospective adoptive parents except the names and addresses of the biological parents, where known to the agency. It is only when all efforts to place the child within the country fail then the child would be cleared for inter-country adoption. These efforts should include contacting the VCA within the area of operation. A clearance certificate should be taken from VCA in this regard. Such clearance certificate shall be given by VCA. If within 60 days from the date the application to VCA, VCA is unable to send suitable Indian parents who are willing to take the child in adoption, intimation of making of the application to VCA shall be given to the Central Adoption Resource Agency forthwith. The Central Adoption Resource Agency will prepare a uniform proforma for clearance certificate to be issued by all voluntary coordinating agencies.

4.6 Adoption of Indian children placed with Indian living abroad will be treated as in-country placement. However, such Indian would have to follow the same procedure of sending their applications, documents etc. through an enlisted foreign agency in that country as in the case of inter-country adoption.

RECORD OF PROMOTION EFFORTS

4.7 Every recognised agency shall keep a complete record in chronological order of the efforts made by it for locating an Indian parent for the adoption of a child and shall specifically note the reasons for any case of non-placement of a child in in-country adoption with any particulars of Indian parents.

1464GI/95-5

CASE HISTORY

4.8 Every recognised Indian placement agency shall maintain a separate file for each child with the child's complete case history.

QUARTERLY DATA TO BE FURNISHED TO AUTHORITIES

4.9 Every recognised Indian placement agency shall furnish quarterly data to the Government of the State in which the agency is operating and a quarterly statement to the Central Adoption Resource Agency, in such proforma as may be prescribed by Central Adoption Resource Agency in respect of children given to Indians and others for adoption from time to time.

INTAKE OF CHILDREN

4.10 All children admitted by a recognised agency should be entered in the admission register with all the available information in the format prescribed by the Central Adoption Resource Agency.

4.11 In the case of an abandoned child not received through Juvenile Welfare Board/Juvenile Court as the case may be or through direct relinquishment by biological parents, a first information report (FIR) should be filed by the concerned agency in the local police station within 24 hours of arrival of the child at the recognised agency's children's home. The nearest Juvenile Welfare Board or where it does not operate, the Juvenile Court or the District Collector should also be notified within 24 hours of arrival of the child at the agency's children's home.

4.12 The recognised agency should ensure that medical examination of the child is conducted within 24 hours of its arrival and appropriate treatment given where necessary.

SURRENDER OF A CHILD

4.13 In the case of surrender of a child, the biological parents/parent should be counselled and duly informed by the agency concerned of the effect of their consent for adoption and the alternative available for the care and maintenance of the child.

4.14 The surrender document should be executed at the free will of the biological parents/parent with no compulsion, payment or compensation of any kind on the part of the agency. If the biological parents state a preference for the religious upbringing of the child, their wish should be respected as far as possible. But ultimately the interest of the child alone should be the sole guiding factor before the child is placed in adoption.

4.15 The parents/parent should be informed by the agency of his/her/their right to reclaim the child within 90 days from the date of surrender. He/She/They should be made aware that after the period of 90 days relinquishment deed will become irrevocable and the agency will be free to place the child in adoption or guardianship within or outside India.

4.16 Wherever possible the surrender document should be executed on stamped paper in the presence of two responsible witnesses whom the recognised agency should be able to produce, if necessity arises. The responsibility for the authenticity of the surrender document would be on the agency.

During the surrender process, the recognised Indian placement agency should ensure that :—

- (i) If a legitimate child is surrendered, both parents sign the relinquishment document and in case one of the parents is dead, proof of death is furnished.
- (ii) In case of a child born out of wedlock the mother herself and none else, surrenders the child.
- (iii) If the surrender is effected by any person other than the biological parents/parent, the same procedure is followed as for an abandoned child.

DESTITUTE OR ABANDONED CHILD

REPORTING

4.17 If a child is found abandoned or is picked up as a destitute then the procedure of going through the Juvenile Welfare Board/Juvenile Court or the Social Welfare Department or the Collector would have to be adopted. As soon as an abandoned or destitute child is found by a social or child welfare agency or a nursing home or hospital or the police or anyone else a report should immediately be lodged with the local police station along with a photograph of the child. The Collector of the District must be informed, who in turn must immediately inform the nearest recognised agency and VCA. The Inspector General of Police, or the Commissioner of Police, as the case may be, should instruct every police station within his jurisdiction to immediately undertake an inquiry for the purpose of ascertaining and tracing the parents of the child in respect of which the report is made and such inquiry must be completed within one month of the report being lodged with the police station. Meanwhile, the social or child welfare agency which has found the abandoned or destitute child may make an application to the Juvenile Welfare Board and where it is not functioning, then the Juvenile Court or to the Social Welfare Department or the Collector, as the case may be, for a release order declaring that the child is legally free for adoption. Since the report of the enquiry to be made by the police has to be completed within a period of one month, it should be possible for the Juvenile Court or the Social Welfare Department or the Collector to make a release order declaring the child legally free for adoption within a period of six weeks from the date of making of the application in the case of children below the age of two years and three months, in the case of children above that age.

BIRTH CERTIFICATE

4.18 Every child must have a birth certificate. For issuing a birth certificate in respect of an abandoned or destitute child, the registration of whose birth is not available the agency concerned must make an application to the local Magistrate along with any other material which the agency considers relevant in the form of an affidavit made by a responsible person belonging to the agency. The local magistrate will then pass an order approving the particulars to be entered in the birth certificate and on the basis of the magisterial order, the requisite certificate will be issued by the local birth certificate issuing authority of the city/town/area where the child has been found. The Chief Medical Officer of the area. The Magistrate would ordinarily act on the certificate granted by the Chief Medical Officer. This process would be initiated only after the adoption is finalised, so that the particulars of the adoptive parents are available for inclusion in the certificate. In case the child has attained the age of three, and the adoption has still not been finalised, the agency may obtain a birth certificate, if it is found necessary, after informing the court in the form of an affidavit:—

- (a) that to the best of its knowledge the child has attained the age of three years;
- (b) that his/her adoption has not been finalised and is likely to take some time or may never be finalised in all probability;
- (c) that a certificate is required for educational/medical/legal purposes or any other reasonable purpose which may be specified; and
- (d) that person/persons would stand in as local parents to the child (this person/these persons should be a responsible person/responsible persons belonging to the placement agency) till such time as he/she attains majority, or is adopted, whichever is earlier.

In such cases a second birth certificate may be issued after adoption to provide for a change in the name/names of the child and the adoptive parent/parents after obtaining an order to that effect from the court which had passed order for issuing the original birth certificate.

4.19 A quarterly statement on child available for guardianship/adoption in the format prescribed by CARA should be furnished to the appropriate authority in the State Government/U.T. Administration and CARA and every month to the VCA concerned.

PROCEDURE FOR ADOPTION

4.20 No child should be offered for adoption :

- (a) In the case of abandoned children until the Juvenile Welfare Board/Juvenile Court, the Collector or the District Magistrate or the Department of Social Welfare declares the child legally free for placement.
- (b) In the case of surrendered children, till the three months period for reconsideration by the parent is over.
- (c) In the case of a child who can understand and express without his/her consent.

ROLE OF THE PLACEMENT AGENCIES

4.21 In the case of surrendered children, after 3 months time for reconsideration, the placement agencies should make all efforts within 45 days to place the child with Indian parents in the country. But in case of destitute or abandoned child, the placement agency after getting a releasing order declaring the child legally free for adoption from the competent authority, should make all the efforts to place the child within the country within a period not exceeding seven weeks from the date of releasing order which include one week time for reconsideration of the biological parents, if traced.

4.22 If the Recognised Placement Agency is not able to find a suitable Indian family within the country, it will give all the details of the child to the voluntary coordinating agency wherever it exists. The information must include details of admission, medical history, legal status, photograph and efforts made to find families in the country. The officers of the VCA shall be permitted to visit and see the child, as and when necessary.

4.23 Where there is a VCA maintaining a register of children available for adoption as also a register of Indian adoptive parents who want to take a child in adoption, VCA will immediately contact the Indian family which is on its register as prospective adoptive parents and inform them that a particular child is available for adoption. If, within a period of two months, the child is not taken in adoption by an Indian family, it should be regarded as available for inter-country adoption. The possibility of inter-State adoption in India and inter VCA coordination should also be exhausted before a child is offered for inter-country adoption. The first priority in inter-country adoption should be given to Indians residing abroad and, if no such Indian family is available, then to adoptive couples where at least one parent is of Indian origin. However, the children placed with parents or one of the parents having Indian origin would be considered as given in in-country adoption.

4.24 It is only where a VCA does not exist or no Indian family comes forward to take a child in adoption within a maximum period of two months, that the child should be regarded as available for inter-country adoption. However, if the child is handicapped or is a sibling or above 6 years of age, the procedure of obtaining VCA clearance need not be followed and the child should be regarded as available for inter-country adoption without the waiting period of two months. In other cases also, if the child is in bad state of health, needing urgent medical attention which it is not possible for the social or child welfare agency looking after the child to provide within the country the agency need not wait for the period of two months but after obtaining a medical certificate from a medical specialist in a Government hospital stating the need for urgent treatment and also that the child will be able to withstand the journey, get VCA clearance and process the case for inter-country adoption. However, in the case of surrendered children, the

three months time for reconsideration should always be adhered to.

4.25 A child should be offered in inter-country adoption by a recognised Indian agency only on receipt of a no objection certificate from the VCA except in the cases mentioned in paragraphs 4.5 and 4.24 above. If it has not been possible to find suitable Indian parents for taking a child in adoption within the period of two months specified in paragraph 4.23 VCA shall issue a no-objection certificate.

4.26 In completing formalities for adoption guardianship all the procedures as laid down by Central Government/CARA should be followed.

Documentary proof of age, marriage, income, health, property and savings of prospective parents, letter of acceptance accepting a particular child alongwith countersigned child study report, medical report and photograph of the prospective parents/agency consent and power of Attorney in the name of the functionary of the Indian Agency, should be taken. A Home study report prepared by or under the supervision of a professionally trained social worker should be taken into account. Photographs of prospective parents should also be kept on record.

4.27 Pending completion of formal adoption/guardianship proceedings, the child may be placed with prospective adoptive parents in foster care in the case of Indian parents living in India.

PLACEMENT OF HANDICAPPED CHILDREN

4.28 The placement of handicapped children and children with deficiencies may be considered as a plus point in evaluating the performance.

TRANSFER OF CHILDREN

4.29 All children transferred to the recognised placement agency (recognised by Government of India) from an unrecognised agency, whether within the State or from outside, should be in the physical custody of the recognised agency for a period of not less than one month before any action for the placement of the child abroad is taken.

4.30 Transfer of the child should be accompanied by available documents pertaining to its admission, preliminary case history, documentary evidence to prove that the child is legally free for adoption, and a letter of transfer. The recognised placement agency should verify all the facts before accepting the child, as they are legally responsible for the placement.

4.31 Attempts to find adoptive parents for children who are legally free for placement may be made by the child welfare agency which has first received the child, either directly or through an unrecognised agency or through the VCA.

4.32 In the case of inter-state transfer of children, children may be transferred by the recognised Indian agency to any of its designated branches, provided that it is done with the written consent and permission of the Social Welfare Department/Magistrate/Collector, as is relevant to the case. The nearest VCA should also be informed.

FOLLOW-UP

4.33 The follow-up of children placed within the country will be as follows:

- (i) If any pre-placement foster care is effected, there should be regular monitoring and evaluation of the foster care. A professionally trained social worker should visit the family regularly.
- (ii) The follow-up format should be completed and forwarded by the recognised placement agency concerned every six months to VCA, the State Government and the Central Adoption Resource Agency.

(iii) The agency should see that legal adoption is effected at the earliest, thereby safeguarding the interest of the child.

(iv) Even after legal adoption, the agency should keep in touch with the family for a period of three years.

(v) Post-adoptive counselling should be provided by the agency to the adoptive parents.

RECORDS

4.34 The following records and registers should be maintained by every recognised Indian placement agency.

- (i) Admission register.
- (ii) A separate file on each child in the prescribed format, giving full details/history. Relevant, legal documents of every adoption and child's background/history should be maintained atleast for a period of 18 years for future reference.
- (iii) Register of prospective adoptive parents with details.
- (iv) Register of children showing their arrival, departure, admittance into hospitals, return to their parents and death, if any.
- (v) Follow-up register of children placed with adoptive family prior to legal placement and after legal placement.
- (vi) Quarterly reports in the prescribed format as forwarded to the State Government, Central Adoption Resource Agency and VCA.
- (vii) The annual report of the organisation together with the necessary details and statistics in the prescribed format as forwarded to the State Government, the Central Adoption Resource Agency and VCA.
- (viii) Audited statement of accounts, together with a copy of FCRA account submitted to the Home Ministry, as forwarded to the State Government and CARA.
- (ix) Other records stipulated under the Societies Registration Act, 1860 or the relevant State Law relating to public trusts.

RECOVERY OF COSTS

4.35 The organisation shall pursue only non-profit objectives. Under no circumstances should be derive improper financial gain from any activity related to inter-country or in-country adoption. It may, however, receive reimbursement or other payment for direct or indirect costs and actual expenses.

4.36 For in-country adoption, the following charges may be recovered by the agency from the adoptive parents, if the agency deems it necessary:—

- (i) Maintenance cost as fixed by the Court from time to time, from the date the child has been approved and accepted by the Indian parent/parents to the date of departure from the institution.
- (ii) Such out of pocket cost, administrative cost and service charges for preparation of child study, medical and IQ reports, legal expenses and conveyance etc., as may be fixed by the court from time to time.

4.37 The maximum amount to be charged by any agency from Indian parents as reimbursement of maintenance expenses shall be fixed by the court.

4.38 For inter-country adoption the following costs may be recovered by the agency from the foreign adoptive parents:

- (i) Cost of any surgical or medical treatment of the child against production of bills or vouchers duly certified.
- (ii) The Indian placement agency processing the application of a foreigner for being appointed guardian of a child with a view to its eventual adoption, should be entitled to recover from the foreigner, cost incurred in preparing and filing the application and processing it in court including legal expenses, administrative expenses, preparation of child study report, preparation of medical and I.Q. reports, passport and visa expenses, and conveyance expenses and that such expenses may be fixed by the court at a figure not exceeding Rs. 6,000. Any increase in maximum recoverable expenses in this regard would be done only with the approval of the Supreme Court of India. In so far as the maintenance or medical expenses incurred by the recognised placement agencies running homes for children is concerned, they are entitled to receive reimbursement of such maintenance or medical expenses from the foreigner taking the child in adoption at a figure not more than Rs. 78 per day per child from the date of selection of the child by the adoptive parents until the child is taken by the adoptive parents after they are appointed as guardians. This outer limit of recoverable expenses may be reviewed by the Ministry of Welfare, Government of India once in three years depending on escalation of the expenses including cost of living.
- (iii) Cost of travel of the child from India to the receiving country and the cost of an escort, if the foreign recognised agency is unable to provide the escort.
- (iv) In case of disruption or failure of adoption, the cost of repatriating the child to India, if no alternative placement for the child is effected in the foreigner's country by the recognised foreign agency with the concurrence of the Indian agency.
- (v) If it comes to CARA's notice that any recognised Indian agency charges more fees than the prescribed fees or tries to exploit financially the foreign enlisted agency, CARA may after giving an opportunity to such agency to explain its point of view, suspend or revoke its recognition. Similarly, if any foreign enlisted agency induces an Indian recognised agency by giving or offers more money than the prescribed fees for processing a case of inter-country adoption of an Indian child, CARA may after giving an opportunity to such agency to explain its point of view de-enlist the foreign agency.

CHAPTER V

RECOGNITION OF INDIAN AGENCIES FOR ADOPTION

Proforma for application

5.1 Any Indian social/child welfare agency desirous of obtaining recognition from the Government of India for undertaking intercountry adoption work shall submit an application in the prescribed form to the CARA through the Department dealing with Social Welfare/Women & Child Development in the State in which the agency is located.

UN-RECOGNISED AGENCIES BARRED

5.2 No agency which does not hold a certificate of recognition from the CARA shall give a child to foreign parents for the purpose of adoption nor submit an application to an Indian court under the Guardians and Wards Act, 1980, for declaring a foreigner as a guardian of an Indian child.

RECOGNITION FOR SPECIFIED PERIOD

5.3 Recognition to an Indian agency shall be granted initially for a period of three years, subject to the conditions laid down in these guidelines.

CONDITIONS FOR RECOGNITION

5.4 Any Indian agency which seeks recognition shall generally fulfil the following conditions :

- (a) It shall be a society registered under the Societies Registration Act, 1860 or a Trust created under the Charitable Trust Act, or an organisation registered under an appropriate law or an organisation which has worked for the welfare of children during the preceding five years ;
- (b) The organisation shall be duly licensed by the State Government under the provisions either of the Women and Children Institutions (Licensing) Act, 1956 or the Orphanages or Charitable Institutions (Supervision and Control) Act, 1960.
- (c) It shall have a duly constituted Executive Committee ; the Chief Executive of the organisation as well as the majority of members of the Board/ Executive Committee should be Indian Citizens ;
- (d) It should have appropriate children's home for the protection and up keep of children including infants ;
- (e) It should be able to raise funds through donations or Government grants ;
- (f) It should be running on a non-commercial, non-profitable basis ;
- (g) It should have atleast one qualified Social Worker on its staff to carry out the adoption work ;
- (h) The Chief Executive of the organisation should be willing to sign a written undertaking to follow the guidelines laid down by the Supreme Court of India and those prescribed, from time to time, by the Government of India and the Regulations if any, made by CARA.
- (i) Recognition of the agency should be recommended by the State Government concerned. Or, if it is not so recommended, the reason for the refusal should be given. CARA may accept or reject the reasons for refusal. The decision of CARA shall be final.

RENEWAL OF RECOGNITION

5.5 The original application should be sent to the appropriate authority of the State Government and a copy of it should simultaneously be forwarded directly to CARA. The State Government will forward the original application to CARA alongwith its views within a period of two months from the date of receipt of the application. If the State Government does not send the application to CARA with its views within a period of two months from the date of receipt of the application the concurrence of the State Government will be presumed by CARA and the application will be processed by CARA for grant of recognition within a maximum further period of two months. If there is no response from CARA to the application within such further maximum period of two months, or before the expiry of the recognition of the agency, whichever is later, the renewal shall be deemed to have been granted for a period of two years. Recognition would normally be renewable for a period of three years at a time subject to the following conditions :—

- (i) Satisfactory performance in in-country adoption. The Licensing Authority should ensure that the agencies should abundantly exhibit their involvement in the area of Indian adoption. Therefore, it shall be obligatory on the part of every recognised placement agency to make atleast 25 per cent placement of children in Indian families out of the total placements effected by it by way of adoption/guardianship in the first year of its recognition. This level of in-country adoption/guardianship shall be raised to 50 per cent by the third year of its recognition. The recognition is liable to be suspended or revoked in cases where the recognised agency fails to arrange in-country adoptions upto the figures stipulated above. However, an opportunity would be given to the placement agency to show cause against such

suspension or revocation, as the case may be and such suspension or revocation shall be made by a written order giving reasons for such suspension or revocation.

- (ii) Regular submission of reports and return.
- (iii) No instance of proved malpractice against the placement agency.
- (iv) Recommendation of the concerned State Government provided that the refusal to recommend is not based on any inadequate, irrelevant or unacceptable reasons.

AGENCIES TO MAINTAIN ACCOUNTS

- 5.7 (i) Every agency shall maintain proper accounts to be audited by a Chartered Accountant every year.
- (ii) A photostate copy of audited accounts together with audit report shall be furnished by every agency within one month from the date accounts have been audited by the Chartered Accountant, to the Social Welfare Department of the State Government concerned and to the CARA.
- (iii) A photostat copy of the FCRA accounts submitted to the Home Ministry should be furnished to CARA together with the audited accounts, by the agency.

APPLICATION TO BE PROCESSED ONLY BY RECOGNISED AGENCIES

5.8 An application for declaring a foreigner or an Indian to be the guardian of an Indian child as a prelude to adoption in a foreign country shall be processed only by a recognised Indian agency after following the procedure set out in these Guidelines.

APPLICATION TO BE SPONSORED BY ENLISTED FOREIGN AGENCIES

5.9 A recognised Indian agency may submit an application of a foreign adoptive parent to an Indian court for awarding the guardianship of an Indian child to a foreigner provided the application of such foreigner has been forwarded by a foreign voluntary agency enlisted by the Government of India and the application is made in accordance with these guidelines. However, if there is an agency owned or operated by the Government in a foreign country, the foreign adoptive parents can approach a recognised Indian agency in India through such agency operated or owned by the foreign Government.

INDIAN AGENCIES RECOGNISED TO DEAL WITH ENLISTED AGENCIES ABROAD

5.10 No recognised Indian agency shall entertain any application directly for adoption of an Indian child from a foreigner or sponsored by a foreign enlisted agency unless the prescribed documents alongwith the application are cleared by CARA.

INSPECTION OF AGENCIES

5.11 The premises of the recognised Indian agencies including their children homes, and their records shall open to inspection by officials of the CARA and/or official of the State Government at any time.

CHAPTER VI

ROLE OF ENLISTED FOREIGN AGENCIES FOR ADOPTION

FOREIGN AGENCIES TO APPLY TO INDIA'S DIPLOMATIC MISSIONS

6.1 A foreign social/child welfare agency desirous of sponsoring applications of foreign adoptive parents for adopting an Indian child shall make an application for enlistment with CARA in the office of India's Diplomatic Mission in that country and only such foreign agencies enlisted for this purpose by CARA shall undertake this activity.

CRITERIA FOR ENLISTMENT OF FOREIGN AGENCIES

6.2 The criteria for enlistment of foreign agencies by CARA for the purpose of inter-country adoption are as under :—

- (i) It shall be either a part of the Government of the country or a duly registered voluntary agency registered under the relevant law of the concerned country and should be recognised by the appropriate authority of that country.
- (ii) It shall be a child welfare agency having an established standing in this field and it must be staffed with qualified social workers who have experience in the field of adoption.
- (iii) The agency in question shall be run on non-commercial and non-profitable basis. The foreign agency should be asked to submit a report and audited statement of accounts of their operations in India.
- (iv) An undertaking by the enlisted foreign agency that in case of disruption of the foreigner's family before adoption is effected or in case the child is not properly looked after or is mal-treated or abused in the adoptive family, it will take care of the child under intimation to the Indian Diplomatic Mission, the Central Adoption Resource Agency, Ministry of Welfare and the concerned Indian recognised placement agency and try to find suitable alternative placement for the child with the concurrence of the recognised placement agency which processed the case and report such alternative placement to the Indian Court which made the order for guardianship and also to CARA.
- (v) The Head/Chief Executive of the Organisation should be willing to sign a written undertaking to follow the guidelines laid down by the CARA for observance by the enlisted foreign agencies. The enlisted foreign agencies should send to CARA a list of the Indian agencies with whom they have contacts and working relations or with whom they prepare to have working relations or with whom they prepare to have working relationship.

PROCEDURE FOR ENLISTMENT :

- 6.3 (i) A foreign social/child welfare agency desirous of sponsoring applications of foreign adoptive parents for adopting Indian Children shall apply for enlistment by CARA, through the office of India's Diplomatic Mission and the Government of the country where it is located.
- (ii) On the recommendation of India's Diplomatic Mission in the country concerned, CARA shall examine the application and consider the agency concerned for recognition provided it fulfils the criteria stated in paragraph 6.2 above.

RENEWAL OF ENLISTMENT :

- 6.4 (i) A foreign agency engaged in inter-country adoption would be enlisted by CARA initially for a period of five years. Enlistment would be renewable for five years at a time in case of satisfactory performance subject to conditions laid down in these guidelines.
- (ii) CARA will take the following factors into consideration while granting renewal of enlistment provided an application for renewal is received through the proper channel atleast six months before the expiry of the previous recognition.
 - (a) Whether the agency is still recognised by the appropriate authority of the country in which it is based.
 - (b) Whether the agency has been regular in the submission of progress reports of the children placed by them in adoption.

(c) Whether the general performance of the agency is satisfactory and whether the children placed by them are making satisfactory progress.

(d) Whether Government of India's Diplomatic Mission in the country concerned has recommended the case for renewal.

Renewal of enlistment may, however, be denied at the discretion of CARA for valid or legitimate reasons but CARA shall not be bound to disclose such reasons.

DE-ENLISTMENT :

6.5 The Central Adoption Resource Agency, Ministry of Welfare, Government of India, may at any time de-enlist any enlisted foreign agency for adoption for valid or legitimate reasons shall not be bound to disclose the same. However, it at the time of de-enlistment there is any case under process that would be allowed to be completed.

6.6 When the Court makes an order appointing adoptive parents as the guardians of the child, the order shall contain an undertaking of the adoptive parents that they shall protect and safeguard the best interests of the child and that the child would be legally adopted in the receiving State not later than two years from the date of the order and that on such adoption in the receiving State, subject to the laws of the country the child would have all the rights of a natural born child.

RIGHTS OF THE CHILD TAKEN ABROAD

6.7 On adoption of the child by the foreign parent according to the law of his/her country, it is presumed that subject to the laws of the land the child would acquire the same status as a natural born child within wedlock with the same rights of inheritance and succession and the same nationality as the foreign parent adopting the child.

6.8 Where the child is not legally adopted by the adoptive parents in the receiving State within two years from the date of order of the Court in India appointing the adoptive parents as guardians either on account of disruption in the family or on account of the adoptive parents failing to get adjusted to the behaviour of the child or otherwise, the foreign agency which has processed the adoption of the child in the receiving State should immediately withdraw the child from the adoptive parents and keep the child in its custody and care and find out new adoptive parents for placement of the child in adoption as soon as possible. The foreign agency shall give an undertaking to this effect to the Court processing the case in India.

6.9 All enlisted foreign agencies shall send a copy of their annual report to CARA every year.

6.10 The foreign agency shall with reference to every child placed by it send follow-up reports through India's Diplomatic Mission abroad with photographs of the child on a quarterly basis for the first two years and on a half-yearly basis for the next three years to CARA and to the Court that awarded the guardianship in India and to the Indian placement agency concerned. The foreign enlisted agency shall send a photoalbum of the children alongwith their adoptive parents to CARA once in a year.

6.11 The enlisted foreign agency will forward a copy of the legal adoption order of the appropriate authority in that country as soon as it is made to the Central Adoption Resource Agency, the Court which awarded the guardianship and to the Indian agency concerned.

6.12 Even after the adoption is legalised, the enlisted foreign agency should maintain contact with the adoptive family in keeping with the need of privacy of the adoptive family and provide support and counselling services, if necessary and safeguard the interest of the child till such time as he/she attains majority.

6.13 The enlisted foreign agency should help the Indian Diplomatic Mission in its country to arrange get-togethers of adopted children of Indian original and their adoptive

families for exposing them to the culture of India. These get-togethers may be organised at the time of national occasions like 15th August, 14th November, 2nd October and 26th January etc. CARA may on some occasions participate in these get-togethers in order to know the feed back on progress of the adopted child.

6.14 The enlisted foreign agencies cannot employ their representatives in India for any kind of activities relating to inter-country adoption.

CHAPTER VII

VOLUNTARY COORDINATING AGENCIES (VCA)

7.1 There shall be a centralised agency namely voluntary coordinating agency (VCA) in the State or even in a large city where there are several recognised placement and child welfare agencies. The principal functions of VCA shall be as follows :—

- (a) It shall actively promote Indian adoption and formulate, develop and execute programmes and activities for generating awareness in this regard;
- (b) It shall ensure that the priority laid down by the Supreme Court on placement/adoption within the country or with India abroad is adhered to. All recognised social/child welfare agencies, Juvenile Welfare Boards and Government homes within the country, desirous of placing children in adoption/ placement shall furnish lists of children legally free for adoption to the concerned VCA and also to CARA.
- (c) It shall maintain a register of all prospective adoptive parents;
- (d) It shall maintain a register of all available children who are legally free for adoption;
- (e) It shall coordinate the work of all its member agencies and other child welfare institutions in the field of Indian adoption. Where Indian adoption is difficult within its area of operation it shall coordinate with other VCAs in the State and in the country;
- (f) Where Indian placement is not materialised, it shall issue a no objection certificate within a period of two months from the date of receipt of application for 'No objection' in the VCAs to the recognised placement agency so as to enable the child to be placed in inter-country adoption;
- (g) In the case of a child requiring immediate medical or surgical assistance, the VCA may waive the stipulated waiting period on production of medical certificate as provided in paragraph 4.24 above and issue a no-objection certificate at the earliest.
- (h) It shall call a meeting of member agencies at least once every quarter;
- (i) In cases where these guidelines are not being followed by any recognised placement agency, the concerned VCA will bring it to the notice of CARA with substantive evidence for taking appropriate action.

7.2 The VCA shall be registered under the Societies Registration Act and will comply with all the rules laid down under the Act and also these guidelines.

7.3 Every VCA shall have, on its staff, at least two professionally trained social workers.

7.4 Every VCA shall have to seek recognition from CARA by means of an application which shall be routed through the State Government and the State Government shall offer its comments on such application within a period of 30 days from the date of receipt of such application and if no such comments are forthcoming within the period of 30 days, it shall be presumed that the State Government has no

objection.

7.5 All the recognised placement agencies (whether doing only in-country and inter-country adoptions) would be entitled to become members of the VCA and those child welfare agencies which are not placing children in adoption but are merely running homes for children etc. would also be eligible to be members of VCA. The final decision in case of the later would rest with the executive committee of the VCA. If any agency is de-recognised by CARA on account of malpractice of any other valid reason or any child welfare agency de-licensed by the State Government, then it shall cease to be a member of VCA and it shall not be eligible for membership of VCA unless it is once again recognised on licensed.

7.6 The recognised placement agencies would have the right to vote for electing the executive committee of the VCA. The child welfare agencies would not enjoy any voting right. The VCA should be an independent registered body with a democratic structure. The Chairman should not be connected with either in-country or inter-country placements.

STRUCTURE OF VCA

7.7 There shall be an executive committee for managing the day to day affairs of VCA. The executive committee shall consist of not less than 3 members and not more than one third the number of members of the VCA.

EXECUTIVE COMMITTEE OF VCA

7.8 The executive committee of VCA shall comprise :

- (a) The Chairman of VCA.
- (b) A representative of the State Government of the level of the Deputy Director (Welfare)/Social Welfare or above.
- (c) One Senior representative of each scrutinising agency working in the jurisdiction of the concerned VCA.
- (d) One representative from the agencies exclusively doing Indian adoption.
- (e) Three representatives of the recognised placement agencies out of these at least two shall be from those placement agencies which have placed at least 50 per cent children within the country during last three years to be elected by the recognised placement agencies which are members of VCA. The terms of office of the members of the executive committee of items (c) and (d) shall be two years and they shall not be eligible for re-appointment for the next succeeding period of 2 years.

The executive committee of VCA may appoint staff to carry out the day-to-day functions of the VCA. Such paid staff would be accountable to the executive committee.

7.9 The no-objection certificate issued by the VCA would be signed and issued by two persons—the Chairperson and Member-Secretary, both of whom will not be connected with adoption activities whether in-country or inter-country. No recognised placement agency shall process the application for inter-country adoption before obtaining the no-objection certificate save in the case of exceptional and/or exempted categories referred to above at these guidelines.

THE FOLLOWING ARE THE BROAD PROCEDURE TO BE FOLLOWED BY THE VCA

7.10 (a) All member agencies must submit a list of children and prospective adoptive parents on a monthly basis to the VCA.

(b) When an agency wishes to place a child in foreign adoption it must check with the VCA to ascertain whether there is any Indian parent willing to take the child in adoption.

(c) The period of 30 days provided for in the Supreme Court Judgement for trying to place a child with Indian parents has been found to be inadequate and this should be extended to 60 days from the date when VCA assistance is sought to locate an Indian family. This procedure may be adopted during the period of 5 weeks within which CARA is required to give a final clearance.

(d) The time frame for VCA to find a placement in India will be 60 days as provided in clause (c) above and only after that, an inter-country placement may be processed.

(e) If there is difference between the placement agency and VCA in regard to the clearance of a child for inter-country adoption, the placement agency concerned may refer the cases to CARA. In such cases, CARA will decide whether to give the clearance of the child or not. The decision of CARA shall be final.

Criteria for Recognition

7.11 In order to be recognised as VCA, an agency must fulfil the following criteria :—

- (i) It should be a society registered under the Societies Registration Act, 1860.
- (ii) The agency must be recommended by the State Government concerned for recognition by CARA.
- (iii) The agency should run on a non-commercial and non-profitable basis.
- (iv) Its office-bearers at item (d) and (e) in paragraph 7.8 shall be from recognised placement agencies which have given children in in-country adoption to the extent of 50% or more of the total number of children given in the adoption in a year after excluding handicapped children, siblings and children above 6 years of age.
- (v) All the office bearers should be Indian nationals. The initial recognition of VCA shall be for a period of 3 years.

Renewal of Recognition

7.12 A VCA which seeks renewal of recognition should apply to CARA through the State Government for renewal of recognition six months prior to the date of expiry of the previous recognition. The following would be the main criteria for renewal of recognition.

- (i) Satisfactory performance in the promotion of in-country adoptions.
- (ii) Timely submission of reports and returns as may be specified by CARA.

Withdrawal of Recognition

7.13 Recognition of a VCA may be withdrawn by CARA on receipt of a report from the State Government regarding unsatisfactory performance, after giving the VCA an opportunity to explain its position. The VCAs should play positive role in bringing greater coordination among all the placement agencies working in the area of their operation. Any malpractice, if proved, would immediately invite action in the shape of de-recognition. Delay and non-compliance in the submission of reports/returns asked for by the State Government or CARA may also be a ground for withdrawal of recognition.

7.14 VCA should conduct the quarterly meetings attended by all the members entitled and eligible to attend the meetings and discuss all matters relating to adoption. The minutes of the meetings should be sent to CARA by the concerned VCA.

Finance of VCA

7.15 The Government of India in the Ministry of Welfare would give grant-in-aid to VCA upto 90% of the cost as per prescribed norms.

Existing VCAs

7.16 The existing VCAs shall stand superseded as soon as VCAs are constituted in accordance with these guidelines for the area of operation of the existing VCAs.

7.17 If in any area there is only one recognised placement agency, it shall be entitled to become a member of VCA operating in the most adjacent area.

CHAPTER VIII

Scrutinising Agency

8.1 It is open to the Court looking into the matter of appointment of guardian under the Guardians and Wards Act, 1890 in exercise of its powers under Section 11 to appoint any independent, reputed Social or Child Welfare Agency, as a Scrutiny Agency for scrutinising an application from prospective adoptive parents for adoption of a child. The agency must be a body of experts in the field of Child Care and Welfare, not itself involved in any manner in the placement of children in adoption. At present there are two scrutinising agencies, namely, Indian Council for Social Welfare and Indian Council of Child Welfare being appointed by the Court. The Court may be requested to appoint any other eligible child or social welfare agency as scrutinising agency which preferably meets the eligibility criteria as laid down by CARA.

Procedure for Recognition

8.2 CARA shall maintain a panel of agencies which according to it can satisfactorily perform the functions of a scrutinising agency. The procedure to be adopted for recognition of an agency as scrutinising agency other than Indian Council for Child Welfare (ICCW) and Indian Council of Social Welfare (ICSW) will be as follows :—

- (i) The agency should apply to CARA for recognition as a scrutinising agency.
- (ii) The agency should fulfil all the criteria laid down by CARA for recognition as scrutinising agency.
- (iii) CARA may seek such information as may be necessary from the scrutinising agency regarding its bonafides and performance on the basis of such report issue a recognition certificate.
- (iv) A scrutinising agency would be recognised initially for a period of three years, renewable as per the procedure given in these guidelines.

Criteria for Recognition

- 8.3 (i) The agency should be an independent, reputed social child welfare agency.
- (ii) The agency must be a body of experts in the field of child care and welfare.
- (iii) The agency should not be involved in the placement of children in adoption.
- (iv) It should be a society registered under the Societies Registration Act, 1860.

(v) All the office bearers should be Indian nationals.

(vi) The agency should run on a non commercial and non-profitable basis.

Renewal of Recognition

8.3 (i) Every recognised scrutinising agency should apply for renewal of recognition, 6 months prior to the date of expiry of the previous recognition. If the performance of the scrutinising agency has been found satisfactory and there are no adverse reports from any court or the State Government concerned and also if any reports or returns asked for by CARA are submitted by it regularly without delay, recognition may be renewed from time to time but each time only for a period of 3 years.

Saving Clause

8.4 Any scrutinising agency may be de-recognised by CARA at any time following reports of malpractices from any State Government or any Court, after giving the agency an opportunity to place its case before CARA.

Functioning of Scrutinising Agency

8.5 It shall be incumbent upon every scrutinising agency to perform the following functions :—

- (1) To scrutinise the following documents :
 - (i) Application for guardianship/adoption made on behalf of the prospective adoptive foreign parents.
 - (ii) Home study report.
 - (iii) Child study report.
 - (iv) Any other documents/certificates attached with the application.
- (2) To ensure that the application or copy of the application, as the case may be, has been duly forwarded by a foreign agency to CARA.
- (3) To ensure that before a child is placed in guardianship with a foreign adoptive parents, a no-objection certificate has been obtained from the concerned VCA.
- (4) To satisfy itself that the child in question is legally free for adoption.
- (5) To see the child in person and to check that the information given to prospective, adoptive parents regarding the child is correct. In case of any change in the medical/physical status of the child, the scrutinising agency should ensure that the information of the change is given to the prospective adoptive parents and their consent obtained before a final order is passed by the court concerned.
- (6) To satisfy itself that the prospective adoptive parents/guardians are fit persons for adopting the child in question.
- (7) To ensure that the adoption would be in the best interest of the child.
- (8) To assist the court in ascertaining whether the child has been voluntarily surrendered by the biological parents.
- (9) To ensure and satisfy itself that no one, including Indian as well as foreign agencies concerned are making any profit out of the adoption in question.
- (10) To verify, in case of older children, the child's own views regarding the adoption. This may be reported to CARA immediately.
- (11) To ascertain, as far as possible, as to what are the laws regarding adoption of foreign children in the

country of the prospective adoptive parents and there is a reasonable assurance that the child would be adopted within the minimum possible period but in any case within a period not exceeding two years.

- (12) To ensure that all the precautionary measures are taken before the handicapped, sibling, older age and other special needs children are placed to a family who are really interested in such children.

8.6 In case of any difference between Scrutiny Agency and once every six months of all the cases it has scrutinised.

8.7 In case of any difference between Scrutiny Agency and placement agency in regard to placing of a child or matching of the child with the prospective adoptive parents or any other related issues, the scrutiny agency may refer it to CARA for consideration. The decision of CARA on such cases shall be final.

Scrutinising Charges

8.8 Whenever an Indian parent makes an application for appointing himself or herself as guardians of a child or a Hindu parent applies for permission to adopt a child and, if the case is referred to it by the court, the scrutinising agency may charge such amount of expenses upto Rs. 150 as directed by the court unless a higher amount is awarded by the court.

When a foreign agency makes an application for guardianship, the scrutinising agency may charge from the Indian agency an amount as directed by the Court varying between Rs. 450 to Rs. 500, for actual expenditure incurred and the concerned Indian agency shall have the right to recover such amount from the foreign parents whose application for guardianship it has processed. This amount may exceed Rs. 500 if the court concerned specifically orders the actual incremental amount to be paid for the specific work done.

CHAPTER IX

MISCELLANEOUS

Violation of Guidelines

9.1 If it comes to the notice of any State Government or any of India's Diplomatic Missions abroad or CARA that a recognised Indian agency or enlisted foreign agency is not observing all or any of the provisions of these guidelines or is otherwise functioning in a manner which is not in the interests of children generally, it shall inform CARA immediately with details and CARA may, at its discretion suspend or withdraw recognition of such enlisted agency and/or take any other such action as may be deemed necessary.

9.2 It would be desirable for the Government of India to enter into bilateral agreement with countries which are receiving children from India for the purpose of adoption and such bilateral agreements should provide for full co-ordination between the appropriate authorities of India and the receiving State and also for protection and safeguarding of the welfare of the children taken for adoption in the receiving State.

9.3 Apprehensions have been expressed that unscrupulous elements arrange illegal transfer of babies to adoptive parents at the time of their birth in some hospitals, nursing homes, maternity homes in the country. Such transfer of babies taking place without observing the appropriate norms and procedure is illegal and thus it is not at all in the interest of the child. If any such complaints are brought to the notice of CARA, it shall cause an enquiry to be done and take up the matter with the appropriate authorities of the Central or State Government including the Medical Council of India.

Amendments to Guidelines

9.4 The Ministry of Welfare, Government of India reserves to itself the power, at its discretion to make such amend-
1464 GI/95—6.

ments, additions, deletions or alterations in these guidelines as are deemed necessary from time to time.

ANNEXURE

List of documents required from foreign adoptive parents and Social or Child Welfare Agency enlisted by Government of India for consideration of an inter country application of Indian Child

- (a) Home Study report of the foreign adoptive parents prepared by a professional worker as per Annexure "A".
- (b) Recent photographs of the adoptive family.
- (c) Marriage certificate of foreign adoptive parents.
- (d) Declaration concerning health of adoptive parents.
- (e) Certificate of medical fitness of adoptive parents duly certified by a medical Doctor.
- (f) Declaration regarding financial status of foreign adoptive parents alongwith supporting documents including employers certificate, where applicable.
- (g) Employment certificate, if applicable of foreign adoptive parents.
- (h) Income Tax Assessment order of foreign adoptive parents.
- (i) Bank references.
- (j) Particulars of the properties owned by the foreigner adoptive parents.
- (k) Declaration from foreign adoptive parents stating willingness to be appointed guardian of the child.
- (l) Undertaking from the social or child welfare enlisted agency sponsoring the foreigner to the effect that child would be legally adopted by the foreign adoptive parents according to the law of the country within a period not exceeding two years from the time of arrival of the child and as soon as the adoption is effected. Social or child welfare enlisted will send three certified copies of adoption order each to the social or child welfare agency in India through which the application for guardianship is processed for filling in the Court and one copy to Central Adoption Resources Agency, Ministry of Welfare.
- (m) Undertaking from the foreign adoptive parents that adopted child would be provided necessary education and up-bringing according to the status of adoptive parents.
- (n) Undertaking from the social and child welfare enlisted agency that report relating to progress of the child alongwith his/her recent photograph would be sent quarterly during first two years and half yearly for the next three years in the prescribed proforma through Indian's Diplomatic Missions abroad.
- (o) Power of Attorney from foreign adoptive parents in favour of officers of the social or child welfare agency in India which will be required to process the case and such Power of Attorney should authorises the Attorney to handle the cases on behalf of the foreigner in case the foreigner is not in a position to come to India.
- (p) Certificate from the enlisted social or child welfare agency sponsoring application of the foreigner to the effect that adoptive parents are permitted to adopt a child according to the law of their country.

(q) Undertaking from the social or child welfare enlisted agency to the effect that in case of disruption of the family of the foreigner before legal adoption has been affected, it will take care of the child and find a suitable alternative placement for the child with the approval of Central Adoption Resource Agency. After seeking the necessary approval from CARA it will report alternative placement to the concerned court handing guardianship proceeding in the foreign country. And such information shall be passed on by the court to the Central Adoption Resource Agency.

(r) Undertaking from the social or child welfare enlisted agency that it will reimburse all expenses to the concerned Indian Social or child welfare agency as fixed by competent court towards maintenance of the child and processing charge fees.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

(1) The home study report should broadly include information in regard to the various matters set out

in Annexure "A" though it need not strictly adhere to the requirements of the Annexure and it should also contain an assessment by the social or child welfare agency as to whether the foreigner wishing to take a child in adoption is fit and suitable and has the capacity to parent a child coming from a different racial and cultural milieu and whether the child will be able to fit into the environment of the adoptive family and the community in which it lives.

(2) All the above Certificates, declaration documents must accompany the application of the foreigner for taking a child in adoption should be duly notarised by a Notary Public whose signature should be duly attested either by an officer of the Ministry of External Affairs or Justice or Social Welfare of the country of the foreigner or by an officer of the Indian Embassy or High Commissions or Consulate in that country.

ANNEXURE "B"

PROCEDURE FOR REGULATING INTER-COUNTRY ADOPTION

Non-Resident Indians	Prospective Foreign Adoptive Parents
1	2
	To contact Foreign Enlisted Agency
	— To prepare the Home Study Report.
	— To complete all the documents.
	— To submit the documents to
Original application & documents	— Certified Copies
Indian Recognised Placement Agency	— To see whether the foreign agency is enlisted
— To register the Parents with the Agency	
— To contact concerned VCA for clearance certificate	
V.C.A.	— To see whether the Indian Placement Agency is recognised
— To explore the possibilities for the placement of the child within the country	— To examine all the document & ensure that all are in order
— Issuance of clearance certificate to placement agency	
Indian Recognised Placement Agency	
— To match of the child with the foreign prospective adoptive parents	
— To obtain the approval of the foreign adoptive parents on the proposed child	
Enlisted Foreign Agency	— Issue of No Objective Certificate to the placement agency
— Communicate the approval of the foreign adopting parents to the placement agency.	— Ensure the efforts made by the recognised placement agency in placing the child with Indian family and to that effect VCA clearance is there.
Indian Recognised Placement Agency	— Processing the case in the competent court
	Indian Court
	— To get the documents scrutinised by the the Scrutinising Agency
	— To award of the guardianship of the child in favour of the foreign prospective adoptive parents.
	Indian Recognised Placement Agency
	— To submit a copy of the court order to CARA
	— To arrange passport of the child
	— To hand over the child to prospective foreign parents or the escorts or to the representative of foreign enlisted agency.

1

2

Foreign Enlisted Agency

- | — To take the child to their dountry
- | — To hand over the child to the concerned adoptive
| parents
- | — To take up the case of the child for legal adoption
- | — To watch the progress of the child
- | — To submit a copy of the order of the legal adoption
| & progress report to CARA, concerned Indian
| recognised agency and concerned Indian Court.

Child finally gets integrated with the adoptive family

